



# भारत में बंधुआ मज़दूर

महाश्वेता देवी  
निर्मल घोष

हिन्दी अनुवाद  
आनन्दस्वरूप वर्मा



**राधाकृष्ण**

1981

©

महाश्वेता दवी  
निमल घाष

हिंदी अनुवाद

राधाकृष्ण प्रकाशन  
नई दिल्ली

प्रथम हिंदी संस्करण 1981

मूल्य

30 रुपये

प्रकाशक

राधाकृष्ण प्रकाशन  
2 अंसारी राट दरियागज  
नई दिल्ली 110002

मुद्रक

भारती प्रिंटर्स  
दिल्ली 110032

बधुआ मजदूर का मामला आज भी एकदम जीवत और सशक्त है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ देश में जब किसी परियोजना का उदघाटन किया जा रहा होता है—किसी जंगल में दश की किसी मुलायम या बठार धरती के हिस्से पर कोई अभाग परिवार चुपचाप गुलामी की जंजीर में कसता जा रहा होता है। यह राग काफी पुराना है और आज भी काफी मजबूत राग है।

किसी भी कानून जथवा अध्यादेश ने बधुआ मजदूर की मदद नहीं की। राष्ट्रीय धर्म संस्थान ने यह साबित कर दिया है कि दश में लगभग 23 लाख बधुआ मजदूर हैं। जब तक बधुआ मजदूर में चेतना नहीं पैदा होती और वे एकजुट होकर खड़े नहीं हो जाते, कोई भी उन्हें आजाद जिंदगी बिताने का हक नहीं देगा।



## क्रम

प्रस्तावना	9
भूमिका	11
अध्याय एक	41
अध्याय दो	63
अध्याय तीन	77
अध्याय चार	128
अध्याय पाँच	139
परिच्छिप्त	144



प्रस्तावना



## 10 भारत म बधुआ मजदूर

हमन इस पुस्तक का टिप्पणिया और सदर्थों स बोचल नही बनाया है । हम उनक प्रति आभार व्यक्त करते है जिनकी पुस्तक और लेखा स हमन मदद ली ।

महाश्वेता देवी  
निमल घोष

## भूमिका

अंग्रेजी द्वारा लागू की गयी भूमि वन्दोवस्त प्रथा न भारत में बघुआ मजदूर प्रणाली के लिए आधार प्रदान किया।

इससे पहले तक जमीन को जातन वाला जमीन का मालिक भी था। जमीन की मितिकयत पर राजाआ और उनके जागीरदारों का कोई दावा नहीं था। उह वही मिलता था जो उनका वाजिव हक बनता था और यह कुल उपज का एक प्रतिशत हाता था। हिन्दू राजाआ ने शासन-काल में यह हिस्सा कुल पैदावार के बारहवें हिस्से से छठे हिस्से तक घटता-बढ़ता रहा। मुगल शासन काल में यह हिस्सा बढ़कर एक तिहाई तक हा गया।

शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लखड़ाते दिना में शाही शुल्क वसूलन के लिए जिम्मेदार अधिकारी अर्थात् तहसीलदार लोग और भी ज्यादा जानामक हा गये। ये लोग एक ऐसी अद्ध मामती व्यवस्था चाहते थे जिसमें इनके पास एक जागीरदार अथवा गवनर की शक्ति और अधिकार हा और जो शहशाह के प्रति बहुत मामूली ढग से उत्तरदायी हो। उन तथाकथित राजाआ या गवनरों ने अपने नये अधिकारों को पूरी तरह जमल में गाते हुए करों की दर बढ़ा दी और इन्ने फसल का आधा भाग कर दिया। यह कमरताड भार और भी ज्यादा हा गया जब इतिहास के महत्वपूर्ण सत्रमण-काल में भारत के रगमच पर अंग्रेजों ने प्रवेश किया।

करों की वसूली के लिए जो तरीके अपनाये गये वे बेहद अमानवीय थे।

फिर भी सदिया पुराना ग्रामीण समाज तथा आदमी और जमीन के बीच का परम्परागत रिश्ता कायम रहा। अभी भी करों का भुगतान नकद के रूप में बहुत कम हाता था—यह फसल के रूप में ही होता था। कर के रूप में फसल की बित्तनी मात्रा ती जाये, इसे एक्जित फसल के आधार पर तय किया जाता था।

अंग्रेजों ने इस स्थापित परम्परा का अपनी खुद की प्रणाली से कैसे बदला? कैसे उन्होंने जमीन को जामानी में बेचन लायक मान का रजा दे दिया और—

स्वयं मजदूरों में रीतिरिवाज मजदूरों और बंधुआ मजदूरों को जन्म दिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन के समय के समाज और भूमि प्रणाली का अध्ययन किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों के आगमन से पूर्व भारत के गांव एक-दूसरे से काफी दूरी पर फैले हुए थे। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था। जमीन और हस्तकला से उत्पादित चीजों का, गांव की जनता ही पूर्ण तरह से इस्तेमाल करती थी। गांव का अपना समाज पर शासन था। ग्राम प्रधान जमीन सम्बन्धी विवादों तथा सामाजिक संघर्षों को हल करने की व्यवस्था गांव करता था। यह विभिन्न व्यवसायों में लोगों का लगाता था तथा उत्पादन के समान वितरण की व्यवस्था भी करता था। वस्तुतः किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप या मध्यस्थता की कोई जरूरत ही नहीं थी।

उनका रहन सहन का स्तर साधारण था। वे केवल खेती करना जानते थे। खेती से सम्बन्धित चलाव उतार के साथ ही वे डूबते उभरते थे। यदि फसल नहीं हुई तो उनका रहन-सहन का स्तर पतन में आ जाता था। अकाल, बाढ़, सूखा तथा अन्य विपदाओं में कुछ उठाना तो हर आदमी का बंधन था। लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि कारीगरों की स्थिति, एक हद तक कुछ बेहतर थी क्योंकि संकट के समय वे गांव छोड़कर राजा के पास कहीं बाहर जा सकते थे।

इसलिए यह कहना सही होगा कि निम्नांकित बातें भारत के ग्रामीण समाज का आधार थीं—जमीन तथा लोगों का उसे जानने का अधिकार और कृषि तथा हस्तशिल्प का संयोग। उन दिनों के हमारे गांवों में धर्म का यह वितरण एक अकाट्य नियम था।

सबसे पहले ही बताया है कि किसान ही जमीन के स्वामी थे। उनके सहित लोगों में लिखा गया है कि जमीन का असली स्वामी राजा था। फिर भी एक बार जानने के लिए जमीन तयार कर लेने के बाद यह मिलिकियत किसान के हाथ में चली गयी। राजा के शासित क्षेत्रों और किसान के स्वामित्व के बीच कोई विवाद नहीं था। युद्ध-क्षेत्र में हुए फसलों के अनुमान राजा और राजत्व में परिवर्तन होता रहा, लेकिन किसानों की मिलिकियत कभी भी प्रभावित नहीं हुई। सिर्फ कर किसी दूसरे की तिजोरी में जान लया। राजा और किसान के बीच कोई विचौलिया भी नहीं थी। भूमि प्रशासन ठीक से चलाने के लिए राजा गांवों में मुखिया नियुक्त करता था। इन मुखियाओं के इस्तेमाल के लिए अनाज तथा द्रव्य की व्यवस्था रखत करती थी।

कोटिस्वयं के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि भूमि पर संपूर्ण अधिकार राजा में निहित है। जिस जमीन का वह जेतने के लिए तैयार करता है उसे कृष्य भूमि कहते हैं। इस ग्रंथ में उस जमीन की उपज से रकत को आज्ञा तथा उठान का अधिकार है जिस पर वह खेती करता है। उसमें यह भी माना गया है कि खेती

के अयोग्य सभी भूमि पर रैयत का पुस्तनी हक है। अगर खेती न की जा रही है, उसी हालत में राजा खेती के योग्य और अयोग्य सभी भूमि का वापस ले सकता है और रैयत का वेदखल कर सकता है। यह एक सुविचारित धारणा है कि बंगाल में एक पुस्त से दूसरी पुस्त तक व्यक्तिगत आधार पर जमीन की मिल्कियत की प्रथा का प्रचलन था। अथ प्राता में भूमि सम्बन्धी अधिकार समग्र रूप में परिवार की इकाई में निहित थे। वशानुक्रम सम्बन्धी अपन विख्यात सिद्धांत में विज्ञानेश्वर ने इसका उल्लेख किया था। जा भी हो, ये दाना प्रथाएँ प्राचीन थीं।

उल्लेखनीय बात यह थी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि के उत्पादन का ही लाभ उठा सकता था। जहाँ तक जमीन का मामला है उसे जय वस्तुधा की तरह बेचा या खरीदा नहीं जा सकता था। बुनियादी तौर से किसी कृषि प्रधान समाज में आत्मनिर्भर किसान भू-स्वामी और उत्पादक दोनों थे। समूचे अंतःसम्बन्ध का यही सार था और इस आधारशिला पर ही प्राचीन भारत की सामंती व्यवस्था का उदय हुआ था।

अपनी निम्न अव्यवस्था और जमीन की सामूहिक मिल्कियत वाले ग्रामीण परिवेश में भू-स्वामी-बटाईदार सम्बन्ध अथवा भू-स्वामी-खतिहर मजदूर सम्बन्ध जसा अतर्क्य गतिविज्ञान विकसित नहीं हो सका। जमीन का कोई अभाव नहीं था और किसी तरह का व्यक्तिगत स्वामित्व भी नहीं था। इस हैमियत से जमीन जोतने वाला की सत्ता में वृद्धि भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें कोई परशानी पड़ा हो। किसी को स्यावलम्बी किसान मानने पर भी बाई प्रतिवध नहीं था। बाई क्या साधारण मजदूर बनना चाहता जब वह जासानी से मालिक उत्पादक हो सकता हो? उन दिनों हल चतान के लिए बलों की भी कमी नहीं थी।

मुस्लिम सम्राटों के शासन-काल के दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने जमीन के पद बनाये जिन्हें अच्छी तरह सीमांकित क्षेत्रों का स्थानीय नियंत्रण माँपा गया। फिर भी उनका ग्रामीण और किसानों से सीधा सम्बन्ध नहीं था। सम्राटों के लिए करा की वसूली तक ही उनकी भूमिका सीमित थी। इस काम में उन्हें गांव के मुखिया की मदद मिलती थी। इस प्रकार वशानुगत जमींदारी प्रणाली में रूपांतरित होते राजवंशों को बरों का भुगतान करने की प्रथा की स्थापना नहीं थी। मुगल शासन काल में भी ऐसा कोई अभिजात वर्ग नहीं था जो भूमि के स्वामित्व पर आधारी हो।

मुगल शासन काल में भू-राजस्व के भुगतान को संचालित करने वाले सिद्धांत के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। प्रथम हिंदू राजाओं का अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। दूसरे, मुगल सरकार अपने लिए कर वसूलने वालों का हमेशा नवद के रूप में चयन नहीं लेती थी। इसकी

बजाय कर वसूली वाला था उनका लिए निर्धारित क्षत्रा में कर की बगली की पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती थी। नतीजा यह होता था कि सरकारी स्तर पर छानबीन करने में बावजूद इन अधिकारियों को कर वसूलन में एक तरह से चुनी छूट प्राप्त थी। तीसरे कुछ मामला में ये अधिकारी गांव में मुखिया पर भरोसा नहीं करते थे और सरकारी खजाना में जमा करा के लिए निम्नाना से मोघ्न कर वसूलते थे।

इन तीन कारणों से कर-वसूली में बड़े प्रभाव रिवाजों से अलग जान की स्थिति मिलती है। फिर भी जमीन की मिलित राशि अथवा जमींदारों का हाथ में नहीं जाती थी। मत का जोतन और अनाज पैदा करने वाले अभी भी पहले की ही तरह इन सत्ता में मालिक थे। उन दिनों में जिन्हें जमींदारों का नाम से जाना जाता था वे दरअसल कर वसूल करने वाले एजेंट थे। दमन और यशना का अस्तित्व था। कवि मुकुंदराम चन्नर्ती लिखित 'चण्डीमंगल' में निहित दारा पोतदारा जादि जम मुगल अधिकारियों द्वारा जवणनीय यातना दिये जाने के अनवर प्रसंग मिलते हैं। यहाँ तक कि धूम दन में भी काम नहीं जाता था। सिपाहियों द्वारा एक के बाद एक मराना पर छापा मारा जाता था और यज्ञर जमीन का खेतिहर जमीन के रूप में दज किया जाता था। वे जाबूग कर सेता की तिरछी पैमाइश करते थे ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिक दिया कर जमीन का जाली खाता तयार कर सकें। इस स्थिति पर कवि मुकुंद न लगभग बिलखते हुए लिखा— किसानों की दुहाई पर कोई नहीं करता सुनवाई। केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के काफी दूर होने के कारण स्थानीय अधिकारियों के लिए निंदनी और दमनकारी होना जाता था। स्पष्ट था कि कर वसूलन की यह प्रणाली दुख और यातना को न मंद रही थी। और और करने की बात है कि कवि मुकुंदराम जिस बाल का बयान कर रहे थे वह मुगल सत्ता का शिखर बाल था।

मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ इस प्रणाली का सबमुत्त ध्वस्त होना लगा। केन्द्र में एक कमजोर सरकार के होने का लाभ उठा कर कर-बमूली के सभी तीनों वर्गों ने अपने-अपने इलाका में नकद और अनाज दोनों रूपों में भुगतान किया जानेवाले कर की राशि में मनमाने ढंग से बढ़ि कर दी। इसके फलस्वरूप किसानों को भयकर मनषा का शिकार होना पड़ा। फार्म्वा बर्निएर के यात्रा-वृत्तान्त में पण्डा को पलटन से कोई भी देख सकता है कि बारीबरा और छोटे व्यापारियों का भी नहीं बर्शा गया। ऊपर से एक नयी मुसीबत यह खड़ी हो गयी कि इतने दिनों से—अफगान राजाओं के आसन बाल से ही विवसित सिवाई व्यवस्था अब बर्खस्त होने लगी। उसने सती की बुनियाद पर ही मरणातक प्रहार किया। एक तरफ तो तुर्क सूबेदारों, जमींदारों तथा अन्य जफमरा की फौज थी

जीर दूसरी तरफ पानी का अभाव था। किसानों को कुछ भी नहीं सूच रहा था। कुछ स्थानों पर तो किसानों ने विद्रोह कर दिया।

काफी समय तक गांव की सामाजिक व्यवस्था ने विदेशी हमला से अपनी हिफाजत की। बदकिस्मती से इसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सामाजिक शक्ति का मुकाबला कर सके। यह प्राचीन, स्थिर और जड़ व्यवस्था उस प्रगति की राह में एक जबरदस्त बाधा बन गई जिसकी शुरुआत नवोदित बुजुआ वर्ग के हाथ हुई थी, जो शीघ्र ही प्रभुत्व स्थापित करने लगा था। उन दिनों व्यापार पर आधारित बुजुआ वर्ग अभी भ्रूणावस्था में था और काफी कमजोर तथा असंगठित था। देश की प्रगति का खाका तैयार करने में यह प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा सका। यही वह कारण है जिसमें भारत में सामंती व्यवस्था अपना पूर्ण विकसित रूप नहीं पा सकी।

इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर विजय पाने के फौरन बाद ग्रामीण समाज की जड़ पर प्रहार किया। अंग्रेजों की बुद्धि ने तुरंत वास्तविकता को भांप लिया। इंग्लैंड का माल बेचने तथा किसानों के उद्योग धंधों को कच्चे माल की शाश्वत कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन किसानों को गुलाम बनाने की जरूरत थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी था कि किसानों को उनके चिरपरिचित माहौल अर्थात् गांव से बाहर खींचा जाये। अंग्रेजों के सत्ता में आने से पूर्व अंग्रेज सादागरा का जकेले गांव में अपने माल की फेरी लगाने में असफलता का ही सामना करना पड़ा था। इन जातन भिर गांव में विदेशी सामान के खरीदार एकदम नहीं थे। शहरों और शहरों के आसपास के इलाकों में ही खरीददार तैयार किए जा सकते थे। ब्रिटिश शासन की जड़ें भारत की मिट्टी में तब तक गहराई तक नहीं पठ सकी जब तक उन्होंने ग्रामीण समाज का साह नहीं लिया।

और उन्होंने यही किया।

सत्ता में आते ही अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो तरीके अपनाये। पहला तरीका एक नयी कर प्रणाली की शुरुआत थी। दूसरा तरीका था कर भुगतान के रूप में फसल की जगह नकद राशि लेना। इन दो तरीकों से उन्होंने जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत का मांग प्रशस्त किया—एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जो उनके अपने देश में प्रचलन में थी। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन व्यवस्था का ध्वंस पूरी तरह कर दिया और नयी व्यवस्था की शुरुआत की।

अंग्रेज शासन ने प्लान किया कि जमींदार गुमास्ता और गांव के मुखिया के रूप में पुनर्जात होने वाला वर्ग ही जमीन का असली मालिक है। भुगतान नाम का प्रभावशाली 'जमींदार' का अर्थ एजेंट था। जब यह अर्थ हमारा बन लिए

## 16 भारत में बहुआय मजदूर

दफना दिया गया। जमीनदारों ने अब किसानों से अपनी ताकत भर वसूलना शुरू किया। साथ ही उन्होंने तीन अर्थ हथियारों का इस्तेमाल किया—जमीन को बिक्री जमीन का वितरण और गिरवी के रूप में जमीन रखना। इन तरीकों से दमन करने वाले नए वर्गों का जन्म हुआ—गाँदीनार, पट्टीनार, ररपट्टीनार और ताल्लुकदार।

उन्होंने अग्रजों द्वारा शुरू की गयी प्रणाली का किसानों से भूगुल हलक के नीचे ठेल दिया। फिर स्वयं किसानों का जमीन पर से अपना पुस्तानी हक सत्या के लिए छोड़ना पड़ा।

भारतीय रणमंच पर अग्रजों के प्रकट होने तक महान मुगल साम्राज्य का प्रकाश धुंधला पड़ने लगा था। किसान पहले ही उन सारी चीजों से वंचित होने लगे थे जो उनके पास अपनी सम्पत्ति के रूप में थी। अग्रजों ने इन सामान्य अवस्था मान लिया और उन्होंने भी उसी दूर अत्याचार और लूटपाट का रास्ता अख्तियार किया।

मुगल शासन-बाल के अंतिम दिनांक तक वे बसूलन के लिए तानत का इस्तेमाल किया जाना आम बात थी। धूत अग्रजों का भस्तिप्य इस मामले में मुगलों से भी ज्यादा उबर था।

दय कर के भुगतान न किया जाना पर किसानों की जमीनें बच देने की एक प्रणाली लागू की गयी थी। जब झपटाचार और जयलिप्ता का बालवाला था और गरीब किसान अपना खून पसीना बहाकर जा कुछ पदा करते थे उसकी आधी से भी कम मात्रा उनके पास बच रहती थी। यह गणित बहुत सरल था।

1764-65 के अंत में जब मुगल साम्राज्य अंतिम शांत ल रहा था और बंगाल में नवाबी प्रणाली एक दिशा ल चुकी थी बंगाल में भूमि कर 8 14 000 पौंड था। 1765 में बंगाल विहार और उड़ीसा के दीवान के रूप में इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जमान के बाद 1765-66 के गणना वर्ष में कुल 14 70 000 पौंड राजस्व की वसूली हुई थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह राशि 30 91 000 पौंड हो गयी थी।

इसने यह महज सरकारी अक्का था। इसने अलावा अलग अलग लागों को मिल व्यक्तिगत पुरस्कार और जमीन लूट का विस्सा ही और था।

किसानों को वह दरिद्रता की स्थिति तक पहुँचाने के बाद भी अग्रज नरम नहीं पड़े। उन्होंने चावल की जल्दी रेवाजी शुरू की। इस काम को कंपनी के एजेंट करते थे। उन्हें पता था कि अनाज की कमी होती ही मुनाफा बढ़ना लाजिमी है। अंत में बुरे दिन आ गये। किसानों को जिंहे फसल पत्ता करना आता था

वेवकूफ नहीं बनाया जा सका। उह अपनी उस सीमित भूमिका का एहसास हा गया जा फसल कटने के साथ ही समाप्त हो जाती थी। खेती से हुई फसल पर जिसे वे कमगुताड महनत के बाद पैदा करते थे, अब उनका किसी तरह का दावा नहीं था।

वे खेती के प्रति उदासीन हो गए। इससे खाद्य स्थिति और भी खराब हो गयी। जनाज की जखीरवाजी करके और कीमता में बेतहाशा वृद्धि करके ब्रिटिश सौदागरा न बेशुमार मुनाफा कमाया, लेकिन इसका जा अवश्यभावी नतीजा था वह भी सामन आ गया।

बंगाली कैलेंडर के अनुसार 1176 का बष बहुत अशुभ सावित हुआ। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर का बष 1770 जो बंगाली कैलेंडर के उस बष से मेल खाता था, देश में घुस आये इन नये जुटेरा के लिए भरपूर समझि का बष था।

1176 का यह साल औरा का तथा इतिहास को बखबी याद है। यह जयरदस्त जकाल का बष था—ऐसा जकाल जिसे मनुष्य ने तैयार किया था।

बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला कर बनाये गये सूबे की एक तिहाई आवादी के मुह से खान के लिए जा चीख निकलीवह कमश धीमी होती हुई सदा-सदा के लिए खामोश हो गयी।

खेतीवाडी का काम ठप पडा था, पर अंग्रेज सौदागर शामक अभी भी कर वसूलन निबलत थे। जत्याचार, मज्ना, बलात्कार और लूटपाट ही इनके हयियार थे। इसमे उह सफलता मिली। 1768 ई० में, अकाल से दो बष पूव बंगाल में कुल 1,52,40,856 रुपए कर के रुप में वसूल गय। 1771 ई० में, अकाल के एक बष बाद यह राशि 1,57,26,576 रुपए हो गयी।

साल दर-माल कम्पनी क खजान में ज्यादा से ज्यादा कर जमा हान लगा। कुछ अधिकारिया द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपनी जेजे भरन के लिए गर कानूनी ढग से करा की वसूली की गयी और कम पत्रिया में तरह-तरह के जत्या चार भी किय गये जिसके फलस्वरूप एक असगठन की स्थिति पैदा हो गयी। नतीजा यह हुआ कि कम्पनी अपनी करारोपण प्रणाली का मुचार रूप से न चला सकी।

1772 ई० में इमने 'पंचसाला वदावस्त' नामक प्रणाली शुरू की। जकाल के प्रभावा ने इस प्रयास का विफल कर दिया। इससे पूव एकसाला वदावस्त को पहले ही र्पनाया जा चुका था। बाद में, 'दससाला वदोवस्त' भी करारापण की नियमित प्रणाली को समथन नहीं दे सका।

एकदम हताश हाकर साड कानवानिसन न अन्तिम समाधान का सहारा लिया।

और यह था स्थायी वदोवस्त।



इस कदम के ज़रिए कर वसूलन वाला को भू-स्वामी बनाने का पातल काम किया गया। तबसे पहले जयत ही जमीन के स्वामी थे और उनसे कर की वसूली का काम कम्पनी के एजेंट करते थे। अब स्थिति उलटी हो गयी थी। अब भू-स्वामियों का उन किसानों से कर वसूलन का अधिकार लिया गया जो अब तब तक थे और जो अब इन भू-स्वामियों की प्रजा बना दिए गए थे। स्थायी वसतिगस्त में पहले भूमि का उचित तरीके से सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तबसे लाभ जमीनदारों ने उठाया और सती के लिए अयोग्य भूमि, चरागाहों व जंगल भूमि पर मुक्त भूमि तथा हर भरे जंगल को देना शुरू कर दिया। इस प्रकार कम्पनी की स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। नये शासकों ने अपने धर्म के देश में अपनाय जा रहे भू-स्वामियों के मताधिकार को शुरू करने की कोशिश की थी। 1793 ई० में पहले बंगाल के मूल में और बाद में उत्तरी मद्रास में उन्होंने अपनी याज्ञना के बाधित किया। दूसरा मकसद था कि कम्पनी का दूध करना नया अपना धर्म का शासन बाधित करना। स्थायी वसतिगस्त के तहत घोषित किया गया कि जमीनदार लोग वसूले गए कर का 10/11वाँ हिस्सा सरकार का देंगे और 1/11वाँ हिस्सा छुट्टे रहेंगे। असली लाभ सरकार को न कि जमींदार और किसानों का मिलता था। बजट बड़ी साफ थी।

उस समय जमींदारों ने 30 लाख पौंड सरकार को देना था—यह राशि पहले की तुलना में किसी भी राशि से बहुत ज्यादा थी। पुराने जमींदार परिवारों जिनके किसानों से वह अनिष्ट सम्बन्ध थे उस राशि का नहीं वसूल मन्। उन लिए किसी पर जल्दाचार करने और सतान की बात अपने आप में एक अभिप्राय थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि उनसे स्थान पर कुछ ऐसा व्यापारिक का रखा जाय जो धून चूमन और अत्याचार करने में माहिर हो। सरकार का सतुष्ट करने और वसूल की अपनी लिप्ता को पूरा करने के लिए उन्होंने आतंक का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास में वसतिगस्त है। यह कुलीन जमींदारों का एक नया बग था जिस स्थायी वसतिगस्त ने जान बूझ कर तैयार किया था। फिर भी स्थायी वसतिगस्त सरकार का प्रारम्भिक लक्ष्य नहीं पूरा कर सका। बाद में रूपए का मूल्य गिर गया। सरकार को बहरी कर मिले जा आमतौर से मिलते थे। लेकिन जमींदारों ने और अधिक कर वसूलन शुरू किया। फलस्वरूप सरकार का एकचौपाई भाग मिला जबकि जमींदारों ने अपने लिए तीन चौपाई हिस्सा रख लिया। तब के बटवारे की बात चाहिए हमें पर साम्राज्यवादी छद्म में स्थायी वसतिगस्त के बिना आयाज उठने लगी। इस आलाचनाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत को भूमि समस्या के बारे में अनजान होने के

कारण असावधानीवश किसानों पर कर का बोझ डाल दिया। असलियत यह है कि इन आलोचनाओं का निशाना था राजस्व में जायी गिरावट—यह ऐसा तथ्य था जिसे बड़ी कुशलता के साथ छिपा रखा गया था।

फिर भी दूसरा मकसद पूरा नहीं हुआ। नये जमींदारों ने अंग्रेजी शासन का मजबूत बनाने और टिकाव रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अंग्रेजों ने जिन वग को जम दिया था, उसने शासकों के हित के साथ अपने हित को बड़े करीब से पहचाना। आगे चलकर लांड बेंटिंक ने स्वीकार किया कि स्थायी बंदोबस्त ने जन विद्रोह या नाति के खिलाफ हुआ पक्ति के रूप में जमींदारों का एक काफी बड़ा वग पदा किया। जमींदारों को जिनका जनता पर काफी प्रभाव था, अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने में सफलता मिली, क्योंकि यह शासन उनके स्वार्थों को पूरा करता था।

बेंटिंक की यह धारणा आगे चल कर सही साबित हुई। जमींदारों के विभिन्न संगठनों, मसलन जमींदार महामण्डल, जमींदार एसोसिएशन आदि ने औपचारिक बठकों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी का एलान किया। वग जमींदार समिति ने 1925 ई० में वायसरॉय को विशिष्ट सेवा का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें समिति के सदस्यों ने वायसरॉय से कहा था कि वह उनके समर्थन और सहयोग पर भरोसा कर सकते हैं। 1938 ई० में निव्वल भारत जमींदार सम्मेलन के अध्यक्ष मैमनसिंह के महाराजा ने इसी तरह की टिप्पणी में कहा था कि जमींदार वग के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें सरकार के हाथ मजबूत करने होंगे।

चाटुकारों के एक वग का स्थापित करने में कम्पनी को कामयाबी मिल गयी। फिर भी उनके आर्थिक मामलों में अभी भी बहुत गड़बड़ घाटाला था। उन तथ्यों ने उन लोगों का अर्थ देशों में स्थायी बंदोबस्त को लागू न करने के लिए प्रेरित किया। जमींदारी प्रणाली के साथ किये गये प्रयासों से उन्हें यह सन्नक हासिल हुआ कि करों की प्रत्यक्ष बसूली करनी होगी। बिना किसी बिचौलिये की मदद लिये किसानों का शोषण करना बेहतर है।

उन्होंने दक्षिण भारत में रयतबाड़ी प्रणाली स्थापित की जिसमें सरकारी सीधे किसानों से निवटती थी। लेकिन तो भी यह स्थायी कदम नहीं था इसमें सशोषणा की गुंजाइश थी। परिणामस्वरूप सरकार समय-समय पर नये मिर में भूमि का सर्वेक्षण और करों में वृद्धि कर सकती। जमींदारों अथवा अन्य बिचौलियों की मदद के बिना सरकार करों की समूची राशि खुद अपने लिए बसू सकती। इस दिशा में सरकार का प्रयास और जातान हो गया, क्योंकि गांधी की सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका था। दक्षिण भारत में फिर भी यह मान सही थी। 1818 ई० में मद्रास राजस्व बोर्ड द्वारा जारी एक

स्मरण यह मैं प्रस्तुत जालोचना में कहा गया था कि ग्रामीणों का एक वापसी लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से विदेशी सरकार ने पुरातन ग्रामीण परम्पराओं का नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये वही परम्पराएँ थी जिनका गाँवों में जनतंत्र का बनाव रखा था।

सैंकड़ों वर्षों में जो जमीन गाँवों की सामूहिक सम्पत्ति थी उसका नये कृषि कानूनों ने विघटन कर दिया। इस आशय के आशयमान नियमों के जमीन के बारे में सरकार के दावे मीमित रहेंगे। वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं था।

रयता की जमीन का निरन्तर पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा था और नये कर घोषित जा रहे थे। किसानों का जबरन जमीन में नरबी कर दिया जाता था—ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान राजाओं के शासन-काल में होता था और यह प्रतिष्ठा छासतीर से उन जमीनों पर लागू की जा रही थी जिन पर करोड़ों का नकदी तौर पर बड़ा रखा गया था। इस मुसीबत से उबरने के लिए भाग्य की भाँति जगह नहीं थी। जो किसान खेतों में भागते थे उन्हें जबरदस्ती घसीटकर काम पर लगा दिया जाता था। फसल बटन तक दावा के बारे में हर तरह की बहस का स्थगित रखा जाता था। किसानों के हिस्से में उस रोज और बस ही पड़ते थे। जिस किसानों के पास यह भी नहीं था उन्हें सरकार द्वारा यह दिया जाता था। ऐसा करना सरकार के हित में था।

रयतवादी प्रणाली के सहित किसानों की जमीन के मालिक के रूप में स्वीकार किया जाता था। जमीनदारी वगैरह की रचना का कोई प्रयास नहीं किया गया। ता भी यथायथ में होता यह था कि कोरफाविला प्रणाली के जिन सूत्रों के जमीन की मिल्कियत मिलने लगी और रयतवादी प्रणाली के अंतर्गत पत्त वान क्षत्रा में जमादारों की तात्कालिकता से घटने लगी। जाहज़ा में पता चलता है कि 1901 ई० से 1912 ई० के बीच मद्रास में एम भू-स्वामियों की संख्या, जो किसान नहीं थे प्रति हजार भू-स्वामी पर 19 से बढ़कर 49 हो गयी। किसान भू-स्वामियों की संख्या 484 से घटकर 381 रह गयी। किसान रयता की संख्या प्रति हजार पर 151 से बढ़कर 225 हो गयी।

उक्त अवधि की जनगणना रिपोर्ट में अन्य भू-स्वामी के बारे में भी ऐसा ही तमबीर उभरती है। पंजाब में भूमि-करा पर नियंत्रण रहनेवाला की संख्या 1911 ई० में 6 26 000 थी जो 1921 में बढ़कर 10 08 000 हो गयी। समुच्चय प्रांत में 1819 में 1921 ई० के बीच इस तरह की जायानों में 46 प्रतिशत का वृद्धि हो गयी। इस अवधि में वर पर नियंत्रण की संख्या में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उत्तर और उत्तर-पश्चिम में अंग्रेजों ने महलवादी प्रणाली शुरू की। यह स्थायी बढोन्नति और रयतवादी प्रणाली के बीच का रास्ता था। महलवादी

प्रणाली ने ग्राम-सभाज अथवा कबीले का भूमि के सामूहिक स्वामी को भायता दी। लेकिन यह महज एक स्वाग था, क्योंकि कबीले के सदस्या को सौपी जाने वाली जमीन का अलग-अलग सर्वेक्षण और पैमाइश की जाती थी। मिसाल के तौर पर पंजाब की बात लें। गांव का मुखिया ही कर वसूलने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। फिर भी कर की वसूली प्रत्येक किसान में अलग अलग की जाती थी।

स्थायी वदावस्त रैयतवादी और महलदारी ही वे तीन हथियार थे जिनसे अंग्रेज शासक ने भारत की एक एक जमीन को हड़पना शुरू किया। उन्होंने जमीन से किसानों को हटा कर जमींदारों को बसाया। सूदखोर महाजन किसानों की पीठ पर सवार हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं था। कोरफाविली प्रणाली ने उन्हें ऐसे लोगों की गजा बना दिया जो खुद भी प्रजा थे। अब जमीन उर्वर नहीं थी। कोरफाविली प्रणाली के लगाने के वृत्ते उपाय ने जमींदारों तथा पंचायत विचौलिया को जम दे दिया था। इन विचौलिया का जमींदारों और किसानों के बीच जिन्हें कोरफा रैयत के स्तर तक नीचे ला लिया गया था घुसा दिया गया।

और फिर भी किसानों की जिंदगी चलती रही। बस अब वे अपनी पीठ पर एक पिरामिडी ढांचा ढा रहे थे जिन्होंने उनका खून चूस लिया था। जमीन की अब उन्हें मान जानकारी थी जिसके साथ उनका आत्मिक सम्बन्ध बना हुआ था, पर अब जमीन पर उनका कोई हक नहीं था। एक बार फिर कवि मुकंदराम के गीतों के शब्द सच लगने लगे — किसानों की पुकार कौन सुनता है? उन्होंने सब कुछ खा दिया — यहाँ तब कि हल, बल और गीज भी। जमीन खा कर अब वे भूमिहीन खेतिहर मजदूर बन गये थे। और ऐसे नागा की सट्टा बढ़ती गयी। 1882 ई० की जनगणना में इनकी सट्टा 70 20,000 थी। 1921 ई० की जनगणना में यह सट्टा बढ़कर 2 10,00 000 हो गयी। 1931 ई० में इनकी सट्टा 3 30 00,000 तक पहुँच गयी। इन आँकड़ों की व्याख्या में अब लगाया गया कि उन दिनों किसानों का एक तिहाई हिस्सा खेतिहर मजदूर था। 1941 ई० में कुल जावादी का 50 प्रतिशत थे।

यह हुआ कैसे? जिन जमीन से किसी जमाव अथवा जमरत की पूर्ति नहीं वह थलाभरकर है। छोटे किसान और बटाईदार जो ऐसी जमीन जोतेते थे दिनादिन और भी गरीब तथा दरिद्र मजदूर होते गये। दाना वर्गों के बीच ज्यादा फसल हो — ऐसी बात नहीं थी। 1930 की मद्रास बकिंग रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरफाविली किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच का फसल दीखता नहीं था। कोरफाविली को इस समयदारी के आधार पर कमजोर कर दिया गया था कि करों का भुगतान नकद रूप में होना। जमीन का वितरण जमादारी के आधार

पर किया गया था। फिर भी भू-स्वामियों ने रयत का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत तक फसल से भी वचन हान का मजदूर किया। इस प्रकार जल्दी ही रयत का दिवालता पिट गया और जमींदारों में साधना का बज्र पड़ा। इस राशि की अदायगी का मतलब बगई के समय फसल का अपना हिस्सा जमींदार के अनाज गानाम में जमा करना होता था। और इस प्रकार उनका किस्मत खराब होनी लगी।

उन जिनका एक किसान का अपने परिवार का दैनिक खर्च चत्तान के लिए 5 एकड़ या 15 बीघा जमीन तथा अपने खुद के हल-बल की जरूरत पड़ती थी। पलाउड कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि सती मलय परिवारों में से तीन बीघाई के पास 15 बीघा में कम जमीन थी। लगभग 57.2 प्रतिशत परिवारों के पास 9 बीघा से भी कम जमीन थी। दक्कन के गाँव में माका मुआमला करने में पता चला कि जिस वर्ष फसल अच्छी होती थी उस वर्ष भी 8 प्रतिशत किसानों के पास पर्याप्त खाद्य नहीं होता था। बमूदगार महाजनता में अपने जीवन मापन के लिए भूत पर पस नैन थे। जिन 3 जिन बज्र का बाँझ चन्ता गया। फिर अचानक एक दिन उन्होंने पाया कि वे अपनी जमीन खा चुके हैं और भूमिहान मजदूरों की श्रेणी में आ गए हैं।

एक पुरानी कहावत है कि दान कर धन ना घट। यह भू-विचार की नकल लगता था। भू-खार महाजन जितना ही पसा बज्र के रूप में दस्त ध उतनी ही उनकी समृद्धि बढ़ती थी। किसान लोग विद्रोहतिथों के उस चूह के समान थे जो सापा के घुसने के लिए ही बिल बना रहे थे। उनकी परियाद कौन मुने? कोई नहीं—एकदम बाइ नन्ना।

सेतिहर मजदूरों का किस दर से पस दिया जाना था? 1842 ई० में एक मजदूर का प्रतिदिन एक आना मिलता था। तब एक रुपये में 40 मन चावल मिलता था। 1922 ई० में चावल एक रुपये में 5 सर की दर में बचा जाता था जबकि एक मजदूर का दैनिक मजदूरी 4 से 6 आना थी। 1842 में 1922 ई० के 80 वर्षों के दौरान मजदूरी में 4 से 6 गुनी वृद्धि हुई, जबकि चावल के मूल्य में 8 गुनी बढ़ोतरी हुई। फलस्वरूप वास्तविक मजदूरी में 25 से 50 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1842 ई० में कोई मजदूर एक आना में दस सर चावल खरीद पाता था जबकि 1922 ई० में वह 5 से 6 आना में लगभग डेढ़ सर चावल खरीद पाता था।

सेतिहर मजदूर का काम मासमी होता है। अधिकांश स्थानों में येन जाने और काटने का काम वर्ष में एक बार होता था। मजदूरों के पास बज्र लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लाखों लोग बज्र के बल पर अपनी गाड़ी चलाते थे। बज्र के साथ-साथ उनकी जिन्दगी में अपमान न भी प्रवेश किया।

स्वतंत्र मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा बधुआ मजदूर बन गया। उन्हें फिर कभी मानवीय मर्यादा नहीं मिल सकी।

कज देकर गुलाम बनाने की नीति जादिवारियों के मामले में काफी पहले शुरू हो गयी थी। 1855-56 में जो सथान विद्रोह यानी हूल हुआ था उसका मुख्य कारण यह था कि जमींदारों और सूदखार महाजनों ने सथाला को बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की थी। उन दिनों के कलकत्ता गजट में यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार सथाला के भालेपन का नाजायज फायदा उठा कर सूदखार महाजन उनसे 50 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक सूद वसूलने थे। कज के एवज में मजदूरों को गुलामी के पट्टे पर दस्तखत करना पड़ता था। हटर लिखित इतिहास में जवरन गुलाम बनाये जाने की घटनाओं के स्पष्ट मदम मिलते हैं। इस काम में जमींदारों और महाजनों को सरकार की पूरी मदद मिलती थी। मिथू और फानू के नेतृत्व में किये गये हूल तथा प्रतिरोध की अन्य घटनाओं के पीछे—जो अंग्रेजी राज के दौरान घटित हुए—इसी शमनाक शोषण का हाथ था।

9034

अपनी पुस्तक 'भारत की भूमि समस्या' में प्राफेसर राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि म्याथी खेतिहर मजदूर भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर जाते थे। नकद के रूप में पारिश्रमिक पाने की घटनाएँ इन्का दुकरा ही थीं। इन खेतिहर मजदूरों के बीच गुलामी के कई रूप देखने को मिलते हैं। कुछ तो विशुद्ध गुलाम थे और कुछ गुलाम जैसे थे—फकत बहुत मामूली या। जमींदारों मालगुजारों तथा इस तरह के अन्य वर्गों ने कज व घातक जाल के जरिए अपने गुलामों का पगु बनाने का मिलसिना चला रखा था। भारत के कई हिस्सों में यह प्रथा आज भी जारी है। यह निकृष्ट प्रथा वाप के बाद वटक द्वारा चलायी जाती थी। महाराष्ट्र की दुविया और कालिया जातियाँ गुलामों में बेहतर नहीं हैं। इनमें से अधिकांश पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मालिकों की गुलामी करत रहे हैं। मद्रास व दक्षिण पश्चिम में एन्नावा, चेन्ना, पुली और होलिया पाय जाने हुआ रास्तव में गुलाम हैं।

मद्रास के पूर्व में समुद्र से घिरी नदियाँ की तटवर्ती जमीनों पर ब्राह्मणों की मिल्कियत है। स्वाभाविक तौर पर मजदूरों परिया और परियाला का अधिकार हिंसा अछूत भी है। काफी पहले अपने पुरखा द्वारा लिये गये कज को जदान कर पाने के कारण परियाला के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी चरती रही है।

इस तरह के कज कभी चुकता नहीं हो सकते और यह बोझ एक के बाद एक अगली पीढ़ी पर खिसकता गया। जहरत पढ़ने पर मालिक इनकी जमीन बेच सकते हैं लेकिन ये गुलाम लोग एक मुश्त सौदे का हिस्सा हैं और इस प्रकार वे खरीदार की सम्पत्ति बन जाते हैं। इस तरह के गुलामों की सूची में विहार

कमिया है जो वेहद निचले वग व है और वज की जजोर में जकटे हुए है। अपने वज से जाशिक छुटकारा पाने के लिए उनके मालिक ऐसे काम उनसे ले सकते है जिनका वयान भी नहीं किया जा सकता।  
इस तरह के कजों के बारे में अब हम बताएंगे।

( 2 )

अब हम छाटे किसानों और खेतिहर मजदूरों द्वारा लिये गये वज का विवरण करेगे। हमने पहले ही इनकी आर्थिक अवस्था भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इनकी स्थिति इनके स्थान तथा वज लेने के कारणों पर प्रकाश डाला है। छोटा किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी जमीन से पर्याप्त उत्पादन पान में असमर्थ है। इसी के साथ करा, बीज पर जान बानी लागत शान्तिया और दाहकर्म पर होने वाले खर्चा का बोझ भी उन्हें घेना पड़ता है—दवाआ पर होने वाले खर्च की तो बात ही अलग है। सूदखोर महाजन से पस की भीख मांगे बिना वे रह ही नहीं सकते। किसी घाम समय में मजदूरों की आय तथा चावल के निर्धारित मूल्य की तुलना की जानी चाहिए। जाच से यह पता चलेगा कि मजदूरों का एक दिन भा पट भरना नहीं नसाय होता था। छोटे किसानों की तरह—जो अमानत रूप में अपनी जमीन गिरवी रखते थे—उन्हें भी वज लेना पड़ता था। जल्दी ही वज बढ़त उड़त इतना हो जाता था कि उन्हें अपनी जमीन बेच देनी पड़ती थी और वे भी खेतिहर मजदूरों की दुखद श्रेणी में आ जाते थे। छाटे किसानों के विनाश का अब सूदखोर महानों को लाभ था।

सादमन कमीशन रिपोर्ट का कहना है कि किसानों का अधिकांश हिस्सा महाजन और जमीन इस्तमाल करने वाला व वज से बंधा था। किसानों और खेतिहर मजदूरों की ददनाक अवस्था के लिए अंग्रेजों का अनाया और कोई ज़िम्मा दार नही है। इन पर वज का जसे जसे बाध बढ़ता था ब्रिटिश शासक द्वारा की गयी प्रगति की रसनाएँ और तज हो जाती। निरंतर आग वाली रिपोर्टों में घामनौर से पिछले 50 वर्षों की अवधि में वज के निरंतर बढ़त बाझ, हताशा में घेती गयी और गिरवी रखी गयी जमीनों का जिक्र 1911 ई० में सर एडवड भवनागा ने अपने वयान में किया है।  
1911 और 1938 के बीच की अवधि के आँकड़ा पर यदि एक निगाह डालें तो बात बहुत साफ हो जाती है।

वर्ष	कज का बोझ (रुपये में)
1911	300 करोड़
1924	600 करोड़
1930	900 करोड़
1935	1200 करोड़
1938	1800 करोड़

इस बात से कोई इफ़कार नहीं कर सकता कि गावों में गरीबी का कारण कज का यह बोझ ही है। कुछ सर्वेक्षणों से पता चला कि अधिकांश मामलों में किसानों ने मवेशी खरीदने, खेतों के लिए लागत पूजी जुटाने और करा के भुगतान के लिए कज का सहारा लिया। कज का 1/5वें से भी कम हिस्सा सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होना था। आज की हालत भी पहले से भिन्न नहीं है। अभी हाल में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उपकरण तथा बीजा की खरीद के लिए तथा करा का भुगतान करने के लिए किसान लोग प्राप्त ऋण का 47.5 प्रतिशत खर्च करते थे। केवल लगभग 33.7 प्रतिशत राशि को सामाजिक दायित्व पूरा करने पर खर्च किया जाता था।

किसानों की निरंतर बढ़ती कजगारी के असली कारणों का बड़ी कुशलतापूर्वक छिपाया जाता था। कहा जाता था कि किसान अपनी चादर देखकर पैर नहीं फलाते। किसी कंगाल का महल के मकान देखने की क्या जरूरत? सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर वे क्यों इतना पैसा बहाते हैं?

पहले, पैसे का प्रमुख स्रोत गांव का महाजन होता था। अंग्रेजों के आने से पूर्व, किसान व्यक्तिगत गारंटी पर उनसे कज ले सकते थे। इससे वे निरुपय नहीं होते थे, क्योंकि महाजन को भी गांव के ही बायदे कानूनों का पालन करना पड़ता था। गांव का समाज किसी का इस बात की इजाजत नहीं देता था कि कज चुकता न होने पर उनकी जमीन हड़प ली जाये। अंग्रेजों ने इन सारे नियमों को बदल दिया और सूदखोर महाजन गांवों के मालिक बन बैठे। अंग्रेजी शासन का प्रारम्भिक दिनाम में महाजन वस फसल लेने के बाद किसानों को छोड़कर 4 — उनकी जमीन नहीं छूते थे। लेकिन अंग्रेजी राज ने ठूपापूर्वक इन महाजनों के अधिकार बढ़ा दिये और कानून, पुलिस तथा ब्रिटिश सरकार के भरपूर समर्थन से उन्हें जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया। सूदखोर महाजनों को अब सारी फसल जब्त करने का अधिकार मिल गया। और यह सब करने के बाद भी कज को ज्यों का त्यों दिखाया जाता था। मूल और सूद में कौन क्या है — किसे यह पूछने का साहस था?

महाजन के कोठार में जो अनाज चला जाता था उसमें से ही फिर किसान



को अपना पट चलाने के लिए बज्र मिलता था। और इस प्रकार बज्र पर बज्र बढ़ता जाता था। किसानों को कवि ने एक बार कहा था कि अगर आकाश का बागज बना दिया जाय समुद्र का दावात और घास का बलम तो भी उसकी कविता पूरी नहीं होगी। गाँवों में बज्रदारी का वृत्तांत लिखने के लिए आकाश समुद्र और घास की बलम भी पर्याप्त नहीं साबित होगी।

हर बार इस कथा का अंत बज्र चुबता करने के लिए हताश हानर जमीन बेचन और स्वतंत्र किसानों के बटाइदार अथवा सतिहर मजदूर बनन में होता था। इस प्रकार गाँव के महाजन छोटे भाटे पूजोपति और विमान उनमें मजदूर बन गये।

कम्पनी द्वारा संचालित सरकार ने खुद अपने स्वार्थों के लिए महाजनों का बड़ावा दिया।

1799 ई० में मातव विनियमन—ठुकरान हैफ्टम सा—की घोषणा हुई। इस कानून ने जमींदारों और महाजनों का रयता तथा किसानों में जमीन जाली करवाने के अधिकार दे दिये। इसमें अलावा किसानों पर पावदी लगा दी गयी कि वे एक जमींदार को छोड़कर दूसरे के पास जाने के लिए अपना रतावा न छोड़ सकें। साथ ही वे कहीं और काम भी नहीं कर सकें।

1812 ई० में पाचव विनियमन—पजन सा—का लागू किया गया। इस कानून के जरिए जमींदार पहन से ही करा की दर तय कर सकता था और फिर खती के लिए लाइसेंस का वितरण करता था। इस लाइसेंस का कभी भी वापस लिया जा सकता था। फल जल करने का अधिकार पहन ही 1793 ई० से लिया जा चुका था।

मुगल शासन काल में करा की दर को मनमाने ढंग से नष्ट करता जा सकता था। लेकिन विमर्ष स्थितियों में अनिश्चित अवकाश (उपकर) लगान की इजाजत थी। 1859 ई० के बंगाल कर कानून के मुताबिक निर्धारित कर का जमींदार किसी भी बहाने से बढ़ा सकता था। समूचा देश उन खूबहार तुरन्ते व्यक्तियों का भिन्नारगाह बन गया।

कई मामलों में ये सूदखोर महाजन खुद ही जमींदार या विचौलिय बन गये। फलस्वरूप एक ही तरह के लोगान—जिन्हें चाहे जमींदार कहिये या ताल्लुकेदार पट्टनीदार गरीदार या महाजन—लूटमार का सुनियोजित कार्यक्रम शुरू कर दिया। करा के अलावा किसानों को उस समय धूस भी देनी पड़ती थी जब उनसे दर स कर जमा करने आदि जसी छोटी मोटी चूक हा जाती थी। अनेक छोटे मोटे अधिकारी भी थे जिन्हें खुश रखना पड़ता था। जमींदारों का एकाउंट उसका कास्टेवल उसका वारि दा—इन सबकी हथेली गरम करनी पड़ती थी। धूसखारों को एक प्यारा सा नाम दे दिया गया था—इम धोती

घरीदना' कहते थे। लेकिन कवि मुकुंदराम इस पर अफसास जाहिर करते हैं कि 'धानी घरीदने से भी किसानों की सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। फसल जुन्न होनी और यहाँ तक कि जमीन से वेदखल हाने का खतरा हमेशा सर पर मँडराता रहता था। अदालत से कोई मदद नहीं मिलती थी। व जमींदारों के बैठकघान की तरह थी।

जा स्थिति तब थी वही आज भी है। जमींदारों, विचौलियों और महाजनों की फरमाइश पूरी करने के बाद गरीब किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था और उसे फिर बज का सहारा लेना पड़ता था। एक कहानी है कि किसी ऊँद विलाव ने एक मछली पकड़ी और उस वाटन का काम जगली बिल्ली का दिया। नतीजा यह हुआ कि मछली का पकड़ने के लिए ऊँदविलाव का फिर पानी में गाना लगाना पड़ा।

निरक्षर ही यह बड़ी निराशाजनक स्थिति थी। फसल के रूप में दिया गया बज पर 150 प्रतिशत और नकद के रूप में दिया गया बज पर 200 प्रतिशत मूल्य लगता था। और बज की यह घाली जगनी पीढ़ी के लिए पड़ती थी। जहाँ तक कानून की बात है— वह हमेशा धनिकों की मदद करता था।

क्या किसानों ने इन दूर भाग्य के सामने हथियार डाल दिए थे? नहीं, कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह किया। उनके अंदर न ता थग-चनना थी, न मगठन था और न बुशान नेतृत्व हो था जिसमें वे विजयी हो सकें। बशक उन्होंने अपने दुश्मनों की गिनत कर ली थी। उन्होंने सरकार, उसके शक्तिशाली मगठन जमींदारों और महाजनों के नकायना चेहरों की अभियंत का समर्थन किया था। हमें उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी पाठियों पर हमला किया जा अभिनय की उदाहरण उदाहरण एक रानीनिक महल मिला। उसके बाद उदाहरण है—नीलमौर के नेतृत्व में धारावाहिक का घाली विद्रोह, फरीदपुर का फरीद विद्रोह 1832-33 में माना में कृषि विद्रोह, 1831-32 का वान विद्रोह 1855-56 का गणतंत्र विद्रोह, नील धारावाहिक के मजदूरों का विद्रोह धारावाहिक का किसान विद्रोह दक्षिण का किसान विद्रोह, मालावा में मापना किसानों का विद्रोह। क्या इन धारावाहिकों में भूला जा सकता है? हजारों किसानों के गून से रघो धारावाहिकों पर आज अनाज के घेत ध्यन्त सड़कों शहर दूधान और बाजार पन है। लेकिन उन विद्रोहों की मच्छाह को मामबत्ती की ली की तरह पन कर बुझाया नहीं जा सकता। यह सभी संभव नहीं है।

अपने उमाओं के विद्रोहों में कुछ मामलाज्याओं का पन इतिहासकारों ने किसानों के विद्रोहों का काफी समझा छोड़ा आवरण चढ़ाने का जनता के मामलों पर किया है। जनता का पता पता कि यना संप्रदायिक दम हरनिकों की था। आज की भाषा में इन उदाहरणों का उमाज विरोधी उदाहरणों अथवा उदाहरण नाम



म सुनते हैं। अंग्रेजों के दमन के खिलाफ सघप करने वाले वह पहले विद्रोही नेता थे। यह घटना 1780 ई० में भागलपुर में घटित हुई। उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया और पांच वर्ष तक लड़ते रहे। उन्होंने ही छापामार युद्ध के जरिए भागलपुर के कलकटर क्लीवलेड का मफाया किया। 1855-56 के विद्रोह पर उनके सघप का जबरनस्त प्रभाव पड़ा था। तिलका माथी का नाम पुराने रस्तावेजों में पाया जा सकता है हालांकि इतिहास के शोधकर्त्ताओं का उनके नाम का उल्लेख करना गवारा नहीं है।

सन 1855-56 के सयाल विद्रोह की मुख्य मांग थी कि खेती योग्य तैयार की गयी जमीन पर अधिकार को उनकी मांग की सुनवाई की जाय। साथ ही जमादारा, मदानना और सरकारी अफसरों तथा पुलिस को उनके इलाके में प्रवेश की इजाजत न दी जाय। कमिया या गुलामी की कुख्यात प्रथा को खत्म किया जाये। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आजादी की लड़ाई थी। खेती गवा, हलगेया हो' (हम सचमुच लटेंगे) की रणभेरी के साथ उन्होंने सघप को जागे बढ़ाया। सयाला ने घने जंगल का साफ करके जमीन का खेतीयादी करने और रहने के योग्य बनाया था। उन्होंने हमें फसलें पदा की। व्यापारियों और मूदखोर महाजनों ने उनके भोलेपन, ईमानदारी तथा सीधेपन का बड़ी क्रूरता के साथ फायदा उठाया। फसल की कटाई के समय वे अपनी खाली बैलगाड़ियाँ लेकर पहुँचे और उनमें फसल भरने लगे। बदले में इन धूर्तों ने उन लोगों को थोड़ा सा नमक तम्बाकू तथा शीरा दे दिया—कभी कभी कुछ सिक्के भी दे दिये। इस प्रकार जमींदारों, पुलिस और यूरोपीय जिला मजिस्ट्रेटों के पूरे समयन से फसल पर उनका कब्जा हो गया।

बरसान के मौसम में गरीब सयाल भूखा मरते थे। मूदखोर महाजन ने उन्हें कज लेने को मजदूर किया और कज सम्बन्धी रक्का पर उनके अगूठे के निशान न लिये। अगर एक दिन सयाल महाजन से उधार लिये जनाज को पाता था तो आने वाले दिन वह आर उसका परिवार पूरी तरह उस महाजन की गुलामी की जजीरों में बंद मिलता था। 33 प्रतिशत चन्नवृद्धि व्याज की दर से देखते देखते कुछ रुपये सैकड़ों रुपये में बढ़ल जाते थे। एक दिन वह सयाल मर जाता है आर उसका घेठा अपने बाप के अंतिम सस्कार के लिए फिर पैसे उधार लेता है। कज देने हुए महाजन की बाँछे खिल जाती है। लोनकथाओं का जादुई तोता राजकुमार को हीरे मानी और मणि देने के लिए उकसाता था। मूदखोर महाजन न भी भोले भाले सयाला के साथ यही किया जिन्हें यह कभी जायाम न हो सका कि वह जो कज आज ले रहे हैं वह भविष्य के गरीब में पनी पीढ़ियाँ के लिए भी एक अदृश्य जजीर बनने जा रहा है। महाजन की इस धमकी से कि वह उन्हें जेल भेज देगा सयाल काफ उठल थे। वे खुले आवाज और विस्तृत क्षितिज के प्राणी



ई० में बंगाल का शक्तिशाली कानून पारित हुआ। इस कानून ने जमीन के अधिग्राहकों को जमीन के अधिकारों का जमाना दे दिया। इस कानून ने जमीन के अधिकारों को जमाना दे दिया।

इसके कुछ ही समय बाद दखन में मोपला लोग का विद्रोह हुआ। दरअसल यह 1873 में ही शुरू हुआ था और 1921 तक चलता रहा। मोपला लोग ने— जो धर्म मुसलमान थे— दमन की तीव्र शक्तियों अर्थात् अग्नेय जमींदारों और मूदखार महाजनों के खिलाफ हथियार उठाया। यह विद्रोह तेज होता गया और फिर इसने खिलाफत विद्रोह का रूप ले लिया। दुश्मन ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी। अग्नेय की सेना और पुलिस का जमींदारों और मूदखार महाजनों की निजी सेना ने मदद पहुँचायी जिससे बाकायदा वतन प्राप्त करने वाले सैनिक थे। वे जालुवागड और एरनाम में उतरे। बड़ी बरहमी से उन्होंने मोपला लोग का कत्लेआम किया। उनके अत्याचार आतंक के पर्याय बन गये।

बावजूद इसके मोपलाओं ने मघप जारी रखा। उन्होंने एलान किया कि उनकी धरती आजाद है और अली मुजलिफों को उन्होंने अपना स्वतंत्र राजा बनाया। लेकिन अग्नेय बेहद मजबूत था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। उनसे निपटने के लिए छापामार युद्ध ही एकमात्र तरीका था। 48 वर्ष के दौरान मोपलाओं ने पाँच बार विद्रोह किया।

पाँचवें विद्रोह के बाद उन्हें हथियार डालने पड़े। अग्नेय ने सक्का विद्रोहियों को गोली से उड़ा दिया और विद्रोह के प्रमुख नेताओं का सावजनिक स्थान पर फाँसी पर लटका दिया।

लेकिन ये विद्रोह आंशिक रूप में सफल रहे क्योंकि इन विद्रोहों के कारण ही अग्नेय शासकों ने 'महाजन कानून' पारित किया।

जो जाने कुरबान गयी उनकी तुलना में जो छोट्ट मोटे काम हुए उनके लिए जहर में ज्यादा कीमत जदा करनी पड़ी। दमन अभी भी बरकरार था। महाजन कानून पारित करने का मतलब कुछ नहीं होता। कानूनों का अमल में भी लाया जाना चाहिए था। यह कभी नहीं हुआ।

लेकिन विपत्ति अभी भी घात लगाकर बैठी थी। इन गरीबों के लड़कों का धोखा देने के लिए जातीय जागतिकी मदद देना बहुत आसान था। अदालतें जमींदारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कानून का अमल में लाने के लिए निम्न अफसरों का घूस देकर भ्रष्ट कर दिया जाता था। 1928 ई० में संघी आयोग ने बड़ी कटुता के साथ लिखा कि लोग अपनी किस्मत पर बहुत निभर रहते हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए मूदखार महाजनों के आगे भीड़ मागत हैं। इसमें कहा गया था कि इन प्रकार महाजनों का शिरोधार्य दिना दिया जाता है।

आयोग ने सच्चाई का बयान नहीं किया। इसने यह तर्क दिया कि इन

काम में सरकार उनकी मदद करती है।

1931 में सेंट्रल वक जांच समिति की रिपोर्ट ने उही दो तथ्यों का दुहराया जिसने बार में हम पहले से जानते हैं। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश शासन-काल में प्रारंभिक दिनों में किसानों को इसलिए सरकार के दमन का शिकार होना पड़ा क्योंकि वे कर का भुगतान नहीं कर सके थे। दूसरे, बाद में उन्होंने अपनी जमीन बच दी और खेतिहर मजदूर अथवा वधुआ मजदूर बन गये।

इस प्रकार किसानों की जमीन पर उन लोगों की मिलीभगत हो गयी जो सती नहीं करते थे। भावात्मक सम्बन्ध समाप्त हो गया। बग विभेद और भी खुलकर सामने आ गया तथा खेती-बाड़ी के काम में कमी आयी।

यहाँ तक कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक असंतुलन, उत्पादों के मूल्य में गिरावट, द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रभाव तथा व्यापक अकाल के कारण खेती का काम बड़े सक्त्पूर्ण दौर से गुजर रहा है।

उत्पादन की कीमत गिरने के साथ ही किसानों की भी स्वतन्त्र क्रय शक्ति में कमी आयी।

आँखों से पता चलता है कि अव्यवस्था में भयंकर सड़क शुरू होने से पूर्व सन् 1928-29 में वृषीय उत्पादन का आसत मूल्य फसल कटने के समय 1034 करोड़ रुपये के बराबर था। 1933-34 में इसमें कमी आयी और यह 473 करोड़ रुपये रह गया। कीमतें तो गिर गयी लेकिन टेक्सा में कोई कमी नहीं हुई। 1928-29 में भूमि पर व रूप में कुल राशि 33 करोड़ 10 लाख रुपये थी। 1932-33 में भी यह राशि 33 करोड़ ही बनी रही। 1933-34 के दौरान जना विमानों की अपनी जमीन में हाथ धाना पड़ा। वे करों का भुगतान नहीं कर सके जबकि यह राशि कम हो गयी थी और 30 करोड़ रुपये पर आकर रह गयी थी।

1934 ई० में वगान पटवत जांच समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि वगान में 1920-21 में लेकर 1929-30 तक बिन्नी योग्य उत्पादन का औसत मूल्य 72 करोड़ 40 लाख रुपये था। 1932-33 में यह कम होकर 32 करोड़ 70 लाख रुपये हो गया। दूसरी तरफ वित्तीय दृष्टिकोण से 27 करोड़ 90 लाख रुपये में बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख रुपये तक पहुँच गयी। यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि किसानों की स्वतन्त्र क्रय शक्ति 44 करोड़ 50 लाख रुपये में बढ़कर 34 करोड़ 30 लाख रुपये हो गयी।

और एक तथ्य का बराबर अनन्वय किया गया है कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है।

मनुष्य प्राणों में करों का भुगतान करने के पक्षस्थल 71 430 किसानों की अपनी जमीन में हाथ धाना पड़ा। साथ ही उनमें करों की वसूली के लिए

2,56,284 वारट भी जारी किये गये ।

कृषि-याग्य भूमि का दायरा निरतर कम होता गया क्वाकि अधिकाश व लाग, जिनके हाय म जमीन पहुँची थी खेती-वाडी का काम नही करते थे । यह एक बहुत भयकर पड़्यन था । जमीन के कम हिस्से को खेती के लिए इस्तेमाल करने मे उन लोगो को ज्यादा फायदा दिखायो देता था । इस प्रकार वे उत्पादना की आपूर्ति का नियमित कर सकते थे और निघन जनता को ज्यादा से ज्यादा कज लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे । आम जनता के खून से तैयार समझि की इस मदिरा ने नय भू स्वामिया का मदहोश कर दिया था ।

1933 34 मे कुल 23 करोड 30 लाख एकड जमीन म खेती-वाडी हाती थी । 1934 35 के दम्तावेजा को देखने से पता चलता है कि इस क्षेत्रफल मे कमी आयी और यह 22 करोड 60 लाख एकड हो गया । अनाज के उत्पादन-याग्य भूमि के क्षेत्रफल म 55 लाख 89 हजार एकड की कमी आयी थी । किसानो को पीडा असीम थी । वावजूद इसके किसी ने भी उनके कष्ट पर ध्यान नही दिया ।

बचारे मुकुंदराम । उनका स्वर नक्कारखाने मे तूती की आवाज बनकर रह गया । सच्चाई तो यह थी कि किसी ने उन किसानो के बारे म सोचने का कष्ट ही नही किया ।

1934 ई० से किसानो की आर्थिक अवस्था मे तेजी से गिरावट आयी और व कज के सागर मे डूब गये । वे भूख की भट्टी मे तप रहे थे और भूख को इससे काई सरोकार नही कि वह किसी अमीर आदमी के पास है या गरीब के पास ।

1931 से 1937 के बीच कज की राशि 67 करोड 50 लाख पौंड से बढ कर 134 करोड पौंड हो गयी ।

सबसे बडी विडम्बना तो यह थी कि हमार राष्ट्रीय नेताओ ने आजादी की लडाई पहले ही से शुरू कर रखी थी । व अपने कट्टर दुश्मन अर्थात अंग्रेजो के बारे म खूब चचाएँ करते थे लेकिन कभी भी जमींदारो और महाजना का नाम नही लिया जिन्होने पूरी अथव्यवस्था का दीवालिया बना दिया था ।

अंग्रेज के चेहरे पर एक कुटिल मुसबान थी क्वाकि उसे पता था कि वह हमार समाज मे आत्म विनाश के बीज बो चुका है ।

द्वितीय विश्व-युद्ध की शुरुआत और बमा मे जापानी फौज के पहुँचने के साथ ही वह घटिया चावल भी मिलना बढ हो गया जिसका विदेशो से आयात किया जाता था । इसका वाद ही हमारी कृषि की दुव्यवस्था की तसवीर सबके सामने आयी । इस घटिया चावल का गरीब लोग खरीद सकते थे लेकिन इसका आयात बढ हाने के साथ ही अनाज का भयकर सकट पैदा हुआ । कोमता मे भी तेजी बढि शुरू हुई । उन दिनों के गीता मे पता चलता है कि वहा कितनी



स्थिति थी।

अंग्रेज़ों ने अनाज की सप्लाई की नाई व्यवस्था नहीं की थी। इससे विपरीत सैनिक साज सामान की सप्लाई के काम में तनिक भी बाधा नहीं पड़ी और वस्तुतः किसानों की लूट में अर्जित धन में ही यह काम होता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि दश भयंकर मुद्रास्फीति की चपेट में आ गया। ज़खीरेवाज़ ने इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया और ज़रूरत मुनाफा कमाया।

इस प्रकार 1943 ई० के मानव निर्मित अनाज का ज़म हुआ।

सरकारी आकड़ा के अनुसार अनाज की सप्लाई में 14 लाख टन की कमी हुई। उही आकड़ा के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में 35 लाख लोग मृत्यु का शिकार हुए। अनाज के बाढ़ महामारी का हमला हुआ। इसमें और 12 लाख लोग मारे गए। बड़ी कुशलतापूर्वक उत्पन्न कीये गए इस अनाज में महाना और काला बाज़ारियों का 150 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ।

इस अनाज को हमारे इतिहास विषयक अभिलेखागारों में 'बचाम' के अनाज के रूप में एक छाना मिल गया क्योंकि 1943 का वर्ष और बंगाली कलेंडर का वर्ष 1350 एव ही था। यह अनाज और 1770 का अनाज एक युगांतरकारी घटना थी।

1943 के अनाज ने लगभग 75 प्रतिशत किसानों की कमर तोड़ दी। इनमें से प्रत्येक के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन थी जिससे उस किसान और उसका परिवार के सदस्यों का भरण पोषण के साथ-साथ भी अनाज नहीं पड़ा हो सकता था। यह स्थिति और भी भयंकर हो गयी थी क्योंकि ज़ा भी चावल उपलब्ध था उसे मई माह के आस-पास ज़खीरेवाज़ ने छिना कर रख दिया था। इस दुष्टतापूर्ण कार्य में सरकारी अधिकारी व्यापारी काला-बाज़ारी और जमींदार—सभी शामिल थे।

अनाज के शिकार सबसे पहले गरीब किसान हुए और फिर छोटे किसानों की बारी आयी। इन सबका अपनी जोता से हाथ धाना पड़ा। अप्रैल 1943 से जून 1944—यानी अनाज के एक वर्ष के अँकड़ा को देखने से कई दिलचस्प तथ्यों का पता चलता है। इनसे बंगाल के 15 90 000 किसानों की किस्मत का जानकारी मिलती है

देखी ५ लगे परिवार

जिन्हें अपनी जमीन से हाथ धाना पड़ा	2,60,000
जिन्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा बचना पड़ा	6,60,000
जिन्हें अपनी फसल गिरवी रखनी पड़ी	6 70 000

अनाज के दौरान 7 10 000 एकड़ जमीन पर मित्त्रियत की फरवदल हुई। इसमें से केवल 20,000 एकड़ जमीन जमींदारों और महाजनों के हाथ

लगी। लगभग 4,20,000 एकड़ ऐसे लोगों के हाथ में पहुँची जो खेती नहीं कर सकते थे। साथ ही किसानों पर कृषि का बोझ अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गया।

अनुमान के अनुसार 1943 में कृषि में लगे लगभग 43 प्रतिशत परिवार कृषि में डूबे हुए थे। 1944 में यह संख्या 66 प्रतिशत तक पहुँच गयी। इससे पहले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद देश में कभी नहीं देखने में आयी थी। हम उन्हें अब भी किसान ही कहेंगे क्योंकि वे ही ऐसे लोग थे जो जानते थे कि किस प्रकार कृषि की राशि कितनी मामूली-सी थी। पर इस मामूली-सी किसानों पर कृषि की राशि कितनी मामूली-सी थी। पर इस मामूली-सी रकम के एवज में वे गुलाम बन जाते थे और इस तरह के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं

### उदाहरण—1

एक किसान ने कभी दो मन चावल उधार लिया जिसे वह लौटा नहीं सका और उसे बंधुआ मजदूर बनना पड़ा।

### उदाहरण—2

एक किसान 'क' के परदादा ने अपने भू-स्वामी से 17 सेंर जमीन उधार लिया था। परदादा और उसके बेटे जयन्त 'क' के बाप का बंधुआ मजदूर के रूप में ज़िंदगी बिताती पड़ी। 'क' को भी अपने मालिक का गुलाम होकर रहना पड़ा। 'क' के परिवार ने 1978 तक भू-स्वामी को 2600 रुपये का भुगतान किया था। भू-स्वामी का कहना था कि अभी 300 रुपये उनकी तरफ बकाया पड़े हैं।

### उदाहरण—3

उदयपुर में जीजा नामक एक अनाथ का उसके चाचा ने 80 रुपये का कर्ज चुकता न करने के कारण ज़मींदार को बेच दिया। अब जीजा तब तक गुलाम बना रहेगा जब तक वह मर नहीं जाता।

### उदाहरण—4

मध्य प्रदेश में सनना में, काबू के चाचा ने उसे 150 रुपये में बेच दिया।

### उदाहरण—5

तमिज़नाडु के दक्षिणी आरकाट ज़िले में अरमुगल के पिता ने 100 रुपये चुकता न करने के कारण अपने बेटे को ज़मींदार के हाथों बेच दिया। हम उस नौ आन का भी नहीं भूलना चाहिए जिसने किसी का जीवन भर के

36 भारत में वधुजा मजदूर

एक बघुआ मजदूर अपने मालिक से क्या पाता है ? मामूली मा वेतन और थोड़ा खाना । अगर वह चाहता मालिक उसे आजादी द सकता है । लेकिन क्या वह कभी ऐसा चाहता है ?

वह कभी ऐसा चाहता है ?  
 वधुआ मजदूर कभी गांव छोड़कर नहीं जा सकता । अपने धर्म और अपने  
 उत्पादन को वह छुड़ कभी नहीं दे सकता । 1921 ई० में बम्बई जनगणना  
 पूरे परिवार के साथ गुलाम बना रहता है । 1921 ई० में बम्बई जनगणना  
 आयोग ने गुजरात के हाली लोगों के बारे में एक रिपोर्ट दी थी । जमरीबा म गह  
 पुष्ट से पूर्व के बागाना में काम करने वाले गुलामों की तरह ही हाली बाग मा  
 पूरी तरह गुलाम की जिंदगी बिताते थे ।

( 3 )

( 3 )

( 3 )

1931 ई० में भारत में 30 लाख बघुआ मजदूर थे। खेती बाड़ी से सम्बन्धित कुल आवदी का यह 3 प्रतिशत हिस्सा था। भूमिहीन किसानों की सख्या के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है कि आजादी के बाद बघुआ मजदूरों की सख्या में किस तरह और क्या वृद्धि हुई ?

सदभ ७५ १९३१

- 1 जून 1931
1. खतिहर मजदूरों की कुल संख्या—4 करोड़ 20 लाख
  2. बंधुआ मजदूरों की संख्या—30 लाख
  3. मामूली वेतन पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या—3 करोड़ 50 लाख
  4. दैनिक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या—40 लाख
1. मुवायन 24 का प्रतिशत 37.8
- 1891 में यह प्रतिशत 13
- खतिहर मजदूर मालिकों और महाजनों में उधार लेते—यह तो स्वाभाविक है। उस प्रकार यह भी स्वाभाविक है। यह भी बहुत स्वाभाविक है। यह घणित कारोबार जारी रहेगा यह भी स्वाभाविक है।
- दूसरे प्रकार प्राथमिकता की भावना हमारे ऊपर दस तरह काम करती है। हमें तत्वान जिस चीज को जरूरत है वह है रखा टेलिविजन। बंधुआ मजदूर का बचान जमा शरीर रंगीन दिखाया जाय तो थान बेहतर लगेगा और धूप में जलदानी पकी भजन में भरे गाता को पट्टभूमि हो तो क्या करने।

चेतिहर मजदूरों की एक विशाल फौज है। गरीब किसानों का साथ भी कम नहीं है। 1931 में उनकी संख्या 3 करोड़ 70 लाख थी।

आज की वाकाल 33 3 प्रतिशत हिस्सा खेती बाड़ी में लगा था। जमीन मालिक थी। इसलिए उह जमींदारों और महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। वसी विडम्बना है, जेर पर बकर की निर्भरता। खानी मामूली आय से वे बज चुकना नहीं कर पाते थे। व जमीन में हाथ धोकर माघाण मजदूर बन गये। लेकिन काम भी पर्याप्त नहीं था। उनका काम काम की गारंटी नहीं थी और आज भी नहीं है। 1931 में 4 करोड़ 20 लाख चेतिहर मजदूरों में से 3 करोड़ 50 लाख बेरोजगार थे। एक बहुत बड़े हिस्से को वागान दर से काफी कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था।

दैनिक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों का एक हिस्सा, जिनकी मागद 40 लाख थी, चाय बाँपी और रबर बागानों में काम करने लगे। 1929 में इस धेणी में 10 71 000 मजदूर थे। आधे से अधिक लगभग 5 57 487 व्यक्ति जमम के चाय बागानों में नग हुए थे। बागानों के बागानों में 1 96 899 और मद्रास के विभिन्न बागानों में 1 02,700 मजदूर काम कर रहे थे। 1946 में ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में यह संख्या बढ़ कर 10 91 461 हो गयी थी।

चाय और काफी बागानों में काम करने वाले मजदूरों का मागमान के लिए स्वतंत्र थे। वास्तविक अर्थों में उनके हिस्से में गुनामी ही थी। उह काम के समय मालिक उनसे स्वका पर अगूठे के निशान लगवाता था। ठकेदार मजदूरों का तागब देकर बागानों में काम दिलाने ल जात थे और फिर उह वधुआ बना लेत थे। उनकी दुख भरी कहानियाँ दसजीवनी और 'न बागानी में प्रकाशित होती थी। द्वारावाताय गागुलों ने इन अखवागों का कई प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट भेजी थी। यूरोपिया द्वारा महिना मजदूरों पर किये गये अत्याचारों की कहानी कुग्रात 'नक बाड' के जरिए काफी प्रचारित हुई। माग में इस बाड का विवरण 'भारत में माग की हत्या' शीर्षक में प्रकाशित हुआ।

चेतिहर मजदूरों में से अधिकांश लोग आदिवासियों और हरिजनों के बीच में आते थे। 1930 में की गयी इनकी गणना इस प्रकार थी

मयुवन प्रांत	1 करोड़ 20 लाख
बागाल	1 करोड़ 15 लाख
मध्य प्रांत	33 लाख
मद्रास	65 लाख
बिहार और उड़ीसा	50 लाख
पंजाब	28 लाख

अमम	10 लाख
रम्बई	15 लाख
सतिहर आगली के मुनायन उनका प्रतिगत दम प्रकार था	
रम्बई	57 प्रतिगत
समुक्त प्रात	21 8 प्रतिगत
बगाल	33 प्रतिगत
मध्य प्रात	52 प्रतिगत
मद्रास	54 प्रतिगत
विहार और उड़ीसा	35 प्रतिगत
पजाब	14 5 प्रतिगत
अमम	25 प्रतिगत

1931 म सतिहर मजदूरों की मर्या सती-याही म लगी जागली का 70 प्रतिगत थी। जो आदिवासी नहीं थे वे मुनयतया अनुमूर्तिन जाति के तथा गरीब मुसलमान थे। मवण हिंदू तथा रईस मुसलमान पढ़े लिखे थे। उह टकम कलकटरी तथा जमीन के बंदोस्त से मवधिन आय नीकरिया म लगाया गया था। उह भली भाँति पता था कि अपन किसानों से जमीन हड़पने व लिए कानून की धमिया का कैसे इस्तेमाल किया जाये। बंदा की गयी जमीन को भीरा म बोन दिया जाता था। इस प्रकार जाति और वग ता मूम मंद धीरे धीरे एक हो गया। एक उदाहरण प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश म जमींदारी प्रथा के समाप्त किए जाने से पूव पुरानी कर प्रणाली के आधार पर जमीन को 37 खेता म बाँटा गया था। पहले सेहाना सरदार नाम से जात एक गुप के प्रमुख नेता के ऊपर कर वसूलने की जिम्मेदारी थी। उनके मातहत अनेक सहायक सेहाना होते थे। वे अपने प्रमुख के अधीन रहकर कर की वसूली और जमीन व निर्धारण का काम करत थे। वे सभी राजपूत और ब्राह्मण थे। वे अनुमूर्तिन जाति के उन लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे जो वग देने से असफल होते थे। जब्त की गयी सारी जमीन को अपने वग के लोगो के बीच बाँट दत थे। इस प्रकार अधिवाश जमीन पर राजपूत और ब्राह्मणों की मित्वयत कायम हो गयी।

पूरे साल के लिए सतिहर मजदूरों व पास काम नहीं हाता है। यहाँ तक कि सोहन शुरू होने पर भी सभी का काम नहीं मिलता। कुछ का इस शत पर काम मिलता है कि वेतन व रूप म वे बचस खाना पा सनेगे। कुछ को बज लेन कारण वधुआ मजदूर बना लिया जाता है। उनके पास कोई और चारा नहीं है वधुआ मजदूरों का कम-से कम खाना तो मिलता था—यह बात जलन है कि क्या खायेगे।

जहाँ तक खाने की बात है, इसका विवरण बहुत घृणाजनक है। मध्य भारत में हलवाहा को खाने का वही मिलता है जो उनके घमण्डरायण हिन्दू मालिक पवित्र समझते हैं। वे अपने मजदूरों को वह अनाज देते हैं जो गाय और भैंस पचाने के कारण गोबर के साथ बाहर निकाल दी जाती है। इस अनाज का धाया जाता है और फिर हलवाहा द्वारा खाया जाता है। यह कोई कल्पित बात नहीं है और बहुत पुरानी बात भी नहीं है।

इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य तक बधुआ मजदूरों की संख्या बढ़त जाने का कारण साम्राज्यवादी भूमि-बंदोबस्त प्रणाली है।

बधुआ मजदूर का मायला आज भी एकदम जीवन और मशक्कत है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ दश में जब किसी परिवारजना का उद्घाटन किया जा रहा होता है — किसी जंगल में दश की किसी मुलायम या कठोर धरती के हिस्से पर कोई अभाग्य परिवार चुनचाप गुलामी की जमीन में बसता जा रहा होता है। यह रोग काफी पुराना है पर आज भी काफी मजबूत रोग है।

अलग अलग स्थानों में बधुआ मजदूरों का अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वे गुजरात में हाली, दक्षिण मद्रास में इक्षवा, चेन्नई में पुली और होलिया मद्रास में पूर्वी नदी घाटी में परियाल तमिलनाडु में पनियल और पयिराम, आंध्र प्रदेश में गम्मिगुल्ला, हैदराबाद में भगेला, अयोध्या में सनवक, मध्य भारत में हरवाहा, बिहार में सकिया, नमिया, सवकिया और जमौर के नाम से जाने जाते हैं। उड़ीसा में उन्हें माटी घरमसिया, नागा भुविया और डडा भुविया कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर में इहे माझी, पन और लमरी कहा जाता है। करल में बगार और राजस्थान में सगरी नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में बेट या बगार है। उत्तर प्रदेश में मट, खडिन आर मजिमत है। सरकारी तौर पर पश्चिम बंगाल में एक भी बधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन भुतुआ, बारोमनिया, महिंदर और बागल लोग बधुआ मजदूर के सिवा और कुछ नहीं हैं।

कर्नाटक में ये जुथा नाम से हैं।

इसके अलावा और भी कुछ हैं जिनके बीच संयोग जनर नहीं है।

हम बाद में उस पर विचार करेंगे।



15 जून 1947 के अविस्मरणीय दिन से पहले के 45 वर्षों में कृषि के काम जान बानी उम्मीद में 148 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि चावादी में 37.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में केवल 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। धुक्ति उत्पादन में वृद्धि आवादी में वृद्धि की तुलना में कम थी, प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादकता में गिरावट आयी। हम बिरासन के रूप में एक ही कृषि-अप-व्यवस्था मिली थी और यह बड़ी अफसोस की बात थी, क्योंकि 1951 की जनगणना में जानकारी दी गयी थी कि आवादी का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है।

आजादी के 30 वर्ष से भी अधिक समय और कुछेक पाँच-वर्षीय योजनाओं के बाद भी हम आज भी कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का दावा नहीं कर सकते। जनसंख्या में वृद्धि और बढ़ती कीमतों ने सारी प्रयत्न को बराबर कर दिया है। अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों ने भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया और साथ ही इन्हें एमो भीमा में बँद कर दिया जिससे य अतिरिक्त नहीं कर सकते। इन स्थितियों का असर हमारी कृषि पर भी पड़ा और इसमें कोई शक नहीं है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि आजादी के बाद भी इन बातों को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गयी। यूरोप का इतिहास हमें बताता है कि जब तक कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त पैदावार नहीं होती तब तक यह पसल पर औद्योगीकरण के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषि का ठोस आधार बनाय बिना खाद्य पदार्थों और बुनियादी वस्त्रों मास की सप्लाई भी संभव नहीं है। तबों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को पुरा करने के लिए वे अतिरिक्त नहीं है।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के दौरान सिखाए गए मूल्य मात मान ली गयी थी कि सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि को बढ़ावा दी जायेगी। कृषि की ओर से लापरवाही बरतना संभव नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की ओर वस्त्रों मास के अभाव में औद्योगीकरण का प्रयास धरासायी हो जाता।

इसलिए प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कृषि का ही रास्ता अलग था।



ट्रिप्लि एव ग्रामीण विभाग के लिए 35 कराट 40 लाख रुपये निर्धारित किए गए। कुल बजट का यह 14.9 प्रतिशत हिस्सा था। गिरार्ड और रिजनी के लिए 64 कराट 70 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी जो बजट का 27.2 प्रतिशत थी।

दूसरी योजना में हमारी प्राथमिकता बढ़ाने ली, जबकि गिरार्ड का उचित समय नहीं था। ट्रिप्लि और ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का 11.8 प्रतिशत तथा उत्पन्न एवं ग्रामीण विकास के लिए 18.5 प्रतिशत अंश निर्धारित किया गया।

दूसरी योजना में ट्रिप्लि के क्षेत्र में उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। तीसरी योजना में भी उत्पादन पूरा निर्धारित लक्ष्य में (जो 10 में 10.5 कराट टन था) बहुत कम रहा।

1952-53 में 1964-65 तक के चार वर्षों के आँकड़े में—जिन खाद्य मंत्रालय ने प्रकाशित किया है—पता चलता है कि ट्रिप्लि के क्षेत्र में सम्मिलित वार्षिक विकास दर केवल 3 प्रतिशत रही। इसमें से नीचे-वाष्प भूमि में 1.21 प्रतिशत तथा उत्पादन में 1.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुरू की तोना पंच-वर्षीय योजनाओं के दौरान ट्रिप्लि उत्पादन के परम्परेष कुल लाभ 2.1 प्रतिशत हुआ। प्रथम योजना के दौरान इसमें 1.2 प्रतिशत और द्वितीय योजना के दौरान 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के समाप्त होने तक इसमें 2 प्रतिशत का ह्रास हो चुका था।

चौथी और पाँचवी योजना के अंत तक यह लाभ राका नहीं जा सका। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा घोषी गयी पुरानी साम्राज्यवादी भूमि प्रणाली में कोई तबलीनी नहीं की गयी और इस कारण को हमेशा नजरअंदाज किया गया। जब तक यह पूरा नहीं होता तब तक न तो उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और न किसानों की दशा में कोई सुधार किया जा सकता है।

जब हम अर्थ-व्यवस्था के कृषीय क्षेत्र में उत्पादकता और विकास की बात करते हैं तो निश्चय ही हम किसानों के जीवन स्तर को सही अर्थों में बेहतर बनाने की दुर्ग्राह्य अवधारणा को भी इसमें शामिल करते हैं। इस अवधारणा को वे लोग नहीं पसंद करते जो आज भी दमन की पुरानी परंपरा निम्नान में पूर्ण ताकत के साथ लगे हुए हैं।

प्रोफेसर कोमाम्बी ने ठीक ही कहा है कि यदि आधुनिक भारत के गाँवों की यात्रा की जाय तो उन वस्तुओं—मसलन पुराने उपकरण, बलगाड़ियाँ, सापड़े और भूख से पीड़ित चेहरे—को देखा जा सकता है जो ईसा पूर्व 150 और 200 ईसवी के कृषि साम्राज्य की मूर्तियों की शक्ल में अमर हो चुकी हैं।

किसानों की मदद की गयी लेकिन हमारे किसान आज भी उमी तरह की

जिंदगी गुजार रह है। निश्चय ही सामाजिक अत्याय का यह एक जबरदस्त उदाहरण है।

आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी कांग्रेस शासन न किसानों की पीड़ा पर कई बार विचार किया। दिसम्बर 1947 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष न कुमारप्पा समिति का गठन किया जिसका काम भूमि-सुधार के मामलों की छानबीन करना था और इस सर्वेक्षण के बाद उसे उपयुक्त सिफारिशें करनी थीं। जुलाई 1949 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में जब तक पूरी तरह सुधार नहीं किया जाता तब तक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। ऐसा करने के लिए त्रिचोलिया का ख़तम करना होगा और जमीन की किसानों के हाथ में सौंपना होगा। इसके साथ ही विधवाया, नाबालिगों और अपंग व्यक्तियों को छोड़कर अब किसी भी मामले में भूमि पट्टेदारी की प्रथा पर रोक लगानी होगी। इसमें यह भी उल्लेख किया था कि भूमिहीन किसानों को कुछ अधिकार भी देन होंगे। एक सुझाव दिया गया था कि जा लाग लगातार छह वर्षों से किसी जमीन का जोत-बो रह रहा वह अपने आप ही उस जमीन पर स्वामित्व कायम करने का अधिकार मिल जाना चाहिए। अब मामलों में जा असली मालिक है वे यदि चाहें तो जमीन पर अपने दावे फिर कायम कर सकते हैं वरन् इसे वे एक निर्धारित समय में पूरा कर लें। रिपोर्ट में अनेक ऐतिहासिक उपायों को भी शामिल किया गया था ताकि जमींदार लोग कोई अनुचित लाभ न उठा लें

(क) जिन लोगों ने न्यूनतम परिमाण में भी शारीरिक श्रम किया है और वेत जोतन-बोन में खुद भी हिस्सा लिया है वह वास्तविक किसान माना जायेगा।

(ख) जमीन के असली मालिक अपने दावे जमीन के उसी हिस्से पर कर सकते हैं जो उनकी जोत को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बना सके।

रिपोर्ट में उल्लिखित अब सिफारिशों में कहा गया था कि किसान काश्त-कारों का एरिया लैंड ट्रिव्यूनल द्वारा निर्धारित मूल्य पर जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही जमीन से बदलल किये जाने के मिलसिले को भी फौरन रोक दिया जाना चाहिए। सभी वर्गों के किसानों को ऊँच करा तथा गर-कानूनी मामलों से हिफाजत देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। करों का निर्धारण नकद के रूप में किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित दरें भी तय कर देनी चाहिए। अब में खेत की एक सीमा निश्चित करने की भी सिफारिश की गयी थी जिसे अधिकतम उस जमीन के क्षेत्रफल का तीन गुना माना गया था जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ जमीन थी।

इन सिफारिशों में तीन तरह की गतिविधियों का शामिल किया गया था—यक्तिगत खेती, सहकारी खेती और सरकारी खेती। कृषि याग्य बनायी गयी

भूमि के बारे में प्रस्तुत सुझावा मंजूर हो गए थे कि ऐसे मामलों में भूमिहीन मजदूरों का वधे सेतु प्रदान का अवसर दिया जाना चाहिए भले ही इस काम में लाभ हो या नुकसान।

इस सुधार समिति ने एक ऐसी कृषि प्रणाली के बारे में सोचा था जिसमें किसानों का नुकसान होगा। जमीनहीन बड़ी लाभोमुख पृष्ठभूमि के मुकाबले मालिकों और मजदूरों के बीच संपन्न कायम करने की कोई वांछित नहीं थी।

यदि किसानों को जमीनीय-यानी रही—इसका अस्तित्व कागजात तक ही सीमित रहा। प्रथम पंच वर्षीय योजना में सरकारी तौर पर तयार की गयी भूमि नीति ने समिति द्वारा पेश किया गया सुझाव के मुख्य पहलुओं की उपस्था की। इसका एक पहलू हम किसानों की परिभाषा में देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर थम का एक 'यूनितम' परिमाण खच करता है, उसी अवस्था में उसे किसान माना जा सकता है। जहाँ तक जमीन की मिल्किट का सवाल है इसमें खेती करने वाले मालिकों और खेती न करने वाले मालिकों के बीच एक फर्क दिखाया। खेती के काम में लग किसान जमीन पर सीधे अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि खुद खेती न करने वाले मालिक केवल उसी जमीन पर दावा कर सकते हैं जो किसानों की अधिक जोता की सीमा को पार करती थी। यदि इस मिश्रण पर भरोसा किया गया होता तो जमीन में बेदखल किया जान की अनेक घटनाएँ राकी जा सकती थीं।

इस आवश्यक अंतर को कभी निर्धारित नहीं किया गया। जमीन पर फिर से दावे करने के मामलों में उन लोगों का वरीयता दी गयी जो खुद खेती नहीं करते थे और इसके फलस्वरूप संचयित मेहनत करने वाले बग को पूरी तरह से आर्थिक रूप से बेदखल कर लिया गया। यथायथ में बेदखली की घटनाएँ बढ़ती गयी और जमीन की मिल्किट बढ़ लागे के हाथों में सिमटती चली गयी। मेहनतकश किसानों का पक्ष लेने वाले मामले बहुत कम थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में दावों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता गया और आर्थिक विषमता भी बढ़ती गयी।

कानूनी से सम्बंधित नीतियाँ भी समान रही थीं। सुधार समिति विधवाओं, नाबालिगों और अपंग लोगों के मामलों को छोड़कर पट्टे पर जमीन देने के विचारों की। फिर भी पहली पंच वर्षीय योजना में जो अत्यंत विधान था उसमें संपूर्ण मामलों को उन लोगों के पक्ष में कर दिया जिन्होंने जमीन को पट्टे पर देने की नीति अपनायी थी।

ऐसे लोगों को इज्जतदार कहा जाता था। साथ ही उन लोगों के बीच कोई भेद नहीं किया गया जो छोटी जमीन के मालिक थे और अनिश्चित आय के लिए

महाराज जात थे तथा जा रही जात के मातिव थे ॥ २२२ ॥ २२२ ॥  
 ५। इस बारण ज्योदार-नाम्नवार सम्बन्ध थे ॥ २२२ ॥ २२२ ॥  
 जारी रहा ।

वर्ष मामला में करा की अधिनम दर अभी भी फसल के पचास प्रतिशत हिस्से से अधिक है। उड़ीसा में एक कानून के जरिए यह घोषित किया गया है कि फसल का 25 प्रतिशत हिस्सा ही कर के रूप में लिया जाएगा, फिर भी पुराना कानून अपनी पूरी ताकत के साथ बरकरार है और किसानों में फसल का 50 प्रतिशत हिस्सा वसूला जाता है। अपनी योजनाओं के दौरान हमने देखा कि पचास में जमीन में वेदव्यन किये जान की घटनाएँ अभी भी तेजी पर हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में बगदारा को किसान न किसी बहाने जमीन से छेड़ दिया जाता है। 1948-51 के बीच सरक्षित बाग़दारों की संख्या 17 लाख में घटकर 13.6 लाख हो गयी। इनके अधीन आ भूमि की यह भी घटकर 18 प्रतिशत रह गयी। आंध्र प्रदेश सरकार की एक जांच समिति ने पता किया कि 1951 और 1955 के बीच सरक्षित बाग़दारों और उनकी जातों में कमी आयी और यह प्रमश 50 तथा 59 प्रतिशत हो गयी। समिति के अनुसार कानून में निहित खामी न होने अप्रभावकारी बना दिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के तयार किये जाने के बावजूद खेतिहर मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जन गणना रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गये हैं वे पहली बार सही जानकारी का सामना करा रहे हैं।

1951 में खेतिहर मजदूरों की संख्या 7,15,766 थी। 1961 में यह संख्या 3,15,19,411 और 1979 में 4,73,04,808 तक पहुँच गयी। दूसरी तरफ़ किसानों की संख्या 9,95,28,313 थी। 1971 में यह घटकर 7,87,06,896 हो गयी। कहना न होगा कि इस अवधि के दौरान मजदूरों की हालत में और भी गिरावट आयी।

1951-52 और 1956-57 की पहली और दूसरी खेतिहर मजदूर जांच समिति की रिपोर्टों में काफी ब्योरा मिलता है। खेतिहर मजदूरों की शिनायत करने के लिए दोनों समितियाँ अलग अलग पमान का इस्तेमाल किया है। पहली समिति के अनुसार जिन लोगों ने खेती में अपने श्रम का आधा हिस्सा दिया था उन्हें खेतिहर मजदूर कहा गया। दूसरी समिति का कहना था कि जिन लोगों ने अपनी कुल आय का आधा हिस्सा खेती-बाड़ी के जरिए अर्जित किया था उन्हें खेतिहर मजदूर कहा जाना चाहिए। इसमें काफी भ्रम फैला।

इसका कारण यह था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हर बार फसल की कटाई के समय किसी मजदूर को काम मिल ही जायेगा और वह भी प्रतिदिन। यदि उसे काम मिल भी जाता है तो मजदूरी के रूप में जो भी राशि उसे प्राप्त होगी वह बड़े किसानों और जेतनारा की मर्जी पर निर्भर है (वैश्व, 'यूनितेड वलन के सम्बन्ध में एक कानून का')। फलस्वरूप अपना जीवन-यापन के

लिए मजदूरों को दूमेरे काम भी करन पड़त थ (शायद गहरी सेवा म भीय मानी पड़ती थी)। इसलिए सेनी-बाड़ी म लगाय गये समय के आधार पर अब्बा इसके जरिए अर्जित आम के आधार पर सेतिहर मजदूरों की सख्या निर्धारित करना उतत हागा।

इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1951-52 और 1956-57 के बीच मजदूरों की मटी का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। पुरुष-मजदूरों की सख्या म 13 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और महिला-मजदूरों की सख्या म यह वृद्धि 51 प्रतिशत रही। महिला-मजदूरों की सख्या म अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि इनका दो जान वाली मजदूरी कम थी। दूसरी तरफ, पुरुषों और महिलाओं की मजदूर की दरों म कमश 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की कमी आई। फलस्वरूप प्रत्येक परिवार की आय म 2.2 प्रतिशत की कमी हा गयी बार कज म 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कज से लदे परिवारों की मख्या 44.5 प्रतिशत म बढ़कर 63.9 प्रतिशत हो गयी।

1950-51 म कज की कुल राशि 80 करोड रुपये थी जो 1956-57 म बढ़कर 143 करोड रुपये हो गयी। 1960-61 म दूसरी योजना के अंत म यह राशि 160 करोड रुपये तक पहुँच गयी।

भूमि सुधार के प्रारम्भिक ढाँच के रूप में प्रथम योजना के दौरान ही 1951 म जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1954 आते जाते विचौलिया का अस्तित्व कम से-कम बागज पना म समाप्त हो गया। इसके पीछे मुख्य इरादा सरकार और किसानों के बीच लेन-देन की सीधी व्यवस्था कायम करना था। ब्रानून म इतनी छामिया थी कि भूतपूर्व जमींदारों का अस्तित्व भी बना रहा। पहल की ही तरह वग युद्ध जारी रह। केवल नाम बदल गये। जिन्ह पहले सामंती भू-स्वामी और जमींदार के नाम से जाना जाता था व अब भूतपूर्व जमींदार, जेतदार और धनी किसान बन गये थे लेकिन छोट किसानों, बगदारा और सेतिहर मजदूरों की पुरानी पहचान बनी रही। धनी किसानों के शक्तिशाली गुट का 'भारतीय कुलक' भी कहा जा सकता है। आकड़ा स पता चलता है कि पहली योजना के दौरान अनेक छोट किसानों और बगदारों को उनकी जमीन से बंखन किया गया और यह जमाय का ऐसा उन्हाहण हुआ जो साल के इतिहास म कभी देखन का नहीं मिला।

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार करें। जमींदारी प्रथा के रातम होने के बाद भी बगदारा और बटाईदारों को जो 25 प्रतिशत से 46 प्रतिशत जमीन जातत थ, किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। असनी फायदा भू-स्वामी को मिला जो सेनी-बाड़ी करने वाली जावादी म अल्प सङ्ख्यक की रिपोर्ट में 1956 म बगदारा के हितों की रक्षा करने के प्रयास विफल हो गये।

कानून बना जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 25 एकड़ में अधिक जमीन नहीं होगी। यह कानून एक्ट में तब तक हा गया, क्योंकि बड़े भू-स्वामियों ने अलग-अलग नामों से जमीन पर अपना कब्जा बाँट रखा। बगदारा न महसूस किया कि सरकार और कानून में उनकी रक्षा नहीं हो सकती। दरअसल, हर समय जमीन में बदलाव कराया जाना का गतरा तलवार की तरह मर पर लटक रहा था। कितने परिवारों का बदलाव कराया गया यह अब इतिहास का विषय बन गया है।

इस प्रकार जमीन में बदलाव किये जाने के बाद छोटे किसानों और बगदारों ने स्वतंत्र भारत में खेतिहर मजदूरों की रतार में शामिल होना बेहतर समझा। दूसरी तरफ के मालिकों और महाजनों से ज्यादा से ज्यादा कच्चा लेन लग ताकि उनकी और उनके परिवारों का गुच चल सके। उनकी आय और कच्चा की मात्रा के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है।

## (2)

1967-68 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ग्रामीण जावादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे रहता है। इस रेखा से नीचे और सबसे नीचे खेतिहर मजदूर आते हैं। येशक यह कहा जा सकता है कि वे जीवित थे क्योंकि वे उस समय तक मर नहीं सके थे। 1972 में बाँकुडा जिले के दो गाँवों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 37 पैसे थी। तत्कालीन श्रम आयुक्त न दस पर टिप्पणी की थी कि ये लोग कैसे जीवित हैं, यह एक चमत्कार है। अब सभी राज्यों में भी मजदूरों के मामले में यह बात सच थी।

आजादी के बाद सरकार ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के सिलसिले में अनेक कानून बनाये। लेकिन इन कानूनों को कभी भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। कानून में जनक स्वामियों के कारण या तो इन्हें अप्रभावकारी बना दिया गया था या भू-स्वामियों के हाथ में ये हथियार बन रहे गये थे। कागज पर मजदूरी में कुछ वृद्धि दिखायी दी गयी थी, लेकिन इस वृद्धि की कीमत में हड़बड़ोनी में नाकाम कर दिया। जिन मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आंदोलन किया उन्हें हटा दिया गया। भू-स्वामियों ने कम मजदूरी पर बाहर से बुलाकर मजदूरों का भर्ती किया। स्थानीय और बाहरी मजदूरों में कई बार संघर्ष हुए लेकिन इसमें भू-स्वामियों को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इस तरह के अनुभवों से मजदूरों ने निश्चय होकर अपने घर-बार छोड़ दिए और दूसरी जगह चले गये।

खेतिहर मजदूरों के लिए काम मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। औसतन 15 प्रतिशत मजदूरों के लिए काम नहीं मिलता। जिन्हें मिलता भी है वे साल

के चारहा महीन काम पर नहीं होते। सेता में जो काम करते हैं उन्हें वष में लगभग 150 दिन मजदूरी सहित काम मिलता है। सिंचाई वाले सेता में काम करने वाले मजदूरों को केवल वान और वाटन के समय ही काम मिलता है। साल के बाकी दिना में वे बेरोजगार रहते हैं। 1950-51 में इस तरह के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 207 पैसे थी। 1956-57 में 230 पैसे और 1964-65 में 297 पैसे हो गयी। सेंट्रल लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 14 वर्षों में खेतिहर मजदूरों की आय में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन वास्तविक आय में पांच प्रतिशत की गिरावट आयी।

कच्चा का सहारा लेना पड़ता है। छोटे किसानों और बगदारा की जरूरतों में कच्चा का फल है। उनकी कच्चादारी मुख्य रूप से इसलिए बढ़ती है क्योंकि उन्हें उपकरण बीज और रासायनिक खाद खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा फसल तयार होने तक खान के लिए भी उन्हें खर्च करना पड़ता है और साथ ही एस सामाजिक दायित्व को भी पूरा करना पड़ता है जिसके प्रति धनी या गरीब कोई भी उपेक्षा नहीं करते सकते। एक बार लिया गया कच्चा पीछी दर-पीछी दर पर चढ़ा रहता है। उनकी निरक्षरता का फायदा महाजन लोग उठाते हैं और कच्चा रूप में लिखी गयी राशि को बढ़ाते रहते हैं। कच्चा की राशि का चाहे जितना भी हिस्सा चुकता किया जाये मूल राशि में कोई कमी नहीं आती और चन्दा ब्याज की दर से इसमें वृद्धि होती रहती है।

भारत सरकार की 1961-62 की रिपोर्ट में बताया गया है कि खेती करने वाले प्रत्येक दस परिवारों में से छह परिवार कच्चा से ग्रस्त थे। कच्चे रूप में ली गयी कुल राशि में से सहकारी संस्थाओं और यकोन आठ प्रतिशत से भी कम दिया था। शेष राशि गांव के सूदखोर महाजनों से प्राप्त हुई थी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण कच्चादारी में 1961 और 1971 के बीच दुगुनी वृद्धि हुई। इसकी आधी राशि खेती बाड़ी के लिए किसानों द्वारा ली गयी थी। इस कच्चे के चालीस प्रतिशत हिस्से पर ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल ऋण 3,752 करोड़ रुपये था। यह राशि नकद के रूप में दी गयी थी और इसके बदले 96 करोड़ मूल्य के सामान उधार लिये गये थे। इसमें से खेतिहर परिवारों ने (श्रमिक वर्ग का 72 प्रतिशत हिस्सा) 3,374 करोड़ रुपये लिये थे जो कुल राशि का 88 प्रतिशत था। खेतिहर मजदूरों ने 181 करोड़ रुपये या 4.7 प्रतिशत की राशि ली। कारीगरों ने 54 करोड़ या 1.4 प्रतिशत और गैर कृषकों ने 239 करोड़ या 6.2 प्रतिशत की राशि ली।

1975-76 में लगभग सभी राज्यों में तरह-तरह के तरीकों से ग्रामीण कच्चा





रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कच्चे की आध से अधिक राशि महाजन द्वारा दी गयी थी जबकि वहाँ सरकारी समितियाँ और ग्रामीण बँका की सुविधाएँ उपलब्ध थी। सरकार की सारी एजेंसियाँ महानगरी के जाल से गरीब किसानों और मजदूरों की रक्षा करने में विफल हुई थी। यह विफलता अवश्यभावी थी, क्योंकि जिन लोगों को इसका शिकार बनाया गया था वे गरीब, असहाय और असंगठित थे। सरकारी कानूनान न केवल सुविधा सम्पन्न लोगों की ही मदद की। आसान दरा पर थोड़े समय के लिए कच्चे देने वाली मृग्य समितियाँ के कार्यों की जाँच करें तो पता चलेगा कि इन पर धनी महाजन, धनी किसान और उनके एजेंटों का ही नियंत्रण है। इसमें उपलब्ध राशि वे अपनी जोत बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं अथवा व्याज की ऊँची दरा पर (24 से 120 प्रतिशत प्रतिवर्ष) इसी राशि को वे गरीब किसानों का दे देते हैं।

राज्य व्यापार निगम की कहानी भी उतनी ही दुःखद है।

इस निगम की स्थापना का उद्देश्य यह घोषित किया गया था कि इसके जरिए मुनाफाखोर विचौलियों को हटा दिया जायेगा। लेकिन इसमें उही तत्वा की मदद से काम शुरू किया। ऐसे लोग पहले की तुलना में और भी ज्यादा प्रभावशाली बन गये और किसानों पर अपना दमन तेज करने का उह और भी ज्यादा अवसर मिल गया। इन सबके बावजूद सरकारी कागज पत्रों में यही दिखाया गया कि हर योजना के दौरान गरीब किसानों और मजदूरों को लाभ मिलता रहा है और महाजनों से उनकी रक्षा की जाती रही है। यह सारा इतना ही एक धोखा था और जनता को ठगने का नया तरीका था।

घटनाओं का नाम कुछ ऐसा रहा कि छोटे किसान अनिवार्य रूप से भयंकर कच्चे से दबते चले गये और अपनी पुश्तैनी जमीना से बंदखल कर दिये जाने का बाद वे खेतिहर मजदूर बन गये। साथ ही इसी प्रक्रिया के जरिए इन मजदूरों का बंधुआ मजदूर बना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि गुलामी कराना गैर कानूनी है लेकिन व्यवहार में इसे हमेशा झुठलाया गया है। जब तक भूमि प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक गुलामी की प्रथा को रोक नहीं जा सकता, भले ही इसके लिए हजारों कानून क्यों न बना दिये जायें। यह दिन ब दिन बढ़ती ही जायेगी।

एक सवाल पड़ा हो सकता है कि जमींदार और महाजन इतने गरीब लोगों को कच्चे क्यों देते हैं जो पसा चुकता न कर सकें? जहाँ तक छोटे किसानों की बात है उनके पास जमानत के रूप में दान के लिए कुछ तो है लेकिन साधारण मजदूरों के पास क्या है? यह बड़ी सहज बात है। कच्चे के कारण छोटा किसान महाजन के लिए अपनी जमीन गँवा देता है और इसी तरह खेतिहर मजदूर बहुत मामूली महनताने पर श्रम करने के लिए बाध्य होता है। मजदूर के पास और कोई चारा

ही नहीं है। महाजन चाहता है कि य लोग उसस ज्यादा म ज्यादा कज तें क्याति उस पता है कि इसकी अदायगी नहीं हो पायेगी और इस प्रकार उस मजदूर को अनक पीढ़िया इसकी गुलामी कर सकेंगी। यही वास्तविकता है। सतिहर मजदूर को इसी प्रकार गुलाम बनाया गया है और व पूरे वष महाजन के सता पर या तो बिना किसी मजदूरी के या बड़ी मामूली मजदूरी लेकर दिन रात काम करत रहत है। उह यह भी अधिकार नहीं होना कि वे किसी और व्यक्ति के खेत पर काम कर सक। अनक स्थाना म यह भी देखा गया है कि य अपन मालिक की इजाजत क बगर शादी भी नहीं कर सकत, भले ही उनक अंदर शादी करन की क्षमता क्या न हो। रगपुर (अब बंगलादेश म है) की एक प्रचलित प्रथा का उदाहरण दिया जा सकता है। यहा वधुआ मजदूरों के पास इतने पस नहा हो पात थे कि व अपन लिए शादी का इतजाम कर सकें। शरीर की इस प्राकृतिक भूख क स्वाव स उनके काम पर असर पड़ता था जिसे मालिका न महसूस किया। इस समस्या क समाधान के लिए हिंदू और मुसलमान—दोनों जोतदारा न एक तरीका ढूँढ निकाला। इन वधुआ मजदूरों को कुछ औरतें दी गयीं और कहा गया कि इन औरतों का काम उनके लिए खाना बनाना है। सच्चाई यह थी कि उन्हें मजदूरों की काम-वासना की तृप्ति के लिए भेजा गया था। तिकड़मी मालिका के विभाग न कसा अनूठा समाधान ढूँढ निकाला।

लिय गय ऋण क बार म यदि विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जाय तो पता चलगा कि इनका परिमाण क्या है? लगभग 58 प्रतिशत वधुआ मजदूरों पर प्रति व्यक्ति ऋण 500 रुपये 199 प्रतिशत पर 500 से 900 रुपये क बीच और लगभग 21 प्रतिशत पर 900 रुपये से अधिक का ऋण है। निश्चय ही निहार इसका एक ठोस उदाहरण है। यहाँ कज की राशि बारी कम है। आकड़ इस प्रकार ह

वधुआ मजदूरों का प्रतिशत

45.8

86.5

प्रति व्यक्ति ऋण

रु० 100 या कम

रु० 300 या कम

कानून इसकी उलटी स्थिति का भी उल्लेख किया जा सकता है। राजस्थान क सगरी सागा म 12.9 प्रतिशत क ऊपर 500 रुपये तक और 58.8 प्रतिशत क ऊपर 900 रुपये से अधिक का कज है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दोनों राज्यों क मजदूरों का अलग अलग जीवन-स्तर है और उनकी सामाजिक अन जियाएँ भी भिन्न हैं।

महाजन लागू सारी धरती पर एक नियम का गमान रूप से पालन करत है और वह यह कि व कभी एक बार म ही पयाप्त रकम कज क रूप म नहीं देत।

हमेशा कर्जदार की जरूरत से कम राशि ही कर्ज के रूप में दी जाती है। कर्ज मिलन तक उन्हें महाजनो के यहाँ कई-कई चक्कर लगान पड़ते हैं और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है।

बधुआ मजदूरों की यह कष्ट भरी कहानी बाजार से बेहद कम मजदूरी पर महाजना के जगल और खेतों में काम करने के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। शुरू में लिया गया ऋण लगातार बढ़ता जाता है। मूल राशि पर और बढ़ती हुई मूल राशि पर ब्याज की राशि भी बढ़ती जाती है।

ब्याज की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। बिहार के कमिया लोग ब्याज के रूप में चालीस प्रतिशत चुकता करते हैं। कई मामला में यह दर सौ प्रतिशत से भी अधिक है। कनाटक के बधुआ लोगों से भी चालीस प्रतिशत से ज्यादा ब्याज वसूला जाता है। खेतिहर मजदूर कुछ भी चुकता नहीं कर पाते—वे कर्ज की अदायगी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते।

मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में एक अजीब और दिलचस्प बात देखने में आती है। वहाँ के महाजन ब्याज नहीं लेते। ऐसा सोचा जा सकता है कि वे बड़े मानवीय हैं लेकिन बात ऐसी नहीं है। दरअसल मजदूर एक ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं जहाँ ब्याज वसूलना एक अनावश्यक श्रम होगा। शुरू में उन्होंने जो कर्ज ले लिया है और उस पर जो सूद इकट्ठा होता जा रहा है उसका कारण हमेशा के लिए वहाँ अध गये हैं।

इस तरह के ऋणा के लेने का कारण विशुद्ध रूप से अपना जीवन यापन करना रहा है। कर्ज का 47.5 प्रतिशत हिस्सा खान के लिए और 33.7 प्रतिशत हिस्सा शादी-ध्याह, दाह सस्वार आदि जैसे सामाजिक कार्यों के लिए खर्च हुआ। यह आरोप कि मजदूर लोग फिजूलखर्च करते हैं, एकदम गलत है और आँकड़ों से यह साबित हो सकता है।

यदि यह कहा जाये कि ग्रामीण कर्जदारी ने बधुआ मजदूरों को जन्म दिया, तो गलत नहीं होगा। सरकारी आँकड़ा के अनुसार खेतिहर मजदूरों का 4.2 प्रतिशत बधुआ मजदूर हैं। गर सरकारी आँकड़े इस 5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बताते हैं। आठ विभिन्न राज्यों का जलम अलग-अलग ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत है

राज्य	बधुआ मजदूरों की संख्या	कुल खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	3 25,000	4.96
बिहार	1,11,000	1.70
गुजरात	1 71,000	9.40
कर्नाटक	1,93 000	7.60
मध्य प्रदेश	5 00 000	11.80

# 54 भारत म बहुआ मजदूर

राज्य	बहुआ मजदूरों की सख्या	कुल खेतिहर मजदूरों का प्रति
राजस्थान	67 000	9 40
तमिलनाडु	2 50 000	6 00
उत्तर प्रदेश	5,50 000	10 60

आवडी से पता चलता है कि आठ राज्या म बहुआ मजदूरों की सख्या 21 7 लाख है जो 3 कराड 70 लाख खेतिहर मजदूरों का 6 1 प्रतिशत है। यदि उड़ीसा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सही आवड प्राप्त हों तो इस सख्या मे और भी वडि होगी।

अब हम उन सात जिला का ब्यौरा देत हैं जहा सबसे ज्यादा बहुआ मजदूर हैं

## क्षेत्र

उत्तरी तमिलनाडु  
तलंगाना (आंध्र प्रदेश)

गुजरात / महाराष्ट्र

मध्य गुजरात  
महाकौशल (मध्य प्रदेश)

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

उत्तर प्रदेश (उत्तर) और  
बिहार

निम्नांकित जिलों को बहुआ मजदूर प्रदेश का उपनाम दिया जा सकता है

## जिला

उत्तरी और दक्षिण आरकाट  
नालगाडा करीमनगर  
शिमोगा  
अहमदनगर  
बडोदा  
सतना सादान यस्तर  
पनामू  
दयारिया

## जिले

धमपुरी उत्तरी और दक्षिणी आरकाट चित्तपुर  
हैदराबाद आदिलाबाद मेडक, करीमनगर, महबूब  
नगर नालगाडा, निजामाबाद वारंगल।  
बलसद, सूरत बिंदरोदा, गुजरात, पंचमहल,  
नासिक धूल जलगाव (महाराष्ट्र)।  
महेशपना, मुरिंदरनगर, काठियावाड।  
रायगड, रतलाम विदिगा गुना मुरना सागर  
छनहार सतना रीना, सदल सरगुजा,  
बस्तर (विणप रूप से उत्प्रेक्षणीय)।  
बिजनौर मुजफ्फरनगर मरठ मुरादाबाद, बरली  
खीरी सीतापुर।

बाहा देवरिया, चम्पारण और सागन।

## राज्य

तमिलनाडु  
आंध्र प्रदेश  
कर्नाटक  
महाराष्ट्र  
गुजरात  
मध्य प्रदेश  
बिहार  
उत्तर प्रदेश

इन धनो म जो बधुआ मजदूर है उनम से 78 प्रतिशत कज लेन के कारण बधुआ बनाये गय हैं और केवल 13 प्रतिशत—जो किसी खास जाति के है और कई दूसरा काम नही पा सकते—अपन मालिको की जमीन कई पीढ़ियो से वास्तकार के रूप म जोत रहे है ।

इस गुलामी की समय सीमा पर ध्यान देना जयपूर्ण होगा । सामान्य तौर पर 60 प्रतिशत बधुआ मजदूर अनिश्चित काल के लिए बधुआ बनाये गये है । इस गुलामी से मुक्ति उनके मालिका की दया पर ही निर्भर है । लगभग 10 प्रतिशत मजदूर दस वष की उम्र से गुलाम हैं । इसके अलावा दस प्रतिशत मजदूर बीस वष से भी अधिक समय से गुलाम है । महज चार वष पूव 56 प्रतिशत मजदूरों का बधुआ बनाया गया है और अन्य 33 प्रतिशत मजदूरों ने अभी दो वष पूव ही अपनी जाजादी खोयी है ।

दृष्टया ध्यान दें कि बधुआ मजदूर प्रया को समाप्त करने के लिए 1975 म एक अध्यादेश जारी किया गया ।

किसी भी कानून जयवा अध्यादेश ने बधुआ मजदूरों की मदद नही की । व अभी भी महाजनो के जाल म हैं । अपनी जाय से वे कज चुक्ता नही कर सकत । इनम से लगभग तीस प्रतिशत लोग प्रति माह दस रुपये से कम पैसे कमाते हैं, हालांकि भुगतान की जाने वाली औसत राशि की दर 35 रुपये है ।

तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, कनाटक और बिहार के मजदूर काफी भाग्यशाली हैं—तमिलनाडु म पचास प्रतिशत मजदूरों की आय प्रति माह चालीस रुपये से थोड़ी ज्यादा है और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के तीस प्रतिशत मजदूरों की है । कनाटक और बिहार म नमश 39 प्रतिशत और 40 प्रतिशत मजदूरों की इनकी ही आय है ।

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नकद और फसल के रूप म उन्हें वस्तुतः क्या मिलता है । अनाज के रूप मे जो कुछ मिलता है उसका मूल्यांकन यदि रुपये के सदभ मे करें तो थोड़ा कहना ही बेहतर होगा ।

हमन पहले ही बताया है कि हरवाह के नाम से ज्ञात गारखपुर और देवरिया के बधुआ मजदूरों का खुराक के रूप म क्या मिलता है । वे गाय और भैंस के गोबर से निकले अनाज को घाकर खाते हैं । भूख की ज्वाला को शांत करन के लिए ही वे ऐसा करत ह और इस आहार का भी मजदूरों मान ली जाती है । इसका अलावा यदि उन्हें नकद के रूप म कुछ दिया जाता है तो उसम से ब्याज काट लिया जाता है । इस प्रकार वास्तव म उन्हें कुछ भी नही मिलता और यही वजह है कि अतीत म लिये गये ऋण का कभी भुगतान नही हो पाता । उलटे मालिक के खाते म यह बढ़ता ही जाता है । इसी तरह पीढ़ी दर-पीढ़ी गुलामी की जंजीर बसती जाती है । परीक्षणो से पता चलता है कि बधुआ मजदूरों की

कुल आवादी का 83 प्रतिशत हिस्सा उन लोग का है जिनकी आयु चालीस वष से कम है। इसका जलावा 53.6 प्रतिशत लोग तीस वष से और 21 प्रतिशत लोग बीस वष से कम उम्र के हैं। मालिक उन लोग को पसंद नहीं करते जिनकी उम्र चालीस वष से अधिक है क्योंकि कठार श्रम करने की क्षमता उनमें नहीं रहती। ऐसे मामला में उनके बेटों को हल जोतने के लिए लगाया जाता है और वह काम से छुट्टी दे दी जाती है। गुनामी का बोझ जो एन लबी अवधि से बाद के कंधा पर था अब बेटे के कंधा पर आ जाता है और कुछ समय बाद उसके बेटे के कंधा पर और इस प्रकार यह सिलसिला जारी रहता है।

बहुआ मजदूर परिवारों में से 75 प्रतिशत परिवारों में कम से कम हर शत परिवारों में से परिवार के चार सदस्यों को गुलामी करता है। बिहार में 62 प्रतिशत हैं और यह समझने के लिए कि वहाँ प्रचलित प्रथा के अनुसार उक्त परिवार के सभी सदस्य बंधक हैं। अन्य राज्यों में केवल उसी व्यक्ति का बहुआ रखा जाता है जिसने छद्म बंध लिया हो।

(3)

हर असल बहुआ मजदूरों में सबसे ज्यादा सध्या हरिजन और आदिवासिया की है जो लगभग 84 प्रतिशत हैं। मालिकों में केवल 8.4 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी हैं तथा 84.2 प्रतिशत सबंध हिंदू हैं। जाति और वर्ग हमेशा से ही हमन के हथिपार रहे हैं। यदि वर्ग व्यवस्था का अध्ययन करें तो इसका पता चल जायगा। मालिकों में हरिजन और आदिवासी अल्पमत में हैं पर य भी बहुआ मजदूर रखते हैं क्योंकि जमीन की मिल्कियत हाने से उनके वर्ग चरित्र में भी तबदीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर, आंध्र प्रदेश के हरिजन—जिन्हें मलस कहा जाता है—बहुआ मजदूर रखते हैं तथा मुडिया और गाड नाम के बस्तर के आदिवासी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुआ मजदूर रखना जरूरी समझते हैं। थोड़ा सुविधा सम्पन्न होते ही सबंध हिंदुओं द्वारा अपनाए जाने वाले बंधा कारण है कि अधिकांश बहुआ मजदूर हरिजन अथवा आदिवासी हैं। इसका लिए विस्तार से विवेचन करना जरूरी है।

1961 की जनगणना से पता चलता है कि मेती-बाढी से संबंधित लोग में से 53 प्रतिशत ऐसे थे जो सचमुच खेती करते थे। इनमें से हरिजन और आदिवासियों की संख्या क्रमशः 38 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी। खेतिहर मजदूरों में—जो कुल संख्या का 17 प्रतिशत थे—38 प्रतिशत हरिजन और 20 प्रतिशत आदिवासी थे।

आदिवासियों के लिए भूतों का काम काफी कठिन लगा। आदिवासी

किसानों में से 10 प्रतिशत से अधिक खानाबदोश ज़िंदगी बिताते हैं। वे ज़मीन के किसी खास हिस्से पर नहीं बस सकते। उनके रहने वाले अनेक इलाकों को वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है क्योंकि कभी इन इलाकों का सर्वेक्षण ही नहीं किया गया। यहाँ शायद ही सिंचाई की व्यवस्था कभी की गयी हो। जैसी ज़मीन उनके पास है वसी ज़मीन खेती करने के लिए एकदम अनुपयुक्त है। इनको अधिक-से अधिक चरागाह बनाया जा सकता है जयवा इन पर कुछ फल के पौधे लगाये जा सकते हैं। साथ ही, इस ज़मीन का क्षेत्रफल भी इतना कम है कि इसमें इतना उत्पादन नहीं हो सकता जिसमें पूरे परिवार का खर्च चल सके। इसका नतीजा यह होता है कि आदिवासियों को महाजन से बज लेना पड़ता है। अगर आदिवासियों के हिस्से की ज़मीन उपजाऊ हुई तो धनी किसान और जोतदार कोई न कोई तिकड़म करके उसे उनसे हड़पने में कामयाब हो जाते हैं। अगर ऐसा करने के लिए उन्हें हरिजन और आदिवासियों के परिवारों का जिंदा जलाना पड़े तो इसमें भी वे नहीं हिचकते।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद में ज़मीन जबरन जोतने मजदूरी, बंधुआ मजदूर तथा बजदारी के सवाल पर 1974-77 में हुए संघर्षों के आकड़े प्रस्तुत किये हैं जो अपन-आप में हत्या, बलात्कार और अत्याचार की एक दुःखद गंगा हैं।

इनका विवरण इस प्रकार है

राज्य	वर्ष	घटनाओं की संख्या
उत्तर प्रदेश	1974	805
	1975	329
	1976	591
मध्य प्रदेश	1974	59
	1975	76
	1976	323
आन्ध्र प्रदेश	1974	44
	1975	15
	1976	48
गुजरात	1974	2
	1975	7
	1976	14
कर्नाटक	1974	6
	1975	22
	1976	20



# 58 भारत म वधुआ मजदूर

राज्य	वर्ष	घटनाओं की संख्या
महाराष्ट्र	1974	17
	1975	10
	1976	9
	1974	8
	1975	5
बिहार	1976	7

हरिजन और आदिवासी इसलिए बच लेते हैं क्योंकि उनकी जोतें बलाकारी हैं और यह इसलिए क्योंकि उनके पास खेती के उपकरण नहीं हैं। बढता जाता है और अतः वे अपने खेतों से हाथ धोकर वधुआ मजदूर बन जाते हैं। आदिवासियों की समस्या और भी गंभीर है। विभिन्न राज्यों में बिये गये सर्वेक्षणों से विस्तृत जानकारी मिलती है। 1975 में पश्चिम बंगाल में आदिवासियों का मामला से संबंधित विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 1,602 आदिवासी परिवारों में से 1,080 परिवार बच के बोझ से दबे हैं। इनमें वे बाशिंदे हैं जिन्हें भोटिया, लेप्चा, लोडा, महाली, मोचा, मुडा, उराव, राबा और सयाल के नाम से जाना जाता है। ये जनजातियाँ पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदिवासियों की कुल आबादी का 94 प्रतिशत हैं। जिन 1,080 परिवारों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें से 755 परिवारों में (69.9 प्रतिशत) नकद के रूप में 150 परिवारों ने (13.88 प्रतिशत) अनाज के रूप में और 177 परिवारों ने (18.2 प्रतिशत) नकद और फसल दोनों रूप में बच लिया था। ये नृण गर आदिवासी महाजना से लिये गये थे जो हर तिब्बत के तरीके तयार रखते हैं।

बिजय मुडा 24 परगना जिले में सदशखाली पुलिस थाने के अंतर्गत मणिपुर नामक गांव में रहता है। उसने 133 एकड़ जमीन मिरबी रखकर 400 रुपये बच लिया। इसके साथ ही यह भी कि 6 वर्ष तक खेत की सारी फसल महाजन लेगा। दार्जिलिंग जिले में पेडांग पुलिस थाने के अंतर्गत सवधान गांव के तनजिब भोटिया ने अपनी 0.15 एकड़ जमीन के बदले में 800 रुपये का बच लिया था। शत यह भी कि इस रकम का बचले वह अपनी फसल देकर बच उतार देगा और जब तक बच उतर नहीं जाता फसल की कीमत 15 रुपये प्रति मन के हिसाब से तय रहेगी। जाहिर है कि यह बच कभी चुकता नहीं हो सकता, क्योंकि बचदार को अपना खर्च चलाने के लिए और भी बच लेना पड़ेगा।

विशाखापत्तनम में आदिवासियों के एक गांव में बिये गये सर्वेक्षण में पता चला कि उम गांव के 61.24 प्रतिशत परिवार बच के बोझ में दबे हैं। भूमिहीन

परिवारों की हालत और भी खराब थी, क्योंकि कुल कज का 63 63 प्रतिशत जकेले उन पर था। किसानों में जिनके पास अपेक्षाकृत ज्यादा जमीन थी, उन पर कम कज था। प्रत्येक परिवार पर कज की राशि औसतन 308 रुपये थी। लगभग 72 22 प्रतिशत परिवारों पर 400 रुपये से कम का कज था।

शेष परिवारों ने 400 से 1200 रुपये के बीच कज लिये थे।

कजदारा में 67 4 प्रतिशत आदिवासियों ने अपने परिवार का खर्च चलाने और कुछ जय जरूरतें पूरी करने के लिए ही कज लिया था। आन्ध्र प्रदेश में भद्रागिरि में 1971 72 में किये गये एक सर्वेक्षण में बताया गया कि 57 प्रतिशत आदिवासी कज में डूबे थे। प्रत्येक परिवार पर औसतन 157 रुपये का ऋण था और 93 प्रतिशत ऋण बैलो तथा खेती बाड़ी से सम्बंधित अथवा सामान की खरीद के वास्ते लिये गये थे। कुल ऋण का केवल 6 4 प्रतिशत जीवन-यापन के खर्चों में शामिल हुआ था। श्रीकाकुलम के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में 1972 में 677 परिवारों ने 1 14 लाख रुपये का ऋण लिया था।

1973 में बिहार में पलामू जिले में हरिजन और आदिवासियों की कज-दारी के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने जीवन यापन के खर्च तथा पारिवारिक जरूरतों का पूरा करने के लिए कज लिया था। अनधिकृत रसीदों से उन ऋणों का प्रमाण मिलता है जिनके लिए 75 प्रतिशत ब्याज वसूला गया। लगभग 26 92 प्रतिशत परिवारों पर ऋण का बोझ था।

तमिलनाडु की स्थिति और भी खराब थी। कोली पहाड़ी के आदिवासियों ने जो ऋण लिया था वह प्रत्येक परिवार पर औसतन 2000 रुपये के बराबर था। कज लिये गये प्रत्येक 100 रुपये पर ब्याज 60 से लेकर 100 रुपये तक वसूला गया।

उड़ीसा में नारायण पटना ब्लॉक में 55 प्रतिशत आदिवासी अपने परिवार का भरण-यापन कराने के लिए कजदार बन हुए हैं। गजाम जिले के परलखमुडी सब डिवीजन में 66 7 प्रतिशत आदिवासी कज के बोझ से दबे हैं। इनमें से 91 4 प्रतिशत लोगों ने नकद के रूप में ऋण लिया है। ऋण लेने के कई कारण हैं—37 8 प्रतिशत मामलों में खेती बाड़ी के खर्च के लिए कज लिया गया है, 41 प्रतिशत छाद्यान के लिए और शेष पिछला कज चुकता करने के लिए।

मध्य प्रदेश में एक इलाके में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों में से 52 5 प्रतिशत ऐसे हैं जो कज से लदे हैं। रतलाम जिले में ऐसे लोगों की तादाद 82 9 प्रतिशत है। प्रत्येक परिवार पर औसतन 357 रुपये का ऋण है। 34 5 प्रतिशत घरेलू जरूरतों के लिए, 12 2 प्रतिशत सामाजिक और धार्मिक कारणों से और 43 6 प्रतिशत खेती में काम के खर्च के लिए ऋण लिया गया।

हरादून के निवट जोनसार गाँव क्षेत्र में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी

सक्या कजदार क रूप म है। यहाँ भी पारिवारिक जम्हरत ही, ऋण लेन का मुख्य कारण बनी। ऋणग्रस्तता क परिमाण का सही सही पता कभी नहा लगाया जा सकता क्याकि इस मसले पर महाजन लोग मामोश है।

इस निष्पक्ष पर आसानी स पहुँचा जा सकता है कि जिन मामला का उत्तेज किया गया है उनम भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। चूकि कजदार उस कज क बल पर अपना जीवन-यापन ही कर पात है इसलिए जाग जिन्ना रहन क लिए भी उह कज का ही सहारा लेना पडता है और इस प्रकार कज का बोप बढ़ता ही जाता है। यहाँ तक कि जिनक पास थोड़ी-बहुत जमीन भी है उह भी खेती करन के लिए कज का ही सहारा लेना पडता है। इससे व केवल ब्याज चुकता क पाते है। इसलिए मूल राशि बढ़ती ही रहती है। जिस राशि पर वे हस्ताक्षर करत है (दगअसस अँगूठ का निशान लगात है) और जो राशि वे पात है उसम काफी अंतर हाता है।

ऋणग्रस्तता को समाप्त करन क बार म सरकार द्वारा पारित किय गय कानून किसी काम क साबित नहीं हुए। उह कभी लागू नहीं किया गया। इसको अमल म लाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक विवत्प के रूप म किसी एस सोन की स्थापना न की जाय जहा स किसाना की जम्हरत पूरी की जा सवें। वका और सहकारी समितिया पर महाजना का ही नियन्त्रण है। उनका विरोध करके किसान उनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता। यदि वे महाजना का नाराज करत ह तो आग कज लेन का रास्ता बन हो जाता है। इस प्रकार कजदार अपन गले म फंदा डलवान म मनुद ही मददगार हा जाता है।

श्रीकाकुलम बिशाखापत्तनम और पश्चिमी तथा पूर्वी गोणवरी जिला म जहाँ अनुसूचित जातिक लोग रहते हैं वधुआ मजदूरी की प्रथा काफी प्रचलित है। इन इलाका म मद्रास ऋण वचन समाप्ति विनियमन कानून 1940 लागू है। यह कानून सभी समझौता को रद्द करता है सिवाय उन समझौता के जो मजदूर और जोतदारा तथा महाजना के बीच प्रत्यक्ष रूप से सम्पन है और जिस जोतदार तथा महाजन अधिकारिया के समक्ष पेश करत हैं। अधिकारिया को इस बात की गारंटी की जरूरत होती है कि कोई समझौता धर कानूनी नहीं है। यह समझौता अधिकतम एक बष के लिए होना चाहिए और इस पर ब्याज की दर 6 5 प्रतिशत स रपादा नहीं होना चाहिए। कहना न होगा कि इस कानून को कभी लागू नहीं किया गया।

1973 म बिहार म चनपुर लातेहर गडवा मनिका और रसना म एक दल ने सर्वेक्षण किया। दल को पता चला कि इन इलाका म वधुआ मजदूर बनाय रखन की प्रथा काफी प्रचलित है। इस सर्वेक्षण की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं

(क) सर्वेक्षण दल न जिन 58 वधुआ मजदूरों से भेंट की उनमें से 34 हरिजन और 24 आदिवासी थे। कुछ मामलों में समूचा परिवार वधुआ मजदूर था।

(ख) प्रत्येक परिवार पर 22 रुपये से 350 रुपये तक का कर्ज था। यह ऋण जबानी करारों अथवा गैर सरकारी रसीदों के एवज में लिया गया था। मूल राशि और व्याज की राशि के चुकता होने तक कर्जदारों को वधुआ मजदूर के रूप में काम करना था। यदि कर्ज देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो उसका बेटा उसके स्थान पर काम करेगा।

(ग) कर्ज लेने का कारण परिवार के लिए भोजन, शादी-विवाह के खर्च, इलाज और पिछले कर्ज के भुगतान की व्यवस्था करना था।

(घ) कर्ज देने वाले सूदखोर महाजन और जमींदार ब्राह्मण तथा बनिया जाति के थे—उनमें से कुछ दुकानदार भी थे।

(च) राज्य सरकार का श्रम विभाग 'यूनितेड वेतन कानून' को लागू करने में विफल रहा।

(छ) वधुआ मजदूरों को पाव भर पिसा मक्का नाश्ते में और जाधा किलो ग्राम मोटा चावल दोपहर के खान में मिलता था। मजदूरों के बीबी बच्चा को भी—यदि वह काम करते थे तो—इतना ही या इससे कम मिलता था।

(ज) एक गांव में सुनने में आया कि मजदूरों को खान के अलावा वेतन के रूप में प्रतिमाह 15 रुपये प्राप्त होते थे। इस राशि को कर्ज का भुगतान मानकर काट लिया गया। व्याज की दर 100 प्रतिशत थी।

1973 में बिहार सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने भड़रिया और राका ब्लॉक के 27 गांवों का एक सर्वेक्षण किया। विभाग के अधिकारियों ने 232 लोगों से बातचीत की जिनमें 98 आदिवासी, 11 हरिजन, 23 निचली जाति के लोग और एक मुसलमान थे। यह देखा गया कि अधिकांश वधुआ मजदूर आदिवासी थे जिन्हें करवा के नाम में जाना जाता है। हरिजनों में अधिकांश वधुआ मजदूर भुइया थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि

(क) कर्ज का भुगतान होने से पहले ही यदि कर्जदार की मृत्यु हो जाती थी तो वधुआ मजदूर के रूप में उसके बेटे को काम करना पड़ता था। उन क्षेत्रों में इस तरह के 18 उदाहरण मौजूद थे।

(ख) पारिवारिक जरूरतों के कर्ज लेने के लिए मजदूर किया। 59 प्रतिशत कर्ज भोजन के लिए, 14 प्रतिशत शादी के लिए, 11 प्रतिशत शादी-ब्याह के लिए और शेष चिकित्सा तथा दाह संस्कार के वास्तव में लिए गए थे।

(ग) वधुआ मजदूरों के मालिक विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के थे 23 प्रतिशत भुइया, 10 प्रतिशत अहीर, 12 प्रतिशत राजपूत और शेष विभिन्न वर्गों के थे। कमिया (वधुआ मजदूरों) लोगों का पता था कि उनके मालिक जा

खरीदने में मदद पहुँचायी। यह इतिहास में उम्र एग बहुत छोट बाल में मम्मल हुआ, जो बहुत पुरानी बात नहीं है।

इतिहास की यह धारा मुगल शासन काल में टैक्स-कलेक्टरों से लेकर ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों के समय तक बिना किसी शोरगुल में बहती रही। उन दिनों सत्ता में कमांडरो का चुनाव निरपवाद रूप से कुलीन घराना में किया जाता था और इन कमांडरो के लिए उन्हें जागीरें तक दी जाती थी। इन इलाकों से वसूल गये कर पहुँचाने के लिए उन्हें जागीरें तक दी जाती थी। इन इलाकों से वसूल गये कर किया जाता था। समय के साथ जागीर प्रणाली में मुताबिक सब जमींदारी प्रणाली का रूप ले लिया।

भारतीय ढंग की सामंती प्रणाली का इन तथ्यों से मदद मिली कि यहाँ के गांव असम्बद्ध और आत्मनिर्भर थे। बाद में तुर्कों अपना और मुगलों ने भारत के सभी क्षेत्रीय सामंत सरदारों को एकजुट करके कृत्रिम रूप से केंद्र शासन सामंतवाद घोषण की कोशिश की। इस हस्तक्षेप के बावजूद स्थानीय सामंतवाद का अस्तित्व बना रहा।

गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार सभी सामंत सरदार उच्च जातियों के थे। तुर्कों और मुगल सम्राटों की सूटपाट जब भी असहनीय होती थी, जनता स्थानीय सामंत सरदारों के यहाँ शरण लेती थी। उन्हें जनता के समर्थन से शक्ति मिलती थी और इससे वे इतने मजबूत हो जाते थे कि वे किसी भी शासन कर रहे सम्राटों की शक्ति की भी अवहेलना कर देते थे। मुगल शासन-काल के अंतिम दिनों में जब वे द्वीय सत्ता के क्षीण होने के कारण जमींदारों और जागीरदारों की ताकत बढ़ी तो ग्राम समाज लड़खड़ा लगे। अब इन सरदारों ने दमन का सिलसिला शुरू किया जो प्लासी के युद्ध के बाद चरम सीमा पर पहुँच गया।

अंग्रेजों द्वारा शुरू किये गये स्थायी बदोबस्त प्रणाली में जब जमाने के बाद इनमें से अनेक सामंत सरदारों का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनकी बड़ी बड़ी जागीर नीलाम हो गयी जिन्हें उन लोगों ने खरीदा जो शहरों में रहते थे और निहंवाणिज्य व्यापार में अंग्रेजों से होड़ लेने में असफलता मिली थी। लोग ऊँची जाति के थे और उनके पास नकद राशि काफी थी जिसे जमीन खरीदने के अलावा और किसी काम में वे नहीं खर्च कर पाते थे। आज भी जो अंग्रेजों कागजात हैं उनके इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

इनमें से एक हिस्सा उन लोगों का था जिन्होंने व्यापार और वाणिज्य के लिए काफी पूँजी इकट्ठी कर ली थी। उन्हें मध्य वर्ग का कहा जाता था। दूसरे व लोग थे जिन्होंने अंग्रेज सौदागरों की सहायता की थी। इनमें से पहले वर्ग के



सास बनाना में रहत थे ताकि निचली जाति के लोगो से इनका शरीर न छू जाय। इस सदी के पूवाढ में इनमें से जनक न गैर-ब्राह्मण रयता के हाथ जमीन बच दी—य लोग ब्राह्मण तो नहीं थे पर ऊँची जाति के थे। सम्प्रति अधिकांश भू-स्वामी खेती न करन वाल ब्राह्मण और कायस्थ थे। जाटा, अहीरा और म भी एक मामूली सा प्रतिभात एस लोगो का है जिनके पास अपनी ज़मीन सामान्य तौर पर अधिवाश जमीन ऊँची जाति के लोगो के पास है जाति नहीं है।

पश्चिम बंगाल में जमींदारी गरीदन में जिन लोगो ने अपनी सम्पत्ति लगा दी थी—द्वारकानाथ टगोर पड़कापाडा के राजा सिंहा, हयकाला और रा बागान के दत्ता लोग रामदुलास के साहा और मल्लिक लोग। ये सभी ऊँची जाति के थे।

दूसरी ओर गरीब बिगान खतिहर मजदूर और बधुजा मजदूर—ये सभी निम्न हिंदू जातिया आदिवासिया और मुस्लिम समुदाया के हैं। मुसलमानों का प्रभाव-क्षय ज्यादा होने के कारण अंग्रेजों द्वारा भाड़े पर खरीदे गये इतिहासकारों ने उनके विद्रोहों को साम्प्रदायिक रंग दे दिया और इन विद्रोहों के महत्व को कम करने की कोशिश की। यह अब सभी जानते हैं कि सयासी विद्रोह (यह नाम मजनुशाह या मजनु फबीर के नेतृत्व के कारण पड़ा) और तीक्ष्णरी के नेतृत्व वाले बहावी विद्रोह को साम्प्रदायिकता का जामा पहना दिया गया ताकि उनका महत्व कम किया जा सके।

इस प्रकार भारत का सामाजिक आयिष इतिहास बताता है कि यहाँ जा ही बग हो गया। चूँकि 'जाति शब्द' का एक महत्व है इसलिए हम लोग कि जाति की हैसियत का अदावा उसकी जाति से लगाते हैं। हम देखत हैं कि ऊँची जाति के जोतदार गरीब हरिजन मजदूरों या किसानों को जिंदा जलान में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं। फिर भी वे ऊँची जाति के गरीब किसानों पर इस तरह का अत्याचार कभी नहीं करते। इसी वजह से हम यह कह रहे हैं कि जाति और बग एक दूसरे के पर्याय हैं।

कानून की खाँमियों को ही इस बात का श्रय है कि तथाकथित आजादी के बाद जमींदारों का नाम तो खत्म हो गया पर उनका नियंत्रण पहले जसा ही बना रहा। जहाँ तक जमींदारी और विचौलियों की प्रथा के समाप्त होने की बात है ये जमूलन सही है पर कई मामलों में, मिसाल के तौर पर सुद कुश्ता रयतो जाति के मामलों में पुराना सिलसिला जारी रहा। इसका अलावा कानून को लागू करने से पूर्व जमादारा को काफी समय भी दे दिया गया ताकि वे अपने रिश्तेदारों और कमचारियों के नाम पर कानूनी ढँग से जमीन हस्तांतरित कर सकें। जमादारा न यही किया भी।

उह अनक वगदारा और रैयत। स जपनी जमीन खाली करान का अवसर भी मिल गया। कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1976 में प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसे अनक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जमींदारों के खत्म होने से लगभग दो करोड़ किसानों का राज्य के साथ सम्पर्क कायम किया जा सका है। इसी के साथ लाखों रैयत और वगदार खेतिहर मजदूर बन गए। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कानून होने के बावजूद जमीन अभी भी मुठ्ठी भर धनी किसानों के हाथ में है और पिछले कुछ दशकों में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयोग के अनुसार इसका प्रमाण नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा एकत्र किया गया जाठवें चक्र का आकड़ा है जिससे पता चलता है कि 2 64 प्रतिशत परिवारों के पास 30 एकड़ जमीन है जो निर्धारित सीमा से 28 05 प्रतिशत ज्यादा है। 1970 71 की कृषि-गणना से पता चलता है कि भू-स्वामियों की संख्या कुल आबादी का महज 4 प्रतिशत है जिनके पास कुल जमीन का 30 5 प्रतिशत है।

इस मामले पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। 1951 की जोतो के बारे में कृषि श्रम जांच नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 5 एकड़ या इससे कम की जोत—जो कुल जोत का 15 5 प्रतिशत है—59 1 प्रतिशत परिवारों के पास था। इसके अलावा 25 एकड़ या इससे अधिक की जोत, जो कुल जोत का 34 4 प्रतिशत है, 5 6 प्रतिशत परिवारों के पास था। राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण (नेशनल सैम्पल सर्वे) द्वारा जून 1960 से जून 1961 के बीच किये गए अध्ययन से पता चलता है कि जमीन का 56 2 प्रतिशत भाग 10 प्रतिशत परिवारों के हाथ में था। रिपोर्ट के अनुसार

30 प्रतिशत परिवारों के पास	0 1 प्रतिशत जमीन
अगले 10 प्रतिशत ,	0 6 ,
अगले 10 प्रतिशत ,,	2 1 ,,
50 प्रतिशत का कुल योग	2 8 ,
अगले 10 प्रतिशत के पास	4 7 ,,
अगले 10 प्रतिशत ,,	6 9 ,,
अगले 10 प्रतिशत ,	11 0 ,
30 प्रतिशत का कुल योग	22 6 ,,

इस प्रकार खेतीबाड़ी में लगे 80 प्रतिशत लोगों के पास कुल जमीन का केवल 25 4 प्रतिशत था। बाढ़ के 10 प्रतिशत लोगों के पास 18 4 प्रतिशत जमीन थी और अंतिम 10 प्रतिशत के पास कुल जमीन का 56 2 प्रतिशत था।



यह अंतिम 10 प्रतिशत ही देश में सामंतवाद के अलम्बरदार है और ये ही वे लोग हैं जिन्हें पंच-वर्षीय योजनाओं में दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता मिलती रही है। यही वे लोग हैं जिनको कानून का सहारा प्राप्त है। आश्चर्य नहीं कि खेती के क्षेत्र में इतनी विषमता देखी जाती है। अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन व दिन और ज्यादा गरीब हो रहा है।

भूतपूर्व खाद्यमंत्री श्री जगजीवनराम ने बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि 42 प्रतिशत खेतिहर परिवार के पास केवल एक एकड़ जमीन है जबकि 22 प्रतिशत परिवार के पास एकदम जमीन नहीं है। लगभग 3-4 प्रतिशत परिवारों के पास अपार जमीन है और सरकारी मदद से वे अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तथा अपनी नीतियों का पूरी ताकत के साथ लागू करते हैं। निम्नतम क्षेत्र की उन्नति की जा सकती है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है।

इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए हर कोशिश करती है और जातन वाले को जमीन सौंपने की बात चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करके जान वाले नारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिना किसी लागू लपेट के यह कहा जा सकता है कि सरकारी भूमि नीति महज एक जमींदार बुजुर्गता है जो सामंतवाद का बरकरार रखने के लिए उन्मुख है। बुजुर्गता वगैरह इतना सावधान है कि हर बार विद्रोह छिड़ने पर वह जमीन दान देना और जमीन का बंदोबस्त करने की बात को सावजनिक चर्चा में ला देता है। तेलंगाना सशस्त्र संघ और तेलंगाणा आंदोलन (बमाल) तथा वल्लि विद्रोह (महाराष्ट्र) के बाद ऐसा देखने में आया है। इन विद्रोहों के बाद जब भी चुनाव नजदीक आया है बुजुर्गता वगैरह इस तरह का जोर देकर किया है। यही चर्चा है। केरल में भी पहली कम्युनिस्ट सरकार ने किसानों को धान में रखने के लिए सहकारी खेती पर बड़ी लम्बी चौड़ी बहसों की थीं। नक्सलवादी और श्रीकाकुलम में विद्रोह की लपटें उठने के बाद तथा पूर्वी गोदावरी और मुशहरी तराई में जमीन का छीनने की घटनाओं के बाद सत्तारूढ़ दल ने भूमि सुधार और किसानों का जमीन देने की आवश्यकता पर खूब बहस कर बातें शुरू कीं।

किसानों के धान पर बड़ा आक्रामक दिखने वाला मल्लम लगाने के लिए सरकार ने भूमि हदबंदी कानून पारित किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। साथ ही कानून के निर्माताओं ने बागों, सेव बागानों, चरागाहों, निवासस्थानों आदि की जमीन के लिए गुंजाइश छोड़ दी ताकि बड़े जोतदार इस कानून से प्रभावित न हों। और इस प्रकार जोतदारों को फायदा हुआ। नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न राज्यों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का पता चलता है।

राज्य	अधिकतम सीमा (हेक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	4 05 से 21 85
असम	6 94
बिहार	6 07 से 18 21
गुजरात	4 05 से 21 85
हरियाणा	7 25 से 21 85
हिमाचल प्रदेश	4 04 से 12 14
जम्मू-कश्मीर	3 68 से 7 77
कर्नाटक	4 05 से 21 85
केरल	4 86 से 7 07
मध्य प्रदेश	4 05 से 21 85
उड़ीसा	4 05 से 18 71
पंजाब	7 00 से 21 80
राजस्थान	7 25 से 21 85
तमिलनाडु	4 86 से 24 28
त्रिपुरा	4 00 से 12 00
उत्तर प्रदेश	7 30 से 18 25
पश्चिम बंगाल	5 00 से 7 00

यथाथ में ये कानूनी बर्दिशें ब्रेकार है। कोयम्बटूर में एक भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री कानूनी स्वीकृति के साथ 847 एकड़ जमीन रख सकता था और रख रहा है। इस जिले के जानुर चक्करह के पास 1,19॥ एकड़ जमीन है, पट्टा नायडू नामक सज्जन नन्दुर के पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 एकड़ जमीन खरीदी। उसने अपनी जमीन से सभी रयता को खदेड़ दिया है और इस समय 6,000 एकड़ जमीन का मालिक है। बिहार में दरभंगा प्रदेश के पास ओसाई के लिए जो जमीन है उसका ही क्षेत्रफल 600 एकड़ है—जय खेतों की तो बात ही अलग है। बाघमया और घघनली में दो महता के पास क्रमशः 10,000 और 3,000 एकड़ जमीन है।

सभी राज्यों में जमींदारों, जोतदारों और यहाँ तक कि उद्योगपतियों ने बराबर कानून का उल्लंघन किया है और हजारों एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे हैं। सर्वेक्षणों से पता चलेगा कि अंग्रेजों के जमाने के राजा और जमींदार आज भी पहले की ही तरह बड़ी बड़ी जोता के मालिक हैं—इतना ही नहीं, उनकी जोता में निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है।

छोटे और लगभग छोटे किसान लगातार अपनी जातों से हाथ धोत जा रहे हैं और मजदूर बनत जा रहे हैं और बारी बागी से बघुआ मजदूर की श्रेणी में

पहुँचत जा रह है, अपन मालिका के खेता में अपन बा पटा रहे हैं ताकि मालिक का मुनाफा हो सक ।

दरअसल जिन्ह वधुआ मजदूरों की जरूरत होती है, व उन्हें रपत हैं । यहाँ प्रस्तुत उदाहरण से बिहार का एक चित्र उभरता है

जमीन की जोत (व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वामित्व)	वधुआ मजदूरों की संख्या
10 एकर	2 29
10 20 एकर	1 83
20 50 एकर	2 92
50 100 एकर	5 40
100 एकर और इसमें अधिक	16 20

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 84 प्रतिशत वधुआ मजदूर हरिजन तथा आदिवासी हैं और 84 2 प्रतिशत भू-स्वामी सवर्ण हिन्दू हैं । इस सिक्का का दूसरा पहलू यह है कि 11 6 प्रतिशत वधुआ मजदूर सवर्ण हिन्दू हैं तथा 1 4 प्रतिशत भू-स्वामी हरिजन एवं आदिवासी हैं । वधुआ मजदूरों में आदिवासियों की संख्या हरिजनों से ज्यादा है । वधुआ मजदूरों का अस्तित्व उन इलाकों में खासतौर से ध्यान आकर्षित करता है जहाँ सवर्ण महाजन एवं जोतदारों तथा गरीब अभाग हरिजनों एवं आदिवासियों के बीच असमानता भयंकर सीमा तक है ।

आंध्र प्रदेश में माला सम्प्रदाय के कुछ हरिजन भू-स्वामियों के पास जो वधुआ मजदूर हैं व भी हरिजन हैं लेकिन उनके बीच ऊँच नीच का जा फर्क है उसमें व थोड़े नीचे पड़ते हैं । वस्त्रों में वधुआ मजदूरों के मालिक सुरिआ और गाड ह जो खुद ही आदिवासी हैं ।

देखा जाता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आन्ध्रप्रदेशियों के वर्ग चरित्र में भी तबदीली आती है और व अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा न बढ़ि की उम्मीद में सवर्ण हिन्दुओं के तीर-तरीकों की नकल करने लगते हैं ।

वधुआ मजदूरों को रखने के मामले में मालिकों की स्थिति इस प्रकार है लगभग 50 प्रतिशत के पास एक वधुआ मजदूर है 41 प्रतिशत के पास 2 से 4 और 3 प्रतिशत के पास 10 से अधिक है । बर्नार्ड्स में 12 8 प्रतिशत के पास 10 से ज्यादा मजदूर हैं । जसाकि हमने पहले कहा है इस स्थिति में बंसी या बढ़ि जमीन की स्थिति के अनुसार होती है । जलग अलग राज्यों में वधुआ मजदूरों के मालिकों की स्थिति पर एक नजर डालनी होगी

**भारत भर मे**

आदिवासी	5 9 प्रतिशत
हरिजन	2 4 „
निचली जाति	23 7 „
सवण हिन्दू	60 5 „
मुसलमान	4 0 „
ईसाई	0 1 „
अन्य	3 4 „

**आंध्र प्रदेश**

आदिवासी	11 4 प्रतिशत
हरिजन	1 3 „
निचली जाति	6 3 „
सवण हिन्दू	78 5 „
अन्य	2 5 „

**बिहार**

आदिवासी	6 5 प्रतिशत
निचली जाति	46 5 „
सवण हिन्दू	42 0 „
मुसलमान	5 0 „

**गुजरात**

आदिवासी	2 7 प्रतिशत
हरिजन	4 3 „
निचली जाति	7 0 „
सवण हिन्दू	74 8 „
मुसलमान	11 2 „

**कर्नाटक**

आदिवासी	2 7 प्रतिशत
हरिजन	2 1 „
निचली जाति	2 7 „
सवण हिन्दू	82 1 „

मुसलमान  
अ-य

1 4 प्रतिशत  
9 0 "

### मध्य प्रदेश

आदिवासी  
हरिजन  
निचली जाति  
सवर्ण हिन्दू  
अ-य

20 8 प्रतिशत  
4 7 "  
12 9 "  
57 9 "  
3 7 "

### राजस्थान

आदिवासी  
हरिजन  
निचली जाति  
सवर्ण हिन्दू  
मुसलमान  
अ-य

22 8 प्रतिशत  
5 5 "  
11 7 "  
55 9 "  
2 1 "  
2 0 "

### तमिलनाडु

हरिजन  
निचली जाति  
सवर्ण हिन्दू  
मुसलमान  
ईसाई

2 8 प्रतिशत  
84 4 "  
0 5 "  
11 2 "  
1 1 "

### उत्तर प्रदेश

हरिजन  
निचली जाति  
सवर्ण हिन्दू  
मुसलमान  
अ-य

0 2 प्रतिशत  
19 3 "  
76 4 "  
3 4 "  
0 7 "

तमिलनाडु का छोडकर शेष सभी राज्यों में बघुआ मजदूरों के मालिकों के रूप में सवर्ण हिन्दुओं का ही पहला स्थान है। बघुआ मजदूरों में हरिजनों और

आदिवासियों की ही संख्या सबसे ज्यादा है। यद्यपि पहले उल्लेख किया जा चुका है, फिर भी हम अखिल-भारत पैमाने पर बधुआ मजदूरों की संख्या का एक बार और उल्लेख करते हैं

आदिवासी	18 3 प्रतिशत
हरिजन	66 0 ,
निचली जाति	8 9 ,,
मुसलमान	2 7
ईसाई	0 4 ,,
सवण हिंदू	2 7 ,,
अन्य	1 0 ,

जाति और वर्ग के भेद के कारण आदिवासी और हरिजन ही सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं। मालिकों की इस बात में दिलचस्पी रहती है कि उन्हें रुपये उधार देकर फँसा लिया जाये। चूँकि उन्हें निम्नतम धोनी में रखा गया है इसलिए उन पर ऊँची जाति के लोगों का मनावज्ञानिक रूप से दबदबा पहले से ही बना रहता है, जो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। उनकी स्थिति इतनी असुरक्षित रहती है कि उन्हें और उनके बच्चों को कोई भी थोड़े से पैसे देकर गुलाम बना सकता है।

उनके अंदर एक महान गुण यह है कि वे कभी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करते।

### (3)

यह देखा गया है कि सभी मामलों में महाजनो की कोशिश यह रहती है कि वे खेतिहर मजदूरों को बज्रदार बना लें और अपने चंगुल में फँसा लें। खेतिहर मजदूर अपनी लाचारी के कारण ही कज लेते हैं। वे मुख्यतः हरिजन और आदिवासी होते हैं। उनके पास जमानत देने के लिए कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे कज लेते हैं। महाजनो को पता है कि इस ऋण की अदायगी कभी नहीं हो पायेगी और यह चक्रवर्द्ध व्याज की दर से दिनोदिन बढ़ता जाता है—कभी-कभी तो व्याज की दर 100 प्रतिशत होती है।

आमतौर पर खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं होती और आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता जिससे वे कज का भुगतान कर सकें। इसके अलावा वे अपढ़ होते हैं, इसलिए महाजन व खात में उनके नाम जो भी रकम लिखी होती है उसे उन्हें मानना पड़ता है। लेकिन इन सारी बातों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं।

महाजना का मकसद पूरा होता है। उन्हें मस्ते दर पर मजदूर चाहिए जो वे

पा जाते हैं क्योंकि वधुआ मजदूर का लगभग कुछ नहीं देना पड़ता है। उह जा कुछ मिलता है उस पर एक् नजर डालें

ऐसे मामले जहाँ कुछ भी नहीं दिया गया	20 0 प्रतिशत
10 रुपया प्रतिमाह का भुगतान	8 5 ,
11 20 रुपय प्रतिमाह	12 0 ,
21 से 40 रुपय प्रतिमाह	24 0 ,
41 से 60 रुपय प्रतिमाह	19 9 ,
61 से 80 रुपय प्रतिमाह	8 3 ,
80 रुपय या इससे अधिक प्रतिमाह	7 3 ,

ये भुगतान कागज पर दिखाय गये हैं। वास्तविकता इसमें भिन्न है। पान के लिए उन्हें जो दिया जाता है यह बेहद अमानवीय है। फिर भी उस पान के घन्टे में बड़ा चढ़ाकर एक रकम लिख ली जाती है। माय ही भुगतान के रूप में जा दज किया जाता है उसे ब्याज कहकर बराबर कर दिया जाता है।

सामान्य तौर पर एक मजदूर का प्रतिदिन 4 रुपय की दर से भुगतान किया जाता है। कभी कभी पाना भी दिया जाता है। इसके अलावा काम में घट सीमित है। लेकिन वधुआ मजदूर पर इनमें से कोई बान लागू नहीं हानी और उनसे चौबीस घंटे काम लिया जा सकता है।

नियमित मजदूर का काम पर लगान के लिए 120 रुपय प्रतिमाह की 'मूनतम' मजदूरी देनी पड़ती है और वह निर्धारित घंटे के अलावा काम नहीं करता। इसके विपरीत एक वधुआ मजदूर से बिना ज्यादा पसा खच किए 15 घंटे तक काम लिया जाता है। इसलिए वधुआ मजदूर रखन में मालिक को ज्यादा मुनाफा होता है।

ब्याज के भुगतान के रूप में जो कटौती की जाती है उससे बज की मूल राशि में कोई कमी नहीं होती। इसका कारण महाजना के दिमाग से उपाजा एक अनोखा गणित है। वधुआ मजदूर कभी भाग नहीं सकता और 60 प्रतिशत ऐसे मजदूर तथा उनके बंशज भी हमेशा के लिए गुलामी की जंजीर में जकड़ जाते हैं। निम्नावित आकड़ों से उनकी गुलामी की अवधि का पता चलता है

एक वष या इससे कम	29 0 प्रतिशत
एक से दो वष	5 4
दो से तीन वष	1 1 ,
तीन से चार वष	0 4 ,
चार से पाँच वष	0 3 ,

पाच से छह वष	0 2 प्रतिशत
छह से सात वष	0 2 „
सात से आठ वष	0 3 „
आठ से नौ वष	0 1 „
नौ से दम वष	0 3 „
दस वष स अधिक्	0 2 „
आजीवन	2 3 „
वशजा का लेकर अनिश्चित अवधि के लिए	55 7 „
अज्ञात	4 5 „

कज लेते समय जो समझौता होता है उसका कभी पालन नहीं किया जाता । ममझौत का आधार कज को चुकता करना होता है और उस अवधि क पूरा हान पर जिसम कज की अदायगी हो जानी चाहिए, खाते म कज की राशि बढ चुकी होती है । इसलिए गुलामी की अवधि भी बढ जाती है ।

बधुआ मजदूरो म 60 प्रतिशत के पास अपनी काइ जमीन नहीं है—उनके पास खेत जोतन दोन के लिए हल बल भी नहीं है । जिनके पास एक दा एकड जमीन होती भी है वह कज क कारण महाजन के हाथ म पहुँच चुकी हाती है । उनम मे लगभग 20 5 प्रतिशत के पास रहन के लिए घर नहीं हाता और महाजन द्वारा बनवाय गय झोपडो म रहते हे । इस प्रकार महाजन उह घरेलू नौकर की तरह इस्तमाल कर सकते ह ।

यदि बधुआ मजदूर शादी करता है तो उसकी पत्नी महाजन क घर की नौकरानी बन जाती है, जिस कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती ।

रगपुर म—जा अय बगलादश म है—मालिक साथ मजदूरो क लिए खाना बनान के नाम पर कुछ औरता को काम देत ह । दरअसल इन औरता को इसलिए काम पर रखा जाता है ताकि व मजदूरो को लुभाय रखें और व मालिक का काम छाडकर भाग न सकें । इसके अलावा उन औरता के साथ अपनी कामवासना की पूर्ति से व इस शारीरिक जरूरत के पूरा होन के कारण ज्यादा क्षमता के साथ मजदूरी कर पाते ह ।

बधुआ मजदूर तब तक ही लाभदायक है जब तक वह काम कर सकता है । ज्यादातर इनके काम की उम्र 44 वष तक हाती है । इसके बाद उसके स्थान पर उसी क परिवार के किसी कम उम्र के व्यक्ति को रख लिया जाता है । निम्नाविण आँकड़े से स्थिति स्पष्ट है

15 वष या इसम कम	6 1 प्रतिशत
16 से 20 वष	14 7 „



१५	१६ २ प्रतिशत
१६	१९ २ "
१७	१४ ७ "
१८	१२ ३ "
१९ इससे अधिक	१६ ८ "

- २। वर्ष की आयु के बीच वाले सबसे ज्यादा काम के होते हैं। सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि इसी दौरान आदमी अपनी करता है। १५ वर्ष या इससे कम उम्र के मजदूर उतने लाभ-  
 ३। कि उनसे काम निवाह पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए  
 ४। कम है।  
 ५। आम कानूनों के साथ इस बुराई को सामोरी के साथ बरदाश्त  
 ६। सी बुराई है जो सब तक कायम रहेगी जब तक भूमि सबघी  
 ७। बसन नहीं होता।

११

१२

१

१

१

## आंध्र प्रदेश

करीमनगर, महबूब नगर, मेडक, नालगाडा निजामाबाद और वारंगल जिला में बीस हजार से अधिक बंधुआ मजदूर हैं।

आदिलाबाद, अनंतपुर और हैदराबाद जिला में लगभग पंद्रह हजार बंधुआ मजदूर हैं।

चित्तूर और पूर्वी गोदावरी जिलों में बंधुआ मजदूरों की संख्या लगभग सात हजार है।

कुरनूल में इनकी संख्या पांच सौ या इससे कुछ कम है।

(1) लिंगम एक हरिजन लड़का है। उसके पिता ने भू स्वामी से 450 रुपये उधार लिये थे और इसीलिए वह बंधुआ मजदूर बना हुआ है। दलील यह दी जाती है कि उसे प्रतिमाह 28 रुपये दिये जायेंगे जिसमें स कज की राशि का एक हिस्सा काट लिया जायगा।

ईश्वर ही बता सकता है कि कितने पैसे उसकी मजदूरी में से काटे जाते हैं? क्योंकि सूद की राशि दिनोदिन बढ़ती जा रही है। अगर लिंगम कभी काम पर नहीं पहुँचता है तो उसका मालिक प्रतिदिन उसकी मजदूरी से पांच रुपये काट लेता है। अगर लिंगम बीमार पड़ता है तो उसका मालिक उसके घर से घसीटता हुआ उसे खेत तक ले जाता है। 450 रुपये का कर्ज़ डेढ़ साल में चुकता कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा मालिक ने उसके बाप की ज़मीन भी हड़प ली है। लिंगम गुलामी करने के लिए मजबूर है।

(2) निजामाबाद जिले के बसनापल्ली गाँव के बलैया की पीड़ा को कौन समझ सकता है? भू स्वामी ने उसकी गाय, भैंस और बछड़ा सब-कुछ हड़प लिया है। शहर के लोगों को यह समझने में दिक्कत होगी कि भारत में किसी ग्रामीण के लिए, जिसके पास ज़मीन नहीं है अथवा बहुत थोड़ी ज़मीन है, य चीज़ें कितनी

बेचा जा सकता है। जुलाई के समय मवेशियों को बहुमूल्य हाती है। गाय का दूध गरीब लोग गाय, भैंस और बैलो पर काफी किराय पर दिया जा सकता है या की उम्र 55 वर्ष थी। उसने एक भू-स्वामी से निभर करते हैं। 1977 में बल्लू और बदले में उसके खेत पर काम करने के लिए दो सौ रुपये का कज लिया था जो लगा रखा था। सड़लू ने दिन रात जी-तोड़ अपना बारह वर्ष का बेट सड़लू की ताकिक कर्ज का भुगतान हो जाये, लेकिन एक मेहनत करके भू-स्वामी की सेवा, भू-स्वामी ने बलैया को बताया कि उसकी तरफ वर्ष की कठोर मेहनत के बाद हैं।

अभी भी चार सौ रुपये निकलते हुए और सड़लू को भू-स्वामी के घर से वापस बलैया इस पर राजी नहीं है बलैया की भैंस और एक बछड़े को ले लिया बुला लिया। बदले में भू-स्वामी आठ सौ रुपये होती है। दो सौ रुपये का और इन दोनों की मिली जुली चार सौ रुपये हो जाता है और इसके बाद भी कज एक वर्ष की मुलामी के बाद व्यक्ति आठ सौ रुपये वसूल लेता है।

भुगतान का रूप में कज देने वाला भी है जहाँ तेलगाना का विद्रोह हुआ था, जहाँ यह उस आंध्र प्रदेश की तसमिहीनों को सम्बोधित करने और उन्हें जमीन जनता पार्टी की विजय के बाद भू-स्वामी अवसर का कम्युनिस्ट पार्टी ने फायदा देने का वायदा करने का प्रथम उपासकवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी ने उठाया। यही वह राज्य है जहाँ भूमि पर स्वयं उत्तार लाने के बड़े-बड़े बायबे हरिजना और गिरिजनो के लिए 'निगम' के नाम से एक सरकारी संस्था है जो किये थे। इस राज्य में गिरिजन भाग और जमींदारों की साँठगाँठ से गिरिजनो जंगल के ठेकेदारों पुलिस बन गई। आंध्र प्रदेश में पुलिस कभी भी—गलती से की जमीन पर कब्जा कर लेती है कार्रवाई नहीं करती। आंध्र प्रदेश में पुलिस, भी—जमींदारों के खिलाफ कोई बड़ी बड़क की नली गिरिजनो, हरिजनो और जमींदारों और ठेकेदारों—इन सब।

जीताआ की जोर निशाना साधे हैं में एक खबर छपी थी जिस पर ध्यान देने की निसम्बर 1978 में अखबारों पर गोली चला रही है जिन्होंने जमींदारों जबरूरत है। पुलिस किसानों के गुमन के खिलाफ मिलजुल कर संबंध करने के लिए (जिन्हें टोरा कहा जाता है) के दह है। टोरा ही गाँव का मुखिया अर्थात् सरपंच रयत कुली संगम की स्थापना की बाद वैसा होने पर वह बीच-बचाव का काम हाता है। दो गुटा के बीच काई दिनों गुट उसे संबंध अथवा झुत्क देते हैं। विवाद करता है और इस काम के लिए जमीनी की जाती है कि उस व्यक्ति का पसा के हल हो जान के बाद उससे यह हुआ है और दोषी व्यक्ति के पैसे को गाँव के वह लौटा गया जो वेमुनाह साबित। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि टोरा विकास में अस्तमाल किया जायगा लोग पसा का घाटाता करते हैं।

इस प्रकार उन्होंने गरीमा से लाखा रुपये लूटे हैं। चिन्नमयूषल्ली गांव के सरपंच ने सात लाख रुपये का गवन किया है। यह सरपंच कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी का प्रेजिडेंट था और कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का चेयरमैन रह चुका है। इन सरपंच ने एक के बाद एक गांवों को लूटने का सिलसिला चला रखा है और इस लूट के धन से वे परती जमीन तथा पचायती जमीन की खरीद करते हैं।

कभी कभी ये लोग धन्य की राशि के बदले में जमीन ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में जमीन पर पूरा अधिकार होने के बावजूद जमीन का मालिक बहा जा नहीं सकता। सरपंच को पुलिस की पूरी मदद मिलती है। भविष्य में भी उनको यह मदद मिलती रहेगी।

(3) 33 वर्षीय भूमया और उसके परिवार के सदस्य उर्षों तक वधुआ मजदूर बने रहे। वे निजामाबाद जिले के लक्ष्मीदेवीपल्ली नामक गांव में रहते हैं। उसके चाचा ने बारह वर्ष तक जीता के रूप में काम किया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी। भू-स्वामी के पास में मात सौ रुपये का बज्र दिया गया। भू-स्वामी ने उस समय उनकी पन्द्रह बीघा जमीन पर बज्रा कर लिया, लेकिन इतना उसे पर्याप्त नहीं लगा। जसी स्थिति बनी थी उसके अनुसार यदि भूमया के पास पांच हजार रुपये होते तो वह शायद वह अपने बज्र से मुक्ति पा सकता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वह गुलाम बना रहा।

(4) 1977 में मेडक तालुक के शंकरपट गांव के टुड्डू रामुदू की उम्र 25 वर्ष थी। वह जाति से हरिजन है। तेलुगू भाषा में वधुआ मजदूर प्रथा को वेद्वी चाकरी कहते हैं और वधुआ मजदूर को 'जीतागाडू' कहा जाता है। एक वधुआ मजदूर और मालिक के बीच हुए समझौते को जीतम कहते हैं। जीतम का अर्थ मजदूरी भी होता है।

रामुदू के पिता भूमया और उसकी मा की मृत्यु तभी हुई थी जब वह महज आठ वर्ष का था। उसके बड़े भाई ने उसे एक कोमाती अय्या वश्य जमींदार के यहाँ जीतागाडू बनाकर रख दिया था। जीतम के रूप में उस प्रतिमाह पांच रुपये मिलते थे। रामुदू को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसका बड़े भाई ने मानिक से कितना बज्र लिया है?

तीन वर्ष के बाद रामुदू वहाँ से रिहा हुआ। इसके बाद उसका भाई उन तबक वमरम गांव के मुथम रेड्डी नामक भू-स्वामी के घर गया। वहाँ उसने पांच नौ रुपये उधार लिये और रामुदू को जीतागाडू बनाकर वहाँ रखा दिया। वहाँ जीतम के रूप में प्रतिमाह 25 रुपये की राशि मिल गई। दादा मामला में रामुदू का अपनी तनख्वाह के दत्तन नहीं हुए। उनके भाई ने बातें मलिय गये बज्र के अपनी शादी कर ली। उस नवविवाहित पत्नी ने भी मजदूर के रूप में काम शुरू किया। रामुदू दिन रात काम करता था और जान के लिए उसे नाममात्र

मिलता था। हर रोज उसे दोपहर म दो मील तक पैदल चलकर खाना खाने घर आना पड़ता था। मालिक व हाथा उसे रोज भार खानी पड़ती थी। दो साल के बाद वह वहाँ से रिहा हो सका।

उसके भाई ने उसी गांव के माली पटल नगया नामक व्यक्ति से 24 प्रतिशत ब्याज पर तीन सौ रुपये उधार लिये। इस पैसे से उसने रेह्री के कज का भुगतान किया और रामुदू अब नगया का जीतागाड़ू हो गया था। यहा जीतम के रूप म बीस रुपये प्रतिमाह की राशि लेय हुई। हर शाम उसे खान के लिए एक बटोरा उबली हुई मक्काई मिलती थी। नगया के यहाँ उसने एक बप तक काम किया।

इसके बाद उसके भाई ने बमारन गांव के वाला पुचवा नामक व्यक्ति के यहा उसे रख दिया और अपना पिछला कज उतारने के लिए इस व्यक्ति स तीन सौ रुपये का ऋण लिया। रामुदू की एक साल की मेहनत को याज का भुगतान माना गया। उसने तीस रुपये प्रतिमाह के जीतम पर पुचवा के यहा दो बप तक मजदूरी की। तनप्वाट के अलावा उसे एक घपाती और एक बटोरा दलिया भी मिलता था।

अब रामुदू बड़ा हो गया था। उसके भाई ने पटवारी रामुलू से एक हजार रुपये की मांग की। रामुलू ने यह राशि दे दी, लेकिन बदले म रामुदू को उसने पट्टह बप के लिए बहुआ मजदूर बना लिया। उसके भाई ने बकाया ब्याज के रूप म पुचवा को दो सौ रुपये वापस किये। सौ रुपये और पचबीस किला चावल के साथ उसने रामुदू की शादी यल्लामा नामक औरत से कर दी। रामुदू को तीस रुपये जीतम के रूप म मिलते थे। पटवारी ने कहा कि उसे कोई ब्याज नहीं चाहिए।

नया मालिक रामुदू को खाना नहीं देता था। यल्लामा कभी कभी दानक मजदूर के रूप म काम करके एक दो रुपये कमा लाती थी और उसी से अपने और अपने पति के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती। रामुदू का एक लडका पदा हुआ। रामुदू रोज सवेर छह बजे से देर रात तक काम करता और प्रतिदिन खाना खाने के लिए दो मील पैदल चलकर अपने घर पहुँचता।

छह बप के बाद उसके मालिक ने बताया कि कज की राशि बदकर 1,300 रुपये हो गयी है। रामुदू यह सुनकर हक्का तक्का रह गया, क्योंकि उसे न तो कभी मजदूरी मिली थी और न खाने के लिए ही कुछ दिया जाता था। अब वह पूरी तरह बदहवास हो चुका था और समय समय पर पैसे उधार लेकर शराब पिया करता था। उसने तय कर लिया था कि अपने बेटे को यह जीतागाड़ू नहीं बनने देगा। यह कहानी तेलगाना के एक किसान की है जहाँ आपका के गिलाफ लड़ाई आज भी जारी है।

(5) मेडन ताल्लुक म अरुमुलुपल्ली गाँव के सिद्दीरामुलू की उम्र 1977 म

21 वर्ष थी। 'स्वतंत्र तेलगाना' आंदोलन जब शुरू हुआ था और शिक्षा संस्थाएँ बंद हो गयी थी, उस समय वह छोटी कक्षा में पढ़ता था। उसने काम की तलाश शुरू की। एक वर्ष तक वह दैनिक मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। उसका बड़ा भाई भी इसी तरह अपनी जिंदगी गुज़ार रहा था। परिवार में एक बीघे से भी कम जमीन थी। उसके पिता उम्र थोड़ी सी जमीन पर ही खेती करते थे और अपने एक जोड़ा भूसे किराये पर देते थे। इससे उन्हें प्रतिदिन दस रुपये की आय हो जाती थी।

एक कहावत है—चार दिनों की चादनी फिर अँधेरी रात। सिद्दीरामुलू का बड़ा भाई आडे की एक रात में आग के अलाव की बगल में सो रहा था। उसके कपड़ा में आग लग गयी और वह जल कर मर गया। भाई की मृत्यु से परिवार की आय में काफी कमी हुई गयी। सिद्दीरामुलू पड़ोस के शहर में मजदूरी करता था। घर में जब खाने का सबूट पड़ा हो गया तो उसके पिता ने अपने भूसे बेच दिये।

अब इस परिवार पर मुसीबत के बादल मँडराने लगें। सिद्दीरामुलू की दादी की मृत्यु हो गयी और उनके अंतिम संस्कार के लिए घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे। सिद्दीरामुलू के पिता ने बँबट्या से दो सौ रुपये उधार लिये और अपने बेटे को सात वर्ष के लिए उसने यहाँ जीतागाड़ बना कर भेज दिया। उस समय इसकी उम्र 13 वर्ष थी। चार वर्ष तक उसने मालिक के मवेशियों को चराया। बाद में जयान होने पर उसे खेत जानने के काम में लगा दिया गया। यहाँ अविश्वसनीय रूप से मेहनत करनी पड़ती थी—कभी-कभी तो उसे एक सास में आठ घंटे तक हल खींचना पड़ता था।

सिद्दीरामुलू के लिए अब वे दिन जब वह स्कूल जाता था, जब उसके परिवार के लोगो को बड़ी मेहनत के बाद ही सही भरपेट खाना तो मिलता था अब अतीत की यादगार बनकर रह गये। उसके मालिक ने सात वर्ष के बाद उसे अपनी गुलामी से आजाद किया। इसके बाद वह पास के एक गाँव की चीनी मिल में काम करने लगा। यहाँ उस प्रतिदिन पाँच रुपये मिलते थे। उसके जीवन में यह सबसे सुखद दिन थे। लेकिन गन् की फसल के कटने के साथ ही उसका काम भी खत्म हो गया और वह बंगोजगार हो गया था।

उसके पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने रमया कापू से चार सौ रुपये उधार लिये और राजम्मा नामक लड़की से उसकी शादी कर दी। सिद्दीरामुलू अब रमया का जीतागाड़ हो गया था और कापू ने फैसला किया कि वह जीतम के रूप में उसे प्रतिमाह बीस रुपये देगा।

कुछ वर्षों बाद इस गाँव में 42 बघुआ मजदूरों के मसले को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आंदोलन शुरू किया। जब आंदोलन चरमबिंदु पर पहुँच गया तब

सरकार की नींद टूटी। गांव में एक छठ विनाश अधिकारी और एक थर्म अधिकारी पहुँचा। उन लोगों ने जमींदारों और वधुआ मजदूरों का बुनाया और इस बैठक में तमाम तथ्यों का उद्घाटन हुआ।

अब तक की प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति का दो सौ रुपये का वज्र व बदले आठ रुपये प्रतिमाह बतन पर मातृक के लिए जीतागाड़ बनाया जाता था। सात वर्ष तक जीतागाड़ में काम करके और उसे एक पैस का भी भुगतान न करके मालिक 6 720 रुपये कमाता था। साथ ही अगर जीतागाड़ का उसके थर्म के बदले उचित मजदूरी दी जाये तो मालिक को सात से आठ हजार रुपये खर्च करना पड़ता।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने एक न्यूनतम वेतन कानून पारित कर रखा है। इस कानून के अनुसार दैनिक मजदूरी करने वाला का तीन रुपये पांच पैसे और मासिक बतन पर काम करने वाला मजदूर का 91 रुपये 63 पैसे प्रतिमाह दिया। 100 रुपये प्रति वर्ष मिलने चाहिए। इन दरों को काफी पहले सरकारी तौर पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन किसी भी मूल्वासी न कमी भी इन दरों पर भुगतान नहीं किया।

1971 की आगमना के अनुसार आंध्र प्रदेश में सेलिहूर मजदूरों की संख्या 68,29,000 थी। 1954 में राज्य में पहली बार न्यूनतम वेतन कानून बना। बाद में 1961, 1966, 1968 और 1974 में इसमें संशोधन किया गया। अंतिम संशोधन आदोलन से काफी पूछा हुआ था। जामिंदारों और मरचारी तौर के मुताबिक पैसे देने की बात मान ली।

सिद्दीरामुन्नु जैसे लोगों के दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। बाढ़ों से पैसे का सन के कारण वे मामूली-भी तनपवाह पर जीतागाड़ बने रहना नहीं बरदाश्त करेगा। बहुत दिनों से वे गुलामी कर रहे हैं—निश्चय ही उनके मद में जा पता चकटा हुआ होगा वह उनका वज्र उतारने के लिए काफी होगा।

पार्टी के लोग कितने अच्छे हैं। उनके आदोलन की ही वजह से तो दोना अपमान यहाँ तक आया। जमींदार भी उनकी बात मान गया। सभी जीतागाड़ खुशी में पागल हो रहे थे।

लेकिन यह एक झूठी खुशी थी। दो महीने बाद जमींदार ने मरचारी बतन दरों के मुताबिक पैसे दो से इक्का कर लिया। जीतागाड़ों को अपने सन पसोने में ही वज्र उतारना होगा।

हरिजन समुदाय के उठे-बूढ़े न जमींदारों में बातचीत की जो आखिरकार सरकारी दर से आधी मजदूरी देने को मयाब हो गये। दाना पक्ष दम पर राजी हुए कि मासिक बतन के रूप में 50 रुपये लिया जायेगा।

सिद्दीरामुन्नु वज्र उतारने के लिए फिर महनन करने लगा। राजम्मा भी

दैनिक मजदूर की हैसियत से काम करने लगी। वह 3 रुपये रोजाना कमाने लगी। सिद्दीरामुलू का उम्मीद हो गयी कि वह चार महीने में कज चुकता कर देगा।

(6) भेडक ताल्लुक के कूचनापल्ली गांव के शिवराजया के बेटे रामचंद्र को यह याद भी नहीं है कि उसके पिता ने नागया से कज लिया था। उसे बस इतना ही याद है कि वह भात बप की उम्र से ही नागया का जीतागाड़ू है। उसे जीतम के तौर पर प्रतिमाह 8 रुपया और दोना वक्त का खाना मिलता था। अपनी तनहाह उसे कभी नहीं मिली। वह नागया के साथ छह साल तक रहा। उसके पिता की मृत्यु हो गयी। उसके बड़े भाई उस अपन साथ ले गये और उहाने करनम रामुलू का यहा जीतागाड़ू बना दिया। उसके नये मालिक ने जोर दिया कि रामचंद्र की शादी कर दी जाये। रामचंद्र का बड़ा भाई भी यही चाहता था। रामुलू ने 37 प्रतिशत ब्याज पर 450 रुपये उधार दिये और जीतम की राशि बढ़ा कर 18 रुपये कर दी। दुल्हन की कीमत 100 रुपये जदा करन के बाद रामचंद्र ने बैकम्मा से शादी कर ली।

450 रुपये पर सालाना ब्याज 166 50 रुपये था। रामुलू का पता था कि रामचंद्र कभी यह पमा नहीं दे सकता। वह हर रोज उसकी पत्नी बैकम्मा के सामने रामचंद्र का बज्रतापूवक पीटता था और बैकम्मा असहाय नजरो से उसे देखती रहती। जब रामचंद्र के बड़े भाई ने इसका विरोध किया तो उसे भी खूब पीटा गया। इस दुदशा का दखवर हरिजन समुदाय के पडोसियो ने सुझाव दिया कि रामचंद्र को अपन दोना बैल बेचकर यह कज उतार देना चाहिए। रामुलू पैस नहीं चाहता था—उसकी निगाह उन दोना बला पर थी। अगर रामचंद्र बला को बेच पाता तो कज उतारने के बाद उसने पास कुछ पैस बचे रहत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामुलू ने जब उसे अनिम तौर पर अपने चगुल में छोडा तब तक वह कगान बन चुका था।

तेलगाना के विरप्यात जिले में रामचंद्र को सचमुच गुलामी से कौन मुक्ति दिला पायगा? उस कोई उम्मीद नहीं थी। वह एक हरिजन था और जीतागाड़ू था। वह दीन हीन था।

बैकम्मा बीमार पडी और उसे लथमी रेडडी से कज लेना पडा। अब एक बार फिर वह जाल में फँस गया था। 1977 में वह पहले ही रेडडी के यहा चार साल वधुआ बनकर काम कर चुका था। ब्याज की दर 39 प्रतिशत थी। रामचंद्र का अपनी ना, पत्नी और पांच साल की एक बहन की देखभाल करनी पडती थी। दाना माहिलाएँ भी दो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करती थी। रामचंद्र को न तो एक पसा मिलता था और न उसे खाने को कुछ मिलता था। उसका परिवार 4 रुपया महीने की दैनिक आय पर चलता था।

क्या उसे याद है कि उसके पिता के पास कभी 4 एकड़ जमीन थी? शिव



राज्या के पास बसे यह जमीन थी रामचंद्र का नहीं पता। शायद 1960 के दशक में सरकार ने जा जमीन बांटी थी उस पर शिवराज्या का स्पष्ट अधिकार दिया गया था। शिवराज्या ने फिर सेत जातन-धाने के लिए सरकार में 600 रुपये का बज्र लिया। लेकिन खेती नहीं हो सकी, क्योंकि जा पूजा थी वह परिवार का पेट भरने में ही खच जा गयी। इस बीच सरकार ने म्याज की अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू किया। एमी हालत थी और ऐसी हालत में अज कोई गरीब किसान बचने में हो बिठल रेंडडी जसा धनी भू-स्वामी के चुपचाप यह देख सकता है? वह 100 एकर जमीन दो ट्रक्टर एक जीप, मजाना ट्राइडेंट रेडिया का मालिक था और उसका गले में सने की एक मोटी जूरी लटकती रहती थी।

उसने शिवराज्या की जमीन ले ली और सरकार को मूल तथा मूद दाना धुवता कर दिया। शिवराज्या की 4 एकर उपजाऊ जमीन के धूल में उसने 1 एकर बजर जमीन दे दी। उसे अपन जानबरा का घराने के लिए इस जमीन की सत जरूरत थी। गरीब किसान का इसके लिए राजी होना पडा। बस बागज पत्र उसका नाम में रह गया।

1968 में रेडडी उस बात का जातने लगा। पिछले दस वर्ष स रेडडी इमी तरीके से अपनी जमीन बटाता रहा था और अब तक उसने कम-से-कम 20 परिवारों को बगल बना दिया था। ये सभी हरिजन थे। इसी तरह की परिस्थितियों में उह सरकार द्वारा जमीन दी गयी थी और उहान सरकार से बज्र के रूप में काय पूजा ली थी। बज्र की अदायगी के लिए उनकी जार से दबाव पडने पर वे बिठल रेडडी के शिकार बन और बिठल रेडडी ने उनकी आर से सरकार का बज्र उतार कर उनकी सारी जमीन हड़प ली। यह एक अजीब विडम्बना थी। जमीन के मालिक किसान थे पर फसल बट कर रेडडी के यहाँ जाती थी।

1977 में रामचंद्र ने जिला कलक्टर के पास अर्जी दी और अपील की कि उसे वह जमीन वापस दी जाये जिस पर उसके पिता का कभी स्वामित्व था। अधिकारियों ने उसे बताया कि अब उस जमीन का मालिक रेडडी है क्योंकि शिवराज्या ने रेडडी के हाथ जमीन बेच दी है। रेडडी के पास अपने दावे की पुष्टि के लिए अंगूठे का निशान लगा एक दस्तावेज भी था। वह पिछले दस वर्ष से इस जमीन की फसल पा रहा था। रामचंद्र के पास जमीन सम्बन्धी बागजात थे, फिर भी जमीन पर उसका कोई हक न था। रामचंद्र अब क्या कर सकता था? उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उसके पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि रेडडी के पास जो दस्तावेज है वह जाली है। अगर वह मामले को आगे बढ़ाता तो उसके परिवार के सदस्यों की खिदमी खतरे में पड जाती। वह किससे विरोध करता? कौन उसकी बात सुनेगा? अगर वह गांव के





स्थानों की आसू भरी कहानियाँ हैं।

जनता सरकार के पतन के बाद पारम्बीया, निपरा तथा अन्य स्थानों पर न जाने कितनी लाशें मिलीं।

बिहार एक विशेष क्षेत्र है। नालंदा जिले के काइला में पुलिस ने जमींदार के गुंडा द्वारा हरिजनों का कत्लेआम चुपचाप देखा। बिहार में पुलिस और प्रशासन एक सदिग्ध स्थिति में हैं। उन्होंने जनता में अपने प्रति तनिक भी विश्वास का भाव नहीं पैदा किया। हरिजनों और आदिवासियों के दमन में पिछले 25 वर्षों में इनकी जा भूमिका रही है उस पर अलग में मुकम्मल रिपोर्ट लिखी जा सकती है। बिहार में जो घटनाएँ घटीं वे वही ओर देखने में नहीं आती।

26 जून, 1979 को राहतास जिले के ममहता गांव में एक पुलिस इस्पेक्टर एक सब-इस्पेक्टर और हमियारबंद पुलिस की तीन टुकड़ियों ने जमींदारों के साथ साठ-गाठ करके हरिजनों की बस्ती पर धावा बोल दिया। उन्होंने यहाँ के लोगों को पीटा और सारा सामान लूट लिया। चार हरिजनों की हत्या के बाद, वे वहाँ से भाग गये।

क्या उन्हें कोई सजा मिली? दोनों जफतरों को बस मुअ्तिल कर दिया गया। सजा का सवाल बाद में पड़ा होता है। ऐसा क्या होता है?

बोधगया बिहार के पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ के मंदिर का महत्त्व बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से है। उनके पास 30,000 बीघा बेतामी जमीन है। छात्रों के एक दल ने इस जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के बीच बांटने की काशिश की। महत्त्व के गुंडा न छात्रों पर बमों और बंदूकों में हंगला किया और उन्हें तितर बितर कर दिया। इस बारदात में चार छात्र मारे गये और अनेक घायल हुए। यह घटना 9 अगस्त, 1979 की है।

बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किये जान से सम्बंधित जो कानून है उसमें 'हलवाहा' शब्द कहीं नहीं आता है। यह प्रथा पटना जिले में प्रचलित है। बाढ़ सब डिवीजन में जमींदार लोग अपनी जमीन पर बेतमी करने के लिए हरिजनों को लगाते हैं। जो म्वनन मजदूर है उन्हें 'छट्टा' कहा जाता है। हलवाहा का 'बंधुआ हलवाहा' कहा जाना है क्योंकि वे बंधु संधित हैं।

(1) रामपुर डुमरा गांव के हलवाहा भूमिहीन हैं और वे मामूली-मध्यम जमींदारों के नेता में काम करते हैं। उन्हें गांव से बाहर किसी अन्य काम-चारी के लिए काम करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें गांव से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं मिलती—शादी-प्याह जिस सामाजिक समारोह में भी भाग लेने वे गांव से बाहर नहीं जा सकते। हलवाहे के परिवार के सभी सदस्य उस मालिक के गुलाम समझे जाते हैं। इस प्रकार एक आदमी का मामूली-मध्यम देकर पूरे परिवार में काम लिया जाता है। उन्हें बाहर स्वतंत्र रूप में काम करने की

घोड़ा उकमाने के बाद राजस्व बोर्ड ने बताया कि जुलाई 1964 में राज्य सरकार ने कहा गया था कि वह तेलंगाना में इस नियम को लागू करे। राज्य सरकार इस मसले पर चुप रही।

1975 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लागू किया गया।

हमने 1977 से सम्बंधित कुछ मामलों का जिक्र किया है।

## बिहार

पलामू जिले को सही अर्थों में बंधुआ मजदूर प्रदेश कहा जा सकता है। यहाँ ऐसे अभागों की संख्या 40 हजार में भी अधिक है। सारन चम्पारण मुंगेर और सयाल परगना में से प्रत्येक स्थान पर दस हजार से बीस हजार बंधुआ मजदूर हैं और गया और मुजफ्फरपुर में से प्रत्येक में पाँच हजार से दस हजार। पटना और भागलपुर में प्रत्येक स्थान पर इनकी संख्या पाँच सौ से पाँच हजार तक है। सहरसा और दरभंगा में इनकी संख्या कम से कम पाँच-पाँच सौ है।

बंधुआ मजदूर प्रथा का मूल कारण हरिजन और आदिवासियों की आर्थिक असहायता ही है। यह प्रथा तब तक जारी रहेगी जब तक आबादी का बहुमत सब कुछ छोड़ कर गरीबी की रक्षा सनीचे बना रहेगा और एक अल्पमत समूह पर निर्भर रहेगा जिसकी सारी जमीन पर भिन्विगत है।

पलामू में कई बार लोग का ध्यान आकर्षित किया है। हर बार घबरें गलत नहीं हो सकती। ध्यान देने की बात है कि ऊपर जिन जिलों का उल्लेख किया गया है उनमें भाजपुर शामिल नहीं है। ता भी 14 अप्रैल 76 के अगवार में छपी एक खबर में पता चलता है कि इस इलाके में भी यह प्रथा प्रचलित है।

राज्य सरकार ने 1976 में पलामू में कुछ दूर-दराज के इलाकों का छोड़कर शेष इलाकों में इस प्रथा को खत्म करने की बात कही थी। उसने कुछ कानूनी शक्तों का सहारा लेकर यह दावा किया था कि अपने मामलों में वह कुछ मजदूर बंधुआ नहीं कर जायेंगे—उनकी यह स्थिति गलत होने का कारण है।

वास्तविक ताबीर बहुत खुरता लिय हुआ है। बिहार के अलावा दूसरा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ सम्भ्रता का मार मान्डा को दखिनार कर हरिजन का साथ पत्नी बरगता और अमानवीयता का साथ पत्नी आया जाता हो।

बिहार का सबसे जमीनदार पर दम काई एक नहीं पत्ता कि कानून में जिन का शामिल है। जनता सरकार का जिन में हरिजन का बरगता तरगहार हुआ और भागिनत गाँवों में जिन का साथ बनातरा की पत्नी हुआ। बसलो पयगदीर मुसलपुर दिरहौनी कानून गाँव, जिनानुपुर जमता स्पेडा बिभामपुर, गिररी, बादमा, पानपुर परगाँव रिमई, अन्वारा तथा अन्य कई

स्थाना की औसत भरी वहानियाँ हैं।

जनता सरकार के पतन के बाद पारसबीघा गिरा तथा अन्य स्थाना पर न जाने बितनी लाश गिरी।

त्रिहार एक विशेष क्षेत्र है। नालदा जिले के काइलास पुनिम ने जमींदार के गुंडा द्वारा हरिजना का बत्तेआम चुपचाप देखा। त्रिहार में पुलिस और प्रशासन एक सदिग्ध स्थिति में हैं। इन्होंने जनता में अपने प्रति तनिक भी विश्वास का भाव नहीं पैदा किया। हरिजना आर आदिवासियों के दमन में पिछले दस वर्षों में इनकी जो भूमिका रही है उस पर अलग से मुकम्मल रिपोर्ट लिखी जा सकती है। बिहार में जो घटनाएँ घटी हैं वही और देखने में नहीं आती।

26 जून 1979 का रोहतास जिले के समहता गांव में एक पुलिस इस्पेक्टर, एक सब इस्पेक्टर और हथियारबंद पुलिस की तीन टुकड़ियों ने जमींदारों के साथ साठ गांठ करके हरिजना की बस्ती पर घावा बोल दिया। उन्होंने यहाँ के लोग का पीटा और सारा सामान लूट लिया। चार हरिजनों की हत्या के बाद, वे वहाँ से भाग गये।

क्या उन्हें कोई सजा मिली? दोना जफसरा का बस मुआतिल कर दिया गया। मजरा का सवाल बाद में पैदा होना है। ऐसा क्या होना है?

बोधगया बिहार के पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ के मंदिर का मूर्त बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से एक है। उसके पास 30,000 बीघा बेनामी जमीन है। छात्रों के एक दल ने इस जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के बीच बांटने की वाशिश की। महल के गुंडा न छात्रों पर बर्सा और बंदूकों में हमला किया और उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस बारदात में चार छात्र मारे गये और अनेक घायल हुए। यह घटना 9 अगस्त 1979 की है।

बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किए जाने से सम्बंधित जा 'गानून है उसमें हलवाहा' शब्द वही नहीं आता है। यह प्रथा पटना जिले में प्रचलित है। बाढ़ सय-डिवीजन में जमींदार लोग अपनी जमीन पर बेती करने के लिए हरिजनों को लगाते हैं। जो स्वतंत्र मजदूर हैं उन्हें 'छुट्टा' कहा जाता है। हलवाहा का 'बधुआ हलवाहा' कहा जाता है क्योंकि वे बजस बंधित हैं।

(1) रामपुर डुमरा गाँव के हलवाहा भूमिहीन हैं और वे मायूनी से पैसे पर जमींदारों के बेता में काम करते हैं। उन्हें गाँव से राहुर किसी अन्य काम चारी के लिए काम करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें गांव से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती — शादी-ब्याह जस सामाजिक समारोहों में भी भाग लेने से गांव से बाहर नहीं जा सकते। हलवाहा के परिवार के सभी सदस्य उस मालिक के गुलाम समझे जाते हैं। इस प्रकार एक आदमी की मामूली में पैसा देकर पूरे परिवार में काम लिया जाता है। उन्हें बाहर स्वतंत्र रूप में काम करने की

इजाजत नहीं मिलती। वे चोगीसा घंटे अपने मालिक के लिए काम करते हैं। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दर से आधी मजदूरी मिलती है और वह भी अनाज के रूप में। यह प्रतिदिन लगभग 1.25 बिन्नी मक्ई या चाई और अनाज तथा थोड़ा-सा नारंग होता है। वे हलवाटे कई पीढ़ियाँ से भूमिहारा व गुलाम हैं। उनके बीच एक बहावत चलती है कि अगर मालिक की मक्ई या चाई ताँहल बाह का लडवा भी बड़ा हुआ कर हलवाहा बनगा। सरकारी कानून निर्माताओं के अनुसार मेतिहर मजदूरों की तुलना में हलवाह बेहतर स्थिति में हैं।

रामपुर-डुमरा में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भूमिहारा द्वारा चलाए जाते हैं। भूमिहार छात्र उन हरिजन छात्रों का पीछे हैं जो कृष्ण में जान की कोशिश करते हैं। प्रधानाध्यापक भुनेश्वर सिंह गाँव के मुखिया का भाई हैं और एक बदमाश जानदार हैं। उसके यहाँ मिहेश्वर पामवान नामक एक हलवाहा है जिसने 800 रुपये उधार लने का कारण रिना रिमी बताना था 18 रुप उमकी गुलामी की। दस जादमी ने हाईवेस्ट में एक मुक्त्मा दायर किया और जीत गया — अनागत न भुनेश्वर सिंह को आदेश दिया कि वह सिद्धेश्वर पामवान को 7 300 रुपये द। लेकिन अचानक मिहेश्वर की मृत्यु हो गयी और उमका एक मात्र उत्तराधिकारी 17-वर्षीय पुत्र हरप्रोत बड़े रहस्यमय ढंग से घायल हो गया।

(2) शामली पासवान पिछले 15 वर्षों से उम सिंह का हलवाहा है। पिता की मृत्यु के बाद उम 13 बट्टा जमीन और बज का एक बाँझ प्राप्त हुआ था। उसका पिता ने अपने मालिक उदय सिंह से दामन मक्ई उधार ली थी। वह उदय सिंह का हलवाहा बन गया और अपने मालिक की जमीन जानने लगा। कमल को उदय सिंह से जाता था। 1976 में शामली ने माँचा कि ऋण विमुक्ति आदेश न पुरान बज को रद्द कर दिया है और फिर उसने अपनी जमीन जानने-बाने की तयारी की। उदय सिंह ने उम भार डालने या किसी फौजदारी के मामले में फँसा देने की धमकी दी। शामली ने अपनी आज्ञा की सारी बागिशें छोड़ दी।

(3) जमुना राम भुनेश्वर सिंह का पिता हृदय सिंह का हलवाहा है। वह एक महीने तक बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। हृदय सिंह ने गुंडे उसके घर आए और उसके हाथ पर बाँध कर एक डंडे में टाँग कर ले गये। वे उसे नंगा करके तब तक मारते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। वे उसे मरा हुआ समझ कर सड़क पर ही छोड़ गए — उसकी चोटा में लगातार खून बह रहा था। उसका बेटा शामली पाँच के लिए पुलिस और जिलाधीश के महा चक्कर लगाता रहा, पर कुछ भी लाभ न हुआ।

क्या सारे हलवाहे बधुआ मजदूर नहीं हैं?

(4) पलामू के योगीखुरा गाँव के एक सवण हिन्दू की हरकतों से इस पाश-विक प्रथा की गम्भीर तस्वीर बहुत साफ उभर आती है।

यहाँ सेवकिया और कमिया जैसे कई तरह के बहुआमजदूर हैं। इस व्यक्ति ने एक नये तरह के बहुआमजदूर बनाये हैं जिसे घरमर कहते हैं।

1976 में राजनीतिक तौर पर उसका बड़ा दबदबा था। वह बिहार राज्य लाख विपणन सहकारी महासंघ में एक उच्च अधिकारी था। देश में जितना लाख पदा होता है उसका 50 प्रतिशत हिस्सा बिहार में होता है और इसमें से भी 34 प्रतिशत अकेले पलामू में होता है। लाख के नियाम से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय होती है। इससे उत्पादक हरिजन और आदिवासी हैं।

उनके हिता की रक्षा के लिए महासंघ को जिम्मेदारी दी गयी कि वह उत्पादक से 3 रुपये प्रति किलो की दर से लाख की खरीद करें। इस व्यक्ति ने खरीद के लिए अपने एजेंट रखे जिन्होंने 25 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति किलो की दर से खरीद की। खरीद वाले रजिस्टर में 3 रुपये प्रति किलो की दर ही दर्ज की गयी और उत्पादक के अंगूठे के निशान लेकर इसे एकदम दुरुस्त कर लिया गया। इस प्रकार इस व्यक्ति ने हर किनोग्राम पर लगभग ढाई रुपये बना लिये। उसकी आय का सबसे बड़ा साधन सिंचाई विभाग था। उसके संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य इस विभाग में ठेकेदार व और उनका दामाद इस विभाग में ही एक उच्च पद पर था। उसके एक रिश्तेदार का जिले के शिक्षा बोर्ड पर नियुक्त था हालांकि उसकी शिक्षा ऐसी थी कि वह ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। जबरदस्ती प्रभाव वाले इस महान व्यक्ति ने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया जो उसके गुणगान करता रहता था।

अपने राजनीतिक प्रभाव, पैसे और सरकारी मदद से इस व्यक्ति ने हरिजनों और आदिवासियों की उस जमीन को लूट लिया जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी जिसे उन्होंने खरीदा था या भूदान, कोदवार और अविभोक्ता के जरिए जिस पर उनका स्वामित्व था।

इस तरह की जमीन गरीब किसान जोतते हैं।

उन्हें घरमर कहते हैं। फसल कटने के समय इस महापुरुष के रिश्तेदार आते और उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जबरदस्ती घरमरों में ले लेते। घरमरों से ये लोग अपने खेतों पर बिना मजदूरी के काम भी लेते।

इसके बाद सेवकिया और कमिया आते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस महापुरुष की कैंदू पत्ता के व्यापार पर भी इजारेदारी थी।

संभवतः पुलिस और वन विभाग पर भी उसकी इजारेदारी थी।

(5) खेत जोतने का काम हलवाहा करता है और चरवाहा मवेशियों को चराता है।

पलामू जिले के हरिहरगंज ब्लॉक में स्थित श्रीपालपुर गांव के श्यामा चमार ने पास के गांव मथुराना के राजपूत करीमन सिंह से चालीस रुपये उधार



लिया था। इससे एवज म उमन सबकिया के रूप म 14 साल तर मजदूरी की। शुरू म बज लेने के दो साल बाद उसने फिर 60 रुपये लिए। 14 साल तक काम करने के बाद उसने बेटे बामुन्द के 15 वष तक काम करना पड़ा। उसी 15 वष की गुनामी 1978 म पूरी हुई और यह अभी भी वही काम कर रहा था। इससे बामुन्द बज अभी उतरा नहीं था। इसलिए बामुन्द के बेटे नरेश ने अपना पिता के साथ काम करना शुरू किया। उनकी उम्र 15 वष है और अब तक कई साल उसने चरवाहे के रूप म गुजारा दिये है। नरेश को कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती है। 1976 म एक अफसर उसे रिहा कराने आया था, लेकिन बामुन्द को रिहा नहीं किया जा सका। लेकिन उसके मालिक ने जमाने का कि उसने अधिारी इसमें काफी मिलचस्पी ले रहा है, तो उसने बामुन्द का मारना पीटना बन्द कर दिया।

(6) बधु म मजदूर प्रथा के प्रतीक का बमिया मजदूर का उत्थापन प्रासंगिक होगा। उनके नाम का पता नहीं है।

(7) एक बनिये का बिल मर गया। उस बनिये ने अपने बमिया को जुए के नीचे धल की जगह लगा दिया और बाजार तक गाड़ी धिक्कात हुए ले गया।

(8) 1976 म पनामू के उपायुक्त ने वहाँ गये सर्वेक्षण दल को एक व्यक्ति के बारे म बताया। इस व्यक्ति ने केवल 56 पस बज लिये थे, इससे बदले म उसे जिन्गी भर सबकिया बनकर रहना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि बिहार और उड़ीसा म बधुआ मजदूर प्रथा 1920 म ही समाप्त कर दी गयी थी।

## दादरा और नगर हवेली

1961-62 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र म बलवा प्रणाली थी। आमतौर पर दुगला के आदिवासी बलवा होते थे। उन्हें 2 से 20 गुठा (जमीन की एक इकाई) जमीन दी जाती थी। मालिक बीज और बल सप्लाई करता था। इस जमीन की फसल बलवा ले सकते थे। उन्हें मालिक की जमीन पर अपने हाथ के बनाने की भी इजाजत थी। बदले म उन्हें मालिक के दल पर काम करना पड़ता था। अपने मालिक की अनुमति के बिना वे वही नहीं जा सकते थे। उन्हें प्रतिदिन 50 पैसे भी मिलते थे। पुरुष भेतिहर मजदूर का प्रतिदिन एक रुपया 75 पैसे और महिलाओं को एक रुपया 25 पैसे मिलते थे।

1968-69 की एक सरकारी रिपोर्ट म बताया गया है कि बलवा प्रणाली सही ज्यों म बधुआ मजदूर प्रणाली नहीं थी। बज की राशि कम थी और इस लिए कोई बानूनी बन्द नहीं उठाया गया।

## गुजरात

घदोदरा और पंचमहल जिला में ये प्रत्येक में बीस हजार से अधिक बहुआमजदूर हैं। बलसाल, सुरे द्रागमर, सूरत, राजकोट और महेसाणा जिलों में ये प्रत्येक जिले में दस से बीस हजार बहुआमजदूर हैं। अहमदाबाद, भटान, पण और साबरमती जिला में 5 सौ से दस हजार बहुआमजदूर हैं। अमरेली, धारामाठा, भावनगर, मेडा और दास जिला में पाँच सौ से पाँच हजार बहुआमजदूर हैं।

गुजरात ने 1975 को महात्मा गांधी जी के बड़े उद्योगपति, सहकारी युद्ध समितियाँ, एक अलग संसृति अपनी विशिष्ट पला और बेसन आग राजनीति में प्रदान किये हैं। पाठना के सामान शायद हम बहुआमजदूरों में अलग अलग उदाहरण न पेश कर सकें। इसकी जगह पर हम हरिजन पर हो रहे आसित अत्याचारों की दास्तान सुनाएँगे। ये हरिजन बहुआमजदूर हैं जिन्हें हाथी या हलपति कहा जाता है।

1 जनवरी, 1975 का अहमदाबाद जिले में गाना गाय गाँव में 25 हरिजन अपनी जान बचाव के लिए रात में अंधेरे में गाँव से भाग गये। वे सुरिधी पहुँच और पुलिस द्वारा पाड़े जाने तक नहीं रहे। उन्होंने 6 अवसरों का 'दृष्टिमा एनसप्रस' के सवादानता का अपनी कहानी सुनायी। वे टकम बलपटर (गिरादार) गुजरात नथुजा के भय से गाँव से भागे थे।

इस व्यक्ति ने 1 अवसरों की रात में दास नामक एक हरिजन युवक पर हमला किया था। मौते पर अब लागा था पट्टा जा के बाद वह पीछे हट गया, पर बाद में जान की घमरी द गया। दगा जा हरिजन लोग गाँव छोड़कर भाग गये।

हरिजनों ने हमला ही इस आदमी के अत्याचारों को चुपचाप बरतार किया। उन्होंने हमारे लिए कुछ गाने और बगमजदूरी पाय अपना श्रम किया। उन्होंने सभी हमारी शिवायत नहीं की। गिरादार एक मरगारी बगमारी होता है। उससे यही उम्मीद थी कि वह अत्याचारी होगा। अब पसल बगमारी का ममम नजरीय आन पर उमरा अत्याचार बढ़ता गयाभाविक था।

21 9 78 का भावनगर जिले के बलपुत्र गाँव में भू ग्यामिमा। सीन बगमारी नौ हरिजनों का मार्ग पीटा। पमममम आठ मारी मार्ग गये।

8 8 77 का अगवाग में यह गमम छी थी कि उममि भावगम, गांधी नगर और गमगरी जिला में गमम हिंदुओं। हरिजनों का पीटा। पमममम जिले में मलगात गाँव में पुलिस ने हरिजनों की शिवायत दगा गरी म दगार कर लिया। 1974 में सुरद्रागम जिले में गेमगपुर गाँव में आन हरिजनों का गये।

1977 में भी हरिजनों को सरकारी कुआ और नला से पानी लेने की इजाजत नहीं मिली। होटला और रेस्तराँआ में उनके लिए अलग जेठें हाती थी। सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सावजनिक बाहना में चढत समय अपमानित किया जाना उनके लिए आम बात थी।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन राज्यपाल ने प्रशासन पर जार दिया था कि यह रनमलपुर हत्याकांड के अभियुक्ता के पिताफ वारवाई करें। उन्होंने हरिजनों का मदिरा और रेस्तराँआ में घुसना सावजनिक कुआ से पानी लना और सबके साथ बठकर खाना सभब बना दिया था। इस पर सबण हिंदू प्राधित हो उठे थे। छुआछूत बरतन के लिए 4। मरपचा का निलम्बित किया गया था। इस राज्यपाल ने अनेक अच्छे काम किये, पर उन्हें हिंदुआ की नफरत मोल लेनी पड़ी।

जनता पार्टी के सत्ता में आते ही हरिजनों पर अत्याचारा की सँकडा घटनाएँ हुई। यह कहना ठीक नहीं होगा कि केवल जनता शासन काल के दौरान ही अत्याचार की ऐसी घटनाएँ हुई। 1974 में तो जनता पार्टी नहीं थी। बहुत मरप यह है कि गुजरात में हरिजनों पर हमेशा ही अत्याचार हुआ है। अपने कायकाल में एक राज्यपाल ने उन्हें समान अधिकार देने की कोशिश की और उसे सबण हिंदुआ का बोप झेलना पडा।

एक बार फिर हरिजनों की सावजनिक कुआ से पानी लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। रेस्तराँआ में उनके लिए अलग बरतन रखे गए। उन हरिजनों पर सूदखार महाजन बेहद क्रोधित हुए जिन्होंने सरकारी अधिकारियों की सलाह पर कज से राहत के लिए अर्जी दी थी।

पचासत के मुखिया ने फैसला किया कि यदि एक भी भूस्वामी ने हरिजनों को काम दिया तो उस पर 5। रुपया जुर्माना किया जायेगा।

हरिजनों को इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें अपनी जमीनों व भी वापस नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि सहकारी दुग्ध समितिवा ने भी उनमें दूध खरीदना बंद कर लिया।

हरिजनों का हमेशा गले निचले स्थान पर रहना पडता है और बचा के दिनों में हमेशा उनके झापडा में पानी भरा रहता है। वे पाखाना साफ करते हैं और सर पर मँला ढोते हैं। गांधी जयंती में उनकी निरुमत सुधारने की चर्चा खूब चलती है। अगले दिन वे फिर भुला दिये जाते हैं।

गुजरात में कोई जुझार आगेलेन नहीं पनप सका। महात्मा गांधी के अनुयायी हरिजनों के नेता हैं। वे सविधान की दुहाई देते हैं। इस आदोलन में कोई भी जुझार मौजवान नहीं है। और इसीलिए सभी जिलों में हजारों हरिजनों और आदिवासी गुलाभी की जिंदगी बसर करते हैं।

1939 में विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के समाज

कल्याण मंत्री १ एतान किया था कि हलपति आदिवासिया में काई भी बधुआ मजदूर ही है। बेशक यह सही है बज्र तन के बाद ही व हाली बनते हैं और बज्र दन वाले के यहां मजदूरी करते हैं।

उन्होंने चाहे जा भी कहा हो, लेकिन हाली लाग बधुआ मजदूर ही है। थोड़ी खाज बरन स यह भी पता चल जायेगा कि हलपतिया के अलावा अन्य हरिजन भी हाली ही है।

1917 में इन बार में एक समिति का गठन हुआ था। 1948 में सूरत में यह प्रथा समाप्त हो गयी थी। फिर भी 1978 में देखा गया कि यहां 10 से 20 हजार बधुआ मजदूर थे।

यह कहना गलत है कि कानून अशक्त है। जिस राज्यपाल का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन्होंने कानून को ही बड़ाई से लागू करके एक हद तक छुआछत पाप में किया था।

बधुआ मजदूर प्रणाली का वही मानसिकता जिंदा रखे हुए है जो हरिजनों पर अत्याचार की बहाल करती है।

दमनकारी जानते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा।

## हिमाचल प्रदेश

दूर-दूर बसे गावा वाले पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में राजाभा और जमींदारों के पास निर्विराध सत्ता थी। आज तक इन इलाकों का उचित ढंग से सर्वेक्षण नहीं हो सका है। ग्रामीण अव्यवस्था की समस्याओं का समझें बिना बधुआ मजदूर प्रणाली का अध्ययन नहीं किया जा सकता। 1948 में मुख्य आयुक्त द्वारा बधुआ मजदूर प्रथा का गैर कानूनी धापित किया गया और सरकारी दावा यह है कि यह प्रथा अब ही नहीं है।

हमन दया है कि कानून बेकार है। यह व्यवस्था वही फलफूल रही है जहां ग्रामीण अव्यवस्था पिछड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल एक उदाहरण है। खासतौर से यह भूतपूर्व दशौ रियासतों में खूब पनपता रहा है। उड़ीसा में गोतिरा इसका उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश में इसका फलना फूलना बहुत स्वाभाविक है। इस लिए अब सरकार जोर शोर के साथ नये प्रचारित कर रही हो तो हम खामोश ही रहेंगे।

शिमला जिले में चोपल तहसील में और सिरमौर जिले में रेणुका और राजगढ़ इलाकों में बधु प्रणाली है। हरिजन लोग थोड़ी सी जमीन के लिए जिंदगी भर अपने मालिकों की गुलामी करते हैं।

मुठठी भर अनाज और थोड़े में कज के लिए राज्य में गुलामी की प्रथा बेहद

## जम्मू कश्मीर

बधुआ मजदूर प्रणाली का नया रूप घिनीनया के साथ प्रचलित हो सकता है लेकिन यह परदे के पीछे छिपा भी रह सकता है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल की माहिंदर प्रणाली को भले ही सरकारी तौर पर बधुआ मजदूर प्रणाली न माना जाय पर वास्तव में यह बधुआ मजदूर प्रणाली ही है।

पश्चिम बंगाल और करल राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है। इनकी तुलना में जम्मू और कश्मीर पिछड़ा राज्य है। इसके अनेक गांव राज्य के भीतरी इलाकों में काफी दूर-दूर बसे हैं।

1961-62 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ जिलों में हाना माझी और लक्षारी नाम के कई तरह की बधुआ मजदूर प्रणाली प्रचलित है। यहाँ भी इस प्रथा की पृष्ठभूमि बड़ी है जो अब राज्यों में है। धनी जमींदार बड़ा देकर गरीब हरिजन और आदिवासियों को जपन जाल में फँसा लेते हैं। अपने मालिकों के खेत में माझिया को मुषन में काम करना पड़ता है और मंगाली में हो मर जाना पड़ता है। इसके बाद उस माझी का बेटा अपने गांव के स्थान पर गुलामी करता है। 1976 में जखनारा में छरी खबरा में बताया गया था कि लद्दाख में बधुआ मजदूर प्रणाली है और कश्मीर में कारीगरों के रूप में लड़कों को बधुआ बनाकर रखा गया है। अनंतनाग जिले में भी यही स्थिति है। बधुआ जिले के हरिजन बधुआ जिले में बिता रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला—दोनों ने बधुआ मजदूर प्रथा पर प्रतिबंध लागू किया था।

सरकार ने कश्मीर में हस्तशिल्प का विकास करने की कोशिश की, लेकिन इसने बुद्धिजीवियों के दिमाग में कुछ शक ही पैदा किया है। हस्तशिल्प एक बड़ा व्यापार है और अनेक धनी व्यापारी इस क्षेत्र में अपनी पूँजी लगा चुके हैं। लेकिन हस्तशिल्प के सामान तैयार कौन करता है?

इनमें से अधिकांश बच्चे हैं। इनकी मर्यादा 1,08,000 है और इनमें से अधिकांश निजी मालिकों के यहाँ नौकरी करते हैं। हालाँकि 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों का नौकरी पर रखना गैर कानूनी है पर अनेक लड़के अपनी कामवाजी जिले में 6 वर्ष से ही शुरू कर देते हैं। जहाँ वे काम करते हैं उन कारखानों में रोशनी हवा या स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का कोई पालन नहीं होता। फलस्वरूप वे टी० बी० जखवा आख के राग से पीड़ित हो जाते हैं। उन्हें ऐसी स्थितियों में इसीलिए काम करना पड़ता है, क्योंकि वे बहद गरीब हैं। मालिकों द्वारा उनके साथ बसा सबूक किया जाता है इसकी मिसाल बिलाल अहमद के मामले से दी जा सकती है।

बिलाल अहमद न थीनगर के अली माहम्मद वजा व कालीन बनान क बार खाने म 6 वष की उम्र से ही काम शुरू कर दिया था। उन दिना उसे प्रतिदिन 25 पैसे मजदूरी मिलती थी। 1980 म उसकी उम्र दस वष थी और उसे चार रुपये प्रतिदिन मिलते थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी ह। मा भाइया और बहना की देखभाल उस ही करनी पड़ती है।

4 मई, 1980 को उसकी एक उँगली कट गयी और वह अगले दिन काम पर न जा सका। 7 मई को जब वह काम पर गया तो वजा और उसके बेटे मुस्ताक न बिलाल अहमद को बुरी तरह पीटा। इससे बाद मुस्ताक और उसके भाइ माजि न लोह की छड़ गरम करके उसके शरीर का मात जगह दागा और फिर एक कमर म बंद कर दिया। रात होने पर बिलाल छिडकी कूद कर भाग निकला और अपन घर जा पहुँचा। अब यह मामला अदालत म है।

बिलाल और उसकी तरह के तमाम लोग गुलाम ह, न कि मजदूर, हाताकि उह जाना, माझी या दलालारी नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण बात है, मालिक का रबया। उसका मालिक समझता ह कि बिलाल उसका गुलाम है जा उसका कारखाने का उत्पादन बढान के लिए ही पैदा हुआ है।

यह बंदर रबैया ही बधुआ मजदूर प्रणाली को बनाए हुए ह। दश के अ य हिस्सा की तरह जम्मू पश्मीर भी इस पाशविक प्रथा को बरकरार रखे हुए ह।

## कनाडा

बगलौर और शिमोगा जिला म से प्रत्येक म 20 हजार से अधिक बधुआ मजदूर ह।

बीजापुर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, कोलार मैसूर उत्तर कानड और रायचूर जिला म स प्रत्येक जिले म दस से बीस हजार बधुआ मजदूर है।

धारवाड, हसन और मांड्या जिला म से प्रत्येक मे बधुआ मजदूर की संख्या पाच से दस हजार है।

बेलारी और बेलगाम मे इनकी तादाद पाच सौ स पाच हजार है। कुर्ग, चिकमगलूर, दक्षिण कानड और तुमकेन जिला म से प्रत्येक मे एक सौ मे पाच सौ बधुआ मजदूर ह।

बधुआ मजदूरों के बारे म सरकारी रिपोर्ट का जायजा ले।

1961 62

मसूर (अभी कर्नाटक नहीं कहा गया था) के कुछ इलाका मे तो बधुआ मा दूर है उह जीया कहते है। मुमकिन है कि अलग-अलग नामा स कुछ और बधुआ मजदूर हा। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह जल्दी से जल्दी इस विषय पर

नारवाई करे।

1963 64

हसन जिले के सक्तेसपुर और बेलूर इलाके में वधुआ मजदूर प्रथा कायम है। यह अनिवार्य है और वंश परम्परा के रूप में (बाप के बाद बेटे की बारी) प्रचलित है। इसका मूल कारण यहाँ की गरीबी है। 10 से 35 वर्ष की आयु तक के लोग जीया के रूप में हैं। उनके पिता और उनकी पत्नियाँ भी उन्हीं के साथ गुलामी करती हैं। सबलापुर ताल्लुक में सूदखार महाजन 144 प्रतिशत व्याज वसूलते हैं। अनेक पञ्जार लोग 15 से 40 वर्ष तक जीया बने रहते हैं। बलूर ताल्लुक में जीयाओं को खाना और कपड़े के अलावा वेतन के रूप में भी कुछ दिया जाता है। लेकिन वेतन के रूप में इतना कम पता मिलता है कि उससे वह व्याज भी नहीं दे पाते। फलस्वरूप बाप और बेटे अनेक दशका तक गुलामी करते रहते हैं।

1965 66 में प्रकाशित रिपोर्ट में पिछली दाना रिपोर्टों का ही विवरण संकलित था। इस रिपोर्ट के परिनिष्ठ में कहा गया था कि वधुआ मजदूर प्रथा का मुख्य कारण वंश है। इस प्रथा को समाप्त करने का एक मात्र तरीका निम्ने गये बच्चों को रद्द करना और पञ्जदारा की स्थिति में सुधार लाना है।

उस वर्ष के दौरान गुलामी के एक और रूप का पता चला। कर्नाटक के अनेक स्थानों में और खासतौर से बेल्तारी जिले में गुलाम-वेश्याओं का एक बग पाया गया। हरिजन और वेदारा की औरता को दूसरी जाति के लोग बसावी (वेश्या) बना लेते हैं और इस धंधे से वे काफी पैस कमाते हैं। 1963 में सिरगुप्पा शहर की दस हजार की आबादी में 600 औरतें बसावी के रूप में सक्रिय थीं। उसी वर्ष में देखा गया कि कुदलागी शहर की दस हजार की आबादी में 1,500 बसावी औरतें थीं। इस सारे धंधे को एक धार्मिक पुट दे दिया गया है। हरिजन और वेदारा जाति की खूबसूरत लड़कियाँ को मंदिरों में रख कर एक अनुष्ठान के जरिए मंदिर के देवता के साथ ब्याह दिया जाता है। एक सान या समगा—जिसे ताली कहा जाता है—इन औरतों के गले में बाँध दिया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि उनकी मंदिर के देवता से शादी हो गयी है। चूँकि इन लड़कियों को देवताओं के साथ ब्याह किया गया है इसीलिए वे अब नश्वर प्राणी मनुष्य के साथ नहीं ब्याही जा सकती। इसके बाद इनसे वेश्यावृत्ति नरवायी जाती है। ये गरीब लड़कियाँ इतनी असहाय होती हैं कि अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकती।

1965 66 में सरकार ने कुदलागी में इन बसावी औरतों के बच्चा के लिए एक स्कूल खोला।

1969 70 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के जरिए राज्य के दूर दराज के इलाकों

में जीया प्रणाली का एक और रहस्योद्घाटन हुआ। जाहिर था कि अत्यंत प्रगतिशील रिपोर्टों के जरिए और भी सूचनाएँ सामने आ रही थी। अनेक गाँवों में प्राचीन जातियाँ व लोग गुलामी की जिन्दगी बिता रहे थे। वे कर्नाटकी और द्रविड़ जाति के पुरातन नस्ल में से थे।

कर्नाटक के सवण हिंदुओं के रवैय का अनुमान निम्नांकित घटनाओं से लगाया जा सकता है। 27 मई 1972 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगस्त 1974 में एक हरिजन की बारात दूल्हा और दुल्हन के साथ उस सड़क से गुजर रही थी जो सवण हिंदुओं की वस्ती से होकर जाती है। हिंदुओं को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूल्हा दुल्हन सहित प्रत्येक बाराती का बुरी तरह पीटा। यह घटना कलिचुर गाँव की है।

दरअसल गडबडी की शुरुआत उस वर्ष मई के शुरू के दिनों में ही हो गयी थी। हरिजनों और आदिवासियों पर संगठित हमले किए गये थे। उनके मवेशियाँ, भेड़ें और बकरियाँ का चुरा लिया गया। अगर उन्हें कोई आयाग करना चाहता तो बिली की लाइन काट दी गयी।

मई 1975 में इन अत्याचारों में और तेजी आयी। शादी-ब्याह के लिए हरिजनों द्वारा बनाये गये पडाला और शामियाना में आग लगा दी गयी। 21 मई को नौ हरिजनों के भूतल जला दिये गये, उनमें रहस्य वाला भी पीटा गया, उनके जेवरों और अनाज लूट गये और डंडा तथा कुल्हाड़ा से प्रहार करके तीन लोगों का बुरी तरह घायल कर दिया गया। एक नौजवान को काफी पीटने के बाद तालाब में फेंक दिया गया।

यह प्यार 27 मई 1975 की थी। उसी दिन 'राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की जगह जीवनराम गालियर में अत्याचार निवारण सम्मेलन' में भाषण देते हुए हरिजनों से अहिंसा का पालन करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने हरिजनों से हर अत्याचार दरवाज़ा करने की अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में उनके बंशजों को हिंसात्मक कार्यों का निशाना नहीं बनाया जायगा।

बनाटक की कुछ ऐतिहासिक विनिष्ठताएँ हैं। कुछ दशक पूर्व, जब इसका नाम मैसूर था, एक परमाणु जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों का छोड़कर सभी जातियाँ पिछड़ी जातियाँ हैं। इसने फलस्वरूप एक प्रभावकारी गैर ब्राह्मण समुदाय बकवलिगा का काफी महत्व मिला। उनके और ब्राह्मणों के बीच भेष की स्थिति पढ़ा हो गयी। 1956 में राज्य का पुनर्गठन के बाद निम्नलिखित बातों के साथ की ताकत बढ़ी और अब तिवाना भेष शुरू हुआ। यह नाम नगरी गौड़ आयाग के फलस्वरूप का नतीजा था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आयोग द्वारा पिछड़ी जाति का जा वर्गीकरण किया गया है वह भविष्य में साथ घाटा है।



1963 में राज्य सरकार एक बंदम और आग बढ़ गयी। इसने ऐलान किया कि 1 200 रुपये सालाना में कम आयवाले किसानों, शिल्पियों, छोटे व्यापारियों, शारीरिक थम करने वाला और घरेलू नौकरों जैसे लोगों का भी पिछड़ी जाति का माना जायेगा। इस प्रकार ग्रामीण वर्गों, शिल्पियों और लिंगायत महत्वपूर्ण हो गये। हरिजन और आदिवासियों की स्थिति पहले जैसी बनी रही।

1972 में गठित हानुर आयोग ने उस समय उत्तरेलपीय नाम का जल उत्पन्न 3,55,000 व्यक्तियों और 200 गांवों का सर्वेक्षण करने के बाद एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार की।

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार थे

1) धर्म विभेद एक वास्तविकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे किसी उचित सिद्धांत का उत्प्रेषण नहीं किया गया कि किस आधार पर जाति और वर्ग सम्बन्धी विभेद का समाप्त किया जाना प्रभावित हुआ है।

2) सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर सदन को प्रभुत्व तथा निम्न जातियों की उत्पीड़ित अवस्था से साबित कर दिया कि जाति का मतलब वर्ग है।

3) शिक्षा और सरकारी नौकरियाँ में हरिजन और आदिवासियों का 70 प्रतिशत प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे किसी बंदम में माध्यम पालिका अडचन डाल देती। इसीलिए शुद्ध में केवल 18 प्रतिशत नौकरियाँ सुरक्षित की गयीं तथा और भी 32 प्रतिशत को सुरक्षित करना जरूरी था। उत्तरेलपीय है कि माध्यमपालिका ने आयोग का पहले ही सूचित कर दिया था कि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थान सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री श्री देवराज जल न आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बान्नी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद जाति के सिफारिशों का लागू किया जायेगा। बुभाग्यवश नौकरियों में जायदाद की योजना का समाचार सुनने के बाद सभी धर्मों और समुदायों के प्रभावशाली लोग अपने-अपने समुदायों का पिछड़ी जाति घोषित करने में व्यस्त हो गये।

आयोग ने 200 जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में चुना। इसमें राज्य की आयादी का 45 प्रतिशत हिस्सा और हिंदुओं का 51 प्रतिशत हिस्सा था। फिर भी कुछ जातियाँ आयोग के दायरे से बाहर रह गयीं। इस रिपोर्ट में मजदूर हिंदुओं में वर्गीकृत घना बढ़ गयी। इसमें हरिजन और भी ज्यादा जलवाहक हो गये।

मिश्रारिणों का लागू करने के लिए 18 मई 1977 का एक अधिनियम पारित हुआ। उस समय तत्कालीन पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के शासन-काल में

आयी रिपोर्ट की उपेक्षा कर दी गयी। जुलाई, 1978 में राज्य विधानसभा के एक कांग्रेसी सदस्य भीमना खडारे ने आयाग की रिपोर्ट में आग लगा दी। लिगायता तथा जय प्रभावशाली समुदायों के लोग रिपोर्ट का विरोध करने लगे। फिर भी 18 अप्रैल, 1979 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भूमि सुधार, ऋण राहत, बधुआ मजदूर मुक्ति खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा अन्य प्रगमनीय कदम उठाये गये।

अप्रैल 1976 में कानून मंत्री श्री हवानूर की पहल पर मसूर जिले में 12 250 और समूचे राज्य में 24,500 मजदूर मुक्त किये गये। लेकिन उनकी आर्थिक समस्याएँ आसानी से हल होने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके भूतपूर्व मालिकों ने उन्हें खेतिहर मजदूर रखने से इकार कर दिया था।

1979 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि शिमोगा जिले में 40,000 से अधिक जीया हैं।

कनाटक की स्थिति अच्छी नहीं है। जीया लोग को बही आने जाने की आजादी नहीं है। 1966 में माडया जिले के मददुर गांव की एक औरत चिनम्मा ने अपनी बहन की शादी के लिए 300 रुपये का कज लिया था। इस कज के कारण वह जीया बन गयी। वह 1976 में एक बार अपनी बहन से मिलने गयी। जब वह लौट कर आयी तो उसके मालिक ने उसे गरम छड से दाग कर यह एहसास करा दिया कि जीया का मतलब क्या होता है।

वे दाग हमेशा चिनम्मा को उसी हैसियत का एहसास कराते रहेंगे।

करन

बधुआ मजदूर प्रथा के सद्भ में हम दो बातों पर ध्यान देना होगा, जो हर राज्य पर लागू होती है। प्रथम, हमें देखना चाहिए कि इनमें मालिकों का क्या है और दूसरे, गरीब भूमिहीन, आदिवासियों तथा हरिजनों के प्रति उनका रवैया क्या है? असल में मालिक बनने की यह मानसिकता है जिसने बधुआ मजदूरों को जन्म दिया है जिसमें किसी व्यक्ति की जमीन को जबरन अथवा छल-कपट के जरिए हड़पने, याज की वेहद भारी दर पर उसे कज देने की घटनाएँ शामिल हैं।

अंग्रेजों के शासन काल से ही अनेक राज्यों में बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने के कानून पारित किये। इस तरह के कानूनों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्हें कभी लागू नहीं किया गया। और, उसे लागू करने का भी कोई लाभ नहीं था। जहरत भी जमीन के स्वामित्व में तबदीली लाने की। अगर जमीन थोड़े लोगों के हाथ में बनी रहती है तो वे लोग जिनके पास कम जमीन है जयदा बिल्कुल जमीन नहीं है जमीन के उन मुठ्ठी भर मालिकों के दमन और उत्पीड़न

का शिकार होते रहें। यह उत्पीड़न वधुआ मजदूर प्रथा का जन्म दया। यदि यह बुनियादी ढांचा ज्या-वा-त्या बना रहता है तो कोई भी राज्य सरकार, भले ही वह किसी पार्टी की हो क्या न हो किसी तरह का उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं ला सकती। पश्चिम बंगाल में यह बात देखी गयी है।

केरल में पिछले 20 वर्षों में वाम मोर्चे ने सरकार में हिस्सा लिया है। सरकारों का प्रचार और विज्ञापन के जरिए इसने कई बार अपना ही अभिनंदन किया है। वास्तविकता क्या है? 1979 में किसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक लेख में इसकी दूसरी ही तस्वीर देखने को मिली। संयुक्त मोर्चा सरकार की प्रगतिशीलता का दिंडारा पीटने वाले प्रचारकों के कारण समाज के कमजोर वर्ग की दयनीय अवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी मिल सकी। सच्चाई यह है कि पिछले 20 वर्षों में केरल में गांधी, हलक और विविध तरह के साल रंगा वाली वाम मोर्चा सरकार के बावजूद हरिजन के बहुमत आज भी गरीबी की रेखा में नीचे रहता है। एक लाख लोगों के लिए भूमि-व्यदापस्त और आवास-योजना की बहु-चर्चित योजनाओं से शामका को महज प्रचार ही मिला है। भूमिहीन गरीब आज भी पहले की ही तरह जिंदगी गुजार रहे हैं।

अलेप्पी के पास अवालुक्कुनु नामक एक हरिजन बस्ती है जिसमें लगभग 160 व्यक्ति रहते हैं। प्रगतिशील केरल राज्य में यह बस्ती अंध जातियों की बस्ती से दूर बनायी गयी है। यहाँ हरिजन के साथ अकेले और सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ आम बात हैं। अपने सामाजिक स्वभाव, पक्ष और पुलिस की मदद के बल पर अपराधी बेदाग निकल जाते हैं। हरिजन पुरुष जो जंगल में पड़े रहते हैं शिकायत की हिम्मत नहीं करते। इन शिकायतों से उन्हें पता नहीं मिलेगा—सच्चाई तो यह है कि उल्टे अपराधी लोग इनसे बदला लेने लगे हैं।

कोचुपनु नामक एक हरिजन लड़की का उमर के पिता की आँख के सामने 1979 में अपहरण किया गया और मनालाकुनु से जाया गया जहाँ बदमाशों के एक गिरोह द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। इसके फल-स्वरूप उसकी शांति की बातचीत टूट गयी। कुछ दिनों बाद पश्चिमी नामक लड़की का बचा लिया गया जब उसने और उसकी माँ ने गिरोह का मिलकर प्रतिरोध किया। 27 मार्च 1979 को भक्तन की शोषड़ी इसलिए जला दी गयी, क्योंकि उसने अपनी भतीजी को बदमाशों को सौंपने से इंकार किया था। चौदह वर्षीय सुगदम्मा को भी भयानक अनुभव झेलना पड़ा।

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के कारण यह घटना प्रकाश में आयी। इस पर भी अलेप्पी के जिला कलेक्टर ने तथ्यों का मानने से इंकार कर दिया। बाद में वह एक पुलिस दल लेकर घटनास्थल पर पहुँचे।

पुलिस द्वारा धमकाव ज्ञान के बाद भी हरिजन ने कोई बात नहीं बतायी।

क्लकटर ने दिखावे के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया।

बे-द्र में जिन दिनों जनता पार्टी की सरकार थी कम्युनिस्ट संसद सदस्य गोविंद नायर कई दिनों के विज्ञापन के बाद 1978 में केरल से नई दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने दो घंटे का अनशन किया। मार्च-अप्रैल 1979 में अवालु कुन्नु के हरिजनो पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किसी दूसरे कम्युनिस्ट नेता ने इतना भी शारीरिक बल उठाने की कोशिश नहीं की। उन दिनों केरल के मुख्य मंत्री भी कम्युनिस्ट थे। इसके अलावा केरल सरकार यह दावा भी करती थी कि उसके शासन-काल में हरिजन बहुत खुश हैं।

इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि सरकारी पचार और असली स्थिति के बीच कितना फाँव है।

कन्नानूर जिले में उत्तरी वायनाड में और कोजीकाड जिले में दक्षिण वायनाड में तथा मालापुरम जिले में बधुआ मजदूर प्रथा का काफी चलन है। वायनाड में पनियाँ और अदियानो को जमींदारों द्वारा बधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। ये दोनों जनजातियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। जमींदारों को गौदन कहा जाता है। ये लोग कर्नाटक में आये थे और जंगली क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद इन्होंने पनियाँ में से बहुतों को मजदूर बनाया। एक समय ऐसा भी था कि जब पनियाँ को कुछ रुपये लेकर खरीदा-बेचा जाता था।

आज भी पनियाँ और अदियान अङ्गुलामी की स्थिति में हैं। बल्लीपूर कावू के समारोह के दौरान गौदन लागू प्रत्येक परिवार का 25 से 30 रुपये तक देते हैं। जो परिवार इस राशि का स्वीकार कर लेता है उस अपने सभी सदस्यों के साथ उस जमींदार के भेत पर बिना कोई मजदूरी लिए एक साल तक काम करना पड़ता है। इस वजह से बल्लीपूर कावू पानम और निलपूमानम कहा जाता है। जो अपना श्रम नहीं दे सकने उन्हें ब्याज सहित पैसे वापस करने पड़ते हैं। बधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति के लिए बधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के पारित किये जाने के बाद यह नियम खत्म हो गया।

लेकिन 1976 में प्रकाशित अखबारी खबरों से पता चलता है कि इस प्रथा का फिर भी काफी प्रचलन था। दो दशकों तक एक-एक बार एक घाम मोर्चा की सरकारें बनीं, लेकिन इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठान में वे हताशा नाकामयाब रही। दरअसल हम बुराई को बर्नी महत्व नहीं दिया गया। केरल और पश्चिम बंगाल के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि केवल बाग मारना सरकारों के मत्ता में आन में ही जमींदारों का बग चरित्र नहीं बर्न जाना। उह पाता है कि इन सरकारों में उन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़न वाला है।

## लक्षदीव

1968-69 की एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऋण सहायन एवं ऋण अनुदान अधिनियम, 1964 में लक्षदीव मिनोकाय और अमनोव द्वीपों के लिए पारित हुआ। 1 अक्टूबर, 1968 से इसे लागू किया गया। ऋण का परिमाण कम करने तथा वज्र का भुगतान करने के लिए सरकारी तौर पर उसे उधार देने के बारे में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।

यहाँ पर नदपू प्रणाली का प्रचलन था। इस प्रणाली के जगह रैयता को जमींदारों के खेत पर बिना मजदूरी लिये काम करना पड़ता था। 1965 में पारित एक कानून द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और 1968 में दम कानून को लागू किया गया।

1971-72 और 1972-73 की रिपोर्टों से पता चलता है कि केन्द्र शासित लक्षदीव में यह प्रथा अब खत्म हो गयी है।

## मध्य प्रदेश

शहडोल, सतना और यस्तर जिला में बहुआमजदूर प्रणाली का बाकी प्रचलन है। इनमें से प्रत्येक जिले में इनकी संख्या चालीस हजार से अधिक है। बिलासपुर सरगुजा निदिशा और रायगढ़ जिला में से प्रत्येक में बीस हजार से भी अधिक बहुआमजदूर हैं। बाताघाट छतरपुर गमुना, सागर, रोना, गुना और मुरना जिला में से प्रत्येक में इनकी संख्या दस से बीस हजार है। धार इंदौर, रायसन रतलाम सिहोर शाजापुर, छरगोन, उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी में से प्रत्येक जिले में बहुआमजदूरों की संख्या पाँच से दस हजार है।

बेतुल, पूर्वी निम्नार जबलपुर, रायपुर छिन्वाडा, टीकमगढ़, मंदसौर और देवदास जिला में से प्रत्येक में पाँच से पाँच हजार तक बहुआमजदूर हैं।

1960-61 की एक सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि आजादी से भी पहले से विध्य प्रदेश और ग्वालियर में महिदारी नामक बहुआमजदूर प्रणाली प्रचलित रही है। अगर महिदारी भागों की कोशिश करता था तो उसे पकड़ कर उसके मालिक तक पहुँचा दिया जाता था। यह प्रणाली आजादी के बाद समाप्त कर दी गयी, लेकिन शिवपुरी गुना और दरिया में शहरिया जानि के लोगो के बीच यह प्रणाली अभी भी प्रचलित है।

महिदारी खुद लिये हुए वज्र का शिकार बनता है और उसे मामूली-मी राशि पर किसी तरह काम चलाते हुए मजदूरी करनी पड़ती है। वह दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, भले ही किसी अन्य काम में उसे ज्यादा पैसे कमा न मिलें।

हजिजन लोग कम उम्र में ही अपने बच्चा की शादी कर देते हैं। शादी के

लिए उन्हें महाजन से पैसे वज के रूप में लेने पड़ते हैं। इन मामूली नडका को जिनके कारण वज बना पड़ा है, महिदार बना दिया जाता है और मालिका के खेत पर भेज दिया जाता है।

1961-62 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गोड जनजाति के लोग को बिना कुछ नये काम करना पड़ता है—किन्हीं किन्हीं मामलों में उन्हें काम के बदले खाने को मिल जाता है।

1962-63 की रिपोर्ट में महिदारी प्रथा के बारे में अपेक्षाकृत विस्तृत जानकारी दी गयी है। एक महिदार का तब तक काम करना पड़ता है जब तक उसका वज चुकना न हो जाये। उसे प्रतिदिन तीन किचोप्राम अनाज मिलता है और उसके अलावा रोज की खुराक तथा सात में एक जोड़ा कपड़ा भी प्राप्त होता है। यह प्रणाली शिवपुरी गुना और दतिया जिला के शहरी समुदाय के बीच ज्यादा प्रचलित थी। इसी तरह की प्रथा बिन्ध्य प्रदेश और महाकोशल में भी रही है। शहडोल जिले में इस प्रथा के कारण काल जाति के लोग तथा अंग गरीब हरिजन को बहुत यातनापूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। यहाँ इस प्रथा को हरबाही हाली कहते हैं। हरबाही को बहुत कम मजदूरी मिलती है। अस्सी रुपये या सो रुपये का वज चुकाना करने के लिए उन्हें पन्द्रह से जठारह वर्ष तक मजदूरी करनी पड़ती है। काम करने में इतना करने पर उन्हें पीटा जाता है और मूल राशि का दागुनी रकम उनसे वसूली जाती है।

मिलासपुर जिले में इस प्रथा को कमिया कहते हैं। एक कमिया को होनी के पाँचवें दिन से काम पर लगाया जाता है। यह अनुबंध एक साल के लिए होता है। उसे चालीस से साठ रुपये तक का भुगतान किया जाता है। उसे प्रतिदिन ढाई किलोग्राम धान भी मिलता है। नकद राशि और धान के भूय को यदि मिलाकर देखें तो उन्हें साल भर में एक सौ चालीस रुपये से एक सौ पचास तक की राशि मिलती है। इस पैसे से कोई भी कमिया अपने परिवार का खर्च नहीं चला सकता। वह अगली होली तक काम करता रहता है। साल भर में उसे केवल चार छुट्टियाँ मिलती हैं। अनेक कमिया भयना और गाड़ जनजातियाँ के पाये जाते हैं।

1965-66 में एक रिपोर्ट सामने आयी जिसमें देश के विभिन्न भागों में और खासतौर से मध्यप्रदेश तथा मद्रास में प्रचलित एक अजीबोगरीब प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसके अनुसार किसी भी सवण हिंदू की मृत्यु होने पर अनुमति जानि के किसी व्यक्ति का चिता तयार करने का काम दिया जाता था। जब तक साश जल नहीं जाती थी उसे लगातार ढाँक बजाते रहना पड़ता था। यह काम के बदले उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती थी।

1971-72 और 1972-73 में प्रवाशिन रिपोर्टों में उल्लेख किया गया था

वि रतलाम, मुरना झबुआ और मदसौर जिलों में एक भीमा तब बधुआ मजदूर प्रणाली का प्रचलन है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में यह प्रणाली खत्म हो चुकी है।

हरिजन और आदिवासियों के प्रति मध्य प्रदेश के मवण हिंदुआ का क्या रुढ़ि है ?

10 नवम्बर 1975 के समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर से इन क्षेत्रों की बड़ी दुखद तस्वीर सामने आती है। छत्तीसगढ़ जिले के ससबल गांव के एक घनी जमींदार शिवराम कुबेर न पुत्र की प्राप्ति के लिए अतृप्त सधावन नामक एक आदिवासी लड़के को बिभी देवी की बलि चढ़ा दिया। इस जिले की विविधता यह है कि सवण हिंदुआ में भी ऐसे अधविश्वासों का प्रचलन एक आम बात है। अपनी गुप्त इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आदिवासी लड़कों के बलि चढ़ाये जाने की अनब घटनाएँ यहाँ सुनने का मिलती हैं।

मुख्य मंत्री के अपने जिले दवास में 26 अगस्त 1977 को अनेक हरिजनता के मकान जला दिये गये। 25 फरवरी 1978 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 1977 में माच और नवम्बर माह के बीच राज्य में 105 हरिजनता की हत्या की गयी। अगस्त 1977 में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें सवण हिंदुआ ने हरिजनों के मैदानों में अपने मवेशी छोड़ दिये और खड़ी फसल को बरबाद कर दिया। हरिजनों के विरोध करने पर बड़ी बेरहमी से उन्हें मार डाला गया।

5 अप्रैल 1978 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1978 में मध्य प्रदेश में 966 हरिजन और आदिवासी मारे गये। इसमें सवण हिंदुआ को इसके लिए दायी ठहराया गया था। लगभग एक हजार हरिजन और आदिवासी औरता की बलात्कार का शिकार होना पड़ा। कौन भी जिना इस तरह के अपराध से मुक्त नहीं था। झबुआ जिले में 189 और बस्तर जिले में 174 लोग मारे गये। इसमें यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि 1977 से पूर्व इस राज्य में हरिजनता और आदिवासियों की हत्याएँ नहीं हुईं।

इस तरह की घटनाएँ ही बधुआ मजदूर प्रणाली की पट्टमूमि का निर्माण करती हैं। 1978 में सतना जिले के खुवरागोठ गाँव में बादू नामक एक बोल मुक्क रहता था जिसकी उम्र 32 वर्ष थी (उत्तर-पूर्व बिहार में बोल नामक एक जनजाति है। मध्य प्रदेश में बोल जाति के लोग अनुसूचित जाति माने जाते हैं)। सतना के इस क्षेत्र में बधुआ मजदूरों का लंगुआ रहना जाना है।

बादू के चारा भी लंगुआ थे। जिस समय बादू सात साल का था, एक शुभ दिन में (नव साल के अवसर पर अथवा बड़े बरसान पर्व के समय) उसे उपहार के रूप में कुछ नया कपड़े और एक जाड़ी चप्पल प्राप्त हुए। उसके साथ उस अपनी पीठ पर बठा कर शान्तिनाम गुरमी नामक जमीन्दार के घर ले गया। बादू हक्का

बकवा था। वह जमींदार के सामने पठा था और खाने के लिए उसे कुछ सामान दिया गया था। सचमुच बादू के लिए यह बड़ा शानदार दिन था। फिर उसने देखा कि जमींदार शातिदास ने उसके चाचा का 150 रुपये दिये।

इसके बाद से ही बादू लगुआ बन गया। उसके चाचा उसे लेकर एक दूसरे मकान पर गए और वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को सौ रुपये दिये। एक पाँच बप की सड़की के साथ बादू की शादी हुई। उसी दिन बादू पति और लगुआ दोनों बन गया। उसके जमे अय सागा की जिंदगी भी उस दिन बड़े नाटकीय ढंग से बदल चुकी थी।

उम बच्ची उम्र में बादू का लगुआ शब्द का जय नहीं मालूम था। अत्र 32 बप की उम्र में वह इस शब्द का भली भाँति समझ चुका है। अपना असली नाम वह भूल गया है और लगुआ के रूप में ही उसकी पहचान बच रही है। 25 बप की बड़ी मेहनत से भी एक सौ पचास रुपये का कज चुकता नहीं कर पाया है। एक बकन का खाना खाकर वह सबर से रात तक बाम करता है। जमींदार ने कज के बदले उसकी पत्नी का अपना गुलाम बना लिया है। बादू और उसकी पत्नी को मजदूरी के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। उनसे बताया गया है कि कज उतारने के लिए बहुत पैसा की जरूरत है। दोनों को पता है कि यह कज कभी नहीं उतरेगा। उ ह गाँव छोड़न की भी इजाजत नहीं है।

(2) रतलाम कस्बे से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दलानपुर गाँव में बिजली है। राजपूत तथा अन्य सबण हिंदू जमींदार चमारों को हाली बनाकर रखते थे। बिजली का पप लगने से खेती गाड़ी का काम और तजी से होने लगा। इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए हालियों की कमी पड़ गयी और जमींदार लोग 1,500 से 2,000 रुपय तक कज देकर उन्हें बधुआ बनाने की कोशिश करने लगे।

हाली जाति का एक नौजवान थोड़ा शिक्षित था। वह कज के भुगतान का हिसाब रखन लगा। इससे जमींदारों के हाथ-पाव फूलने लगे। उन्हें यह भय सतान लगा कि चमार लोग भी अब अपने अधिकारों के बारे में सजग होने लगे। उन्होंने फसला किया कि दूसरी जगह के मजदूरों को लाकर काम दिया जाय और इन चमारों का सबक सिखाया जाये। उनके चारा और पहाड़ों और जंगलों में भील जाति के लोग रहते थे।

जमींदारों ने भीलों के पास अपने दलाल भेजे जिन्होंने इन भूखे और सकोची जादिसिया को कज, नौकरी और मकान दिलाने का वादा किया। उनके आने से मजदूरों की सप्लाय में वृद्धि हो गयी और जमींदारों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इन नये मजदूरों के रहने के लिए तमाम छोटी छोटी झापड़ियाँ पड़ी हो गयीं।

पजा भील को कौन मुक्त करायेगा ? 1976 में उसकी उम्र 22 बप थी।



उसके पिता जीवा भील न मोती जाट से 300 रुपये का बज्र लिया था और हाली बन गया था। जब उसका लडका बड़ा हुआ तो उसने रुपसिंह नामक राजपूत से 600 रुपये बज्र लिये, मोती जाट से लिया बज्र चुराया किया और अपने बेटे को रुपसिंह के यहाँ हाली बना दिया।

सुद पञा न ६ वष के दौरान रुपसिंह स 700 रुपया और 460 किलाग्राम मक्का लिया था। इस प्रकार रुपसिंह ने पिता और पुत्र को 1,300 रुपय का बज्र दिया था। मक्का की कीमत 460 रुपय लगायी गयी थी। इस प्रकार बज्र की राशि 1,760 रुपय हो गयी। इस पर 24 प्रतिशत ब्याज लगा। इस प्रकार मूल राशि और ब्याज मिलाकर कुल 2,062 08 रुपय का बज्र हुआ। यह माना गया था कि रुपसिंह पहले दो वष तक पञा को 40 रुपय प्रतिमाह, तीसरे वष 50 रुपये प्रतिमाह और चार वष से 65 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप में देगा। इस प्रकार छह वष में पञा को 3 900 रुपये मिलते। उसे 2,062 08 रुपये वापस करन थे। पञा का कभी अपनी तनखाह नहीं मिली। यह मान लिया गया कि तनखाह का पसा बज्र म मुजरा हाता जा रहा है। खाता के मुताबिक पञा का 1,837 रुपये 92 पैसे और मिलन चाहिए थे, लेकिन जमींदार न बताया कि उसके ऊपर अभी भी 1 000 रुपय का बज्र चढ़ा हुआ है।

उसके अलावा पञा को प्रतिदिन 4 रुपय 50 पैसे की सरकारी दर स मजदूरी मिलनी चाहिए थी। छह वष में उसे 9 855 रुपये मिलने चाहिए थे। बज्र की राशि को बाटन के बाद उस 7,792 रुपये 92 पैसे मिलना चाहिए था।

लेकिन न तो उसे पम मिलेंगे और न वह आजादी ही पायेगा।

रुपसिंह के अनुसार उसके ऊपर अभी भी एक हजार रुपये बज्र के रूप में हैं।

वह भील चार वष से फूलमिह का हाली है। उसने नकद और मक्का के रूप में 1 800 रुपये की राशि के बराबर बज्र लिया था। मक्का की कीमत प्रति क्विंटल 100 रुपये लगायी गयी थी। उसने 600 रुपये नकद लिये और 12 क्विंटल मक्का लिया था। उस प्रतिमाह 60 रुपया वेतन मिलना था जिसे बज्र के बदले मुजरा होना था। चार वष में बज्र का 2 880 रुपया चुकता हुआ, लेकिन बज्र अभी बना ही रहा। भुगतान न की गयी राशि के रूप में 100 रुपया अभी भी पड़ा दिखलाया गया। निरक्षर बहुरू न अपने मालिक से कभी इस सिलसिले में कुछ नहीं पूछा। हर साल वह एक सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगा जाता है। बहुरू का कोई तनखाह नहीं मिलती। उसकी पत्नी दलिक मजदूर के रूप में काम करती है और उसे प्रतिदिन पौन दो रुपये में द्वाई रुपये तक मिलते हैं। इसी बमाई पर चार सदस्या के परिवार का खिन्गी गुजारनी पडती है। एक सतिहर मजदूर 9 घंटे तक काम करता है लेकिन बहुरू को 16 घंटे काम करना पडता है। एक सतिहर मजदूर के रूप में उसे ओवरटाइम के लिए 4 50 रुपये या 5 25

रूप में मिलना चाहिए था। उसकी दैनिक आय 9 75 रुपये होती। आज भी, कानून विभाग के विद्वानों के अनुसार हालियों की स्थिति काफी ठीक है।

जमींदार लोग हालिया में फूट डालने के लिए कागज पर यह दिखाते हैं कि उनके कुछ साधियाँ को ज्यादा मजदूरी मिलती है और इस प्रकार तथाकथित कम मजदूरी पाने वाले दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है। सच्चाई यह है कि किसी को ज्यादा पैसे नहीं मिलते। वज्र दिनादिन बढ़ता चला जाता है।

चूँकि भीखों को मामूली पैसे पर हाली रखा जा सकता है, चमार हालियों का बाजार खत्म हो गया।

बहुत को बताया गया कि केन्द्र सरकार न हाली प्रथा समाप्त कर दे और राज्य सरकार ने सारे ऋण रद्द कर दिये। अब वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है। उसने बड़े शांत भाव से जवाब दिया कि उनकी सरकार तो फूलसिंह है और उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

पंजा और उसके जैसे लोग अपने मालिक के अलावा और किसी की सत्ता को नहीं जानते।

9 फरवरी 1979 के समाचार-पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किये जाने से संबंधित कानून को मध्य प्रदेश में उचित ढंग में लागू नहीं किया गया है। इस प्रथा को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ के कमिश्नर ने रिपोर्ट दी थी कि वस्तर, रायगढ़ और जगली क्षेत्र के गाँवों में आदिवासियों का बिना मजदूरी दिये वन विभाग के लिए वष में 140 दिन काम में लगाया जाता है।

बेगार नामक इस प्रथा को इसलिए लागू किया गया था, क्योंकि सरदार ने इन लोगों को जंगल की जमीन दी थी।

## महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अहमदनगर सचमुच बधुआ मजदूर प्रदेश है। यहाँ 40,000 से अधिक बधुआ मजदूर हैं। अलगाव, धुलिया और नासिक में इनकी संख्या उल्लेखनीय रूप में ज्यादा है। ये तथ्य 23 फरवरी 1979 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे।

1961-62 की एक सरकारी रिपोर्ट में यह रहस्यादघाटन किया गया था कि थाने और नासिक में घोरकोली कतकरी, बर्ली और भील आदिवासी वट अथवा बेगार नामक बधुआ मजदूर प्रणाली के शिकार हैं। व मुख्यतया मेतिहर मजदूर थे जिन्हें वज्र लेने के कारण बधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर किया गया था। प्रशासन के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस प्रथा को

समाप्त करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। दरअसल इन आदेशों का प्रसारित नहीं किया गया और आदिवासियों में मजदूर विभागों का अयना आदिवासियों को इनकी कोई जानकारी नहीं थी।

1964-65 की एक रिपोर्ट 1 थान में प्रचलित व्यापक वधुआ मजदूर प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। 22 रुपये में लेकर 300 रुपये तक के ऋण के कारण अनेक आदिवासी 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए वधुआ मजदूर बन चुके थे।

1971-72 और 1972-73 की सरकारी रिपोर्टों में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में वधुआ मजदूर प्रथा के होना का कोई प्रमाण नहीं है। इस विषय में कोई कानून नहीं था पर श्रम कानूनों के मुताबिक यह प्रथा ग़र कानूनी है।

ध्यान देने की बात है कि राज्य सरकार ने इस प्रथा को हटाने की बात स्वीकार नहीं की। लेकिन इससे हरिजन और आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में अपनी जड़ जमा ली थी। जो लोग गरीबी की रक्षा के नीचे रहते थे, वे बच लेने के लिए मजबूर थे।

इस तरह के लोग अपढ़ थे और सबंध हिंदुओं से आतंकित थे। उन्हें गुलाम बनाना आसान था। राज्य सरकार के दावों पर विचार किया जा सकता था यद्यपि हरिजन और आदिवासी सम्मान के साथ जीवन बिता रहे होते।

लेकिन उन्हें पैट भरने शादी ब्याह करने तथा अपने परिवार के मृत सदस्यों के अंतिम सम्कार के लिए बच के लिए भागना पड़ता था। यदि उनके दावा में दम था तो दलित आदालत क्या शुरू हुआ?

1973 में डा० गोरे और शिरभान लिमचे ने अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण में पता चला कि अनुसूचित जाति के 90 प्रतिशत लोग गाँव की चौहद्दी से बाहर रहते हैं 50 प्रतिशत को कुएँ से पानी लेने की इजाजत है और 25 प्रतिशत को रेस्तराँओं में खाने नहीं दिया जाता। जिन्हें रेस्तराँओं में खाने की इजाजत मिलती भी थी उन्हें अलग बैठकर अपने लिए निर्धारित अलग प्लेटों में खाना खाना पड़ता था। इनमें से अधिकांश भूमिहीन और गरीब थे।

15 मार्च, 1975 की एक खबर में बताया गया था कि किस तरह थान जिले के आदेशों के एक दूकानदार रतिलाल ने दो पुलिस कांस्टेबलों की मदद से एक आदिवासी युवती भगलीवाई के घर पर धावा बोला था। उसने उस युवती से कहा कि वह दोनों कांस्टेबलों के साथ सहवास करे। युवती के इस्वार करने पर उसकी शापड़ी जला दी गयी। 1974 से 1975 के बीच अखबारों का देखें तो हरिजन और आदिवासियों पर होने वाले इस तरह के अत्याचार की अनेक घटनाएँ मिलती हैं।

1976 में भूमि सेना ने थाने जिला के पालघर ताल्लुक में 100 वधुआ

मजदूरों से बातचीत की। इस सर्वेक्षण से जनक तथ्य प्रकाश में आयें। एक सच्चाई का पता चला। भेंटकता ने, जो खुद भी आदिवासी था, देखा कि आदिवासी बधुआ मजदूर साहूकारों और महाजनों से इतने आतंकित हैं कि उनके खिलाफ बज्रबान भी नहीं खोलते। वे सवण हिंदुओं से डरते थे। यदि वे इतने आतंकित थे कि अपनी बिरादरी के आदमियों से भी कुछ नहीं कह पाते थे तो किस तरह वे दूसरों से कुछ कहते? इसलिए यह मानना गलत होगा कि चूंकि वे खामोश हैं, इसलिए वहां बधुआ मजदूर प्रथा है ही नहीं।

राज्य सरकार ने इस मामले का ज्यादा महत्व नहीं दिया। 1977 के आस पास यह पाया गया कि बधुआ मजदूरों की सट्टा, खासतौर से कोलाबा, नासिक, धुलिया और चंद्रपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में बहुत ज्यादा है। कज लेने के मामले अनक हैं। कभी कभी सरकारी दबाव के कारण कजदार व्यक्ति को सरकारी कज चुकता करने के लिए पैसे लेने पड़ते थे और इस प्रकार वह बधुआ मजदूर बन जाता था। रत्नागिरि में अनेक दलित और कुबी बधुआ मजदूर थे।

पालघर तालुक के कुछ बधुआ मजदूरों के उन्माहरण से यह तसवीर कुछ साफ उभर सकेगी।

(1) गावाड गांव में जेठया राघो बनगा अपनी पत्नी के साथ पिछले 13 वर्ष से महाजन का बधुआ मजदूर था। उस यह नहीं पता था कि—

(क) उसने कितना कज लिया था?

(ख) ब्याज की दर क्या है?

(ग) कितना भुगतान हो चुका है और कितना बाकी है? उसे केवल इतना पता है कि अपनी भादों के समय उसने कौन-कौन से सामान लिए थे। सामानों की सूची इस प्रकार है—

सामान	मात्रा	1965 में मूल्य	1977 में मूल्य
धान	10 मन	150 रुपये	500 रुपये
घोती	एक	10 रुपये	20 रुपये
कुर्ता	एक	7 रुपये	15 रुपये
साड़ी	तीन	45 रुपये	75 रुपये
अय कपड़े	तीन	9 रुपये	15 रुपये
नकद	—	12 रुपये	12 रुपये
योग		233 रुपये	637 रुपये

इस कज ने दो लोगों को गुलाम बना लिया।

(2) 1969 में बिरात गांव के विष्णु गनपत बालेकर ने महाजन साड़ी, तीन कपड़े, एक कमीज और एक धोती ली थी। इन चीजों की

90 रुपये से अधिक नहीं थी। वह और उसकी पत्नी आठ वष तक बधुआ बन रहे। उसे यह नहीं पता है कि कब तक कब चुकता होगा और कब तक व गुलाम बन रहगा। उह बाई मजदूरी नहीं मिलती। उह महज रोज का खाना, चाय आर बीड़ी मिलती है। साल में उह दा लेंगोटी, दा जाधिय, दा ट्राउज और दा साडी भी मिलती हैं।

(3) गायद्या गांव में काशीनाथ विटठल सुम्बादा और उसकी पत्नी 197 रुपये के ऋण के कारण 12 वष से बधुआ बन हुए हैं।

अमृत लंदाबा बडक न 400 रुपये कब लिय के आर 13 वष से बधुआ है। रघु पांडुपवार 500 रुपये के ऋण के कारण 16 वष से मालिक की गुलामी कर रहा है। बंनगाव में बल्वा चैतय माहर और उसकी पत्नी न 300 रुपये के एवज में एक करारनाम पर जंगूटे का निशान लगाकर 21 साल तक गुलामी करने की पास लगा ली। 9 साल गुजर चुके हैं। अभी 12 वष और गुलाम रहना है। विटाल जानु ने 300 रुपये का कब लिया था और अपनी पत्नी के साथ 21 वष तक गुलामी करने की रजामती दे दी। उसे यह भी पता नहीं है कि कितने वष बीत चुके। लीद्या लट्या पाडवर न 800 रुपये अपनी शादी के समय लिये थे। वह अपनी पत्नी के साथ बधुआ मजदूर के रूप में आठ साल बिता चुका है। इस बात पर सहमति हुई थी कि उह प्रतिदिन 450 ग्राम चावल और प्रतिवष 20 रुपये दिये जायेंगे। रुपये को कब में चुकता किया जायेगा। इस प्रकार व चालीस साल से गुलाम है। बेचारे लीद्या न धीमती गांधी के बीस-सूत्री कार्यक्रम पर यकीन कर लिया और राहत के लिए अपील की, लेकिन उसकी अपील पर कोई जवाब नहीं आया।

(4) विश्रामपुर गांव में रमेश बाबू माहर न 111 रुपये 75 पैसे कब लिये थे। उसके बदले में उसे और उसकी बहन का बधुआ मजदूर बनना पड़ा। 9 महीने की गुलामी के बाद एक दिन किसी लोहार के जबरन पर वह काम पर नहीं जा सका। इससे नाराज होकर महाजन न उसे और उसके बाप को बहुत पीटा। रमेश डर गया और भाग खड़ा हुआ। उसके मां बाप न महाजन का 300 रुपये और 150 रुपये मूल्य का तीन मन धान देने को कहा लेकिन महाजन न यह कहकर लेन से इकार कर दिया कि उस 1,200 रुपये पाना है। 1975 से ही रमेश भाग गया है। उसने 15 नवम्बर 1976 को तहसीलदार के नाम एक अर्जी देकर राहत की मांग की। मई 1977 तक उसकी अर्जी का कोई जवाब नहीं आया था। रमेश अपनी जान बचाने के लिए गांव से बाहर हो है।

राज्य सरकार ने थान जिले के बधुआ मजदूरों को छुड़ाने की कोई काशिश नहीं की। दिसंबर 1976 में भूमि सेता न तहसीलदार के पास 120 अर्जियां दी थीं। लेकिन प्रशासन न कुछ भी नहीं किया। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां

पुलिस भाग हुए बधुजा मजदूरों का पकड़कर पहले पीटती है फिर उन्हें उनके मालिकों के हवाले कर देती है। यहाँ पुलिस जमींदारों के हितों की रक्षा में लगी रहती है।

## उडीसा

उडीसा में खामतौर में कोरापुट जिला और गजाम जिलों में गांधी प्रणाली दखन की मिलती है। प्रत्येक स्थान पर इसका स्वरूप भिन्न है। गृह की राशि 50 रुपये से 200 रुपये तक है। गोठिया को प्रतिवर्ष 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिलते हैं तथा उन्हें खाना या अनाज और कपड़ा दिया जाता है। उन्हें बड़ी खरीदों के लिए भी प्रति सप्ताह 6 से 12 पैसे तक दिया जाता है। उनके मालिक उन्हें ग्रामीण पुनर्वास कार्यों में भी लगाते हैं जो राज्य सरकार समय समय पर चलाती रहती है। उनके वेतन उनके मालिकों की जेब में चले जाते हैं। हालांकि गोठिया प्रणाली काफी प्रचलित है पर यहाँ टडामुलिया और दारोमसिया प्रथा का भी चलन है।

केन्द्रीय आदिवासी विभाग ने 1962 में काश्मिर और पराजिया आदिवासियों के नौ गांवों का सर्वेक्षण किया था। इससे पता चला कि कुल आबादी में 10 प्रतिशत गोठिया हैं। गुलामी की अवधि 10, 19 और यहां तक कि 30 वर्ष भी है। एक व्यक्ति ने 60 रुपये उधार लिए थे और उसे गोठिया बनना पड़ा और बाद में उसके दाना घट भी गोठिया बन। इन्होंने कुल 22 वर्ष तक गुलामी की।

ध्यान देने की बात है कि 1948 में वन एक कानून के जरिए उडीसा में गृह के एजेंडों में गुलामी की प्रथा समाप्त की जा चुकी है।

इसके अलावा एक और प्रथा का चलन है। जब कभी किसी बड़ी परियोजना का निर्माण-कार्य शुरू होता है तो ठेकेदारों के एजेंट जिन्हें खानादार या मरदार कहा जाता है, 25-30 मजदूरों का एक दल बनाते हैं जिनमें 12-13 साल की लड़कियां भी होती हैं। ये एजेंट इन मजदूरों की मजदूरी पहले ही ठेकेदार से लेते हैं, मजदूरों का पस कभी नहीं मिलता। इन पैसों का रख रखा जाता है और काम करते-करते हान पर देन का वादा किया जाता है। एजेंटों का यह डर रहता है कि यदि मजदूरों के हाथ में पैसा आ जायेगा तो वे घर लौट जायेंगे।

इन अभाग मजदूरों को डाढ़न मजदूर कहा जाता है। काम की समाप्ति पर ठेकेदार एजेंटों में हिताय करता है, न कि मजदूरों में। नतीजा यह होता है कि मजदूरों का ठेका समाप्त होने के बाद भी रुके रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास घर लौटने का पस नहीं होता। उनमें जेब भुगतान होता है ना रनव गिवट का अलावा उन्हें नन्द के रूप में मामूली राशि दी जाती है। उनका दाना तराई से घाटा होता है—पैसे का मामले में भी और बिना किसी काम के समय दरबार

करने से। काम के दौरान उनकी सेवाएँ समाप्त किए जाने पर भी कोई मुआवज़ा नहीं मिलता।

उनके काम के घंट भयंकर होते हैं। वे सवेरे छठ बजे से रात के बारह बजे तक काम करते हैं—घीब में एक घंटे के लिए खान की छुट्टी मिलती है।

कोड़े लगाने की घटना तो आम बात है। इतने चोट से कुछ मर भी जाते हैं। जा भगान की कोशिश करते हैं उन्हें पकड़े जाने पर और भी बदरना का सामना करना पड़ता है। अनेक डाइन मजदूर उड़ीसा से बाहर काम करते हैं। मुदा सब डिवाइजन के पांच मजदूरों की पिटाई के कारण मृत्यु हो गयी। 1974 और 1975 में कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में काम करते समय 15 से ज्यादा मजदूर मारे गये।

1976 में उड़ीसा सरकार ने डाइन मजदूरों का काम पर लेने, ठेके की शर्त तय करने और मजदूरों की दर निर्धारित करने के बारे में एक कानून पारित किया। यह कानून कभी लागू नहीं किया गया। डाइन प्रथा जारी है और यह सचमुच दुख की बात है कि अनेक लोगों का यह पाशाविक प्रथा ही जीने का एक मान उपाय देती है। इसीलिए वे आज भी खातादार के आन पर उसके प्रस्तावों को खामोशी से सुनते रहते हैं। खातादार उन्हें तीन महीने का ठेका देने, 210 रुपये मजदूरी तथा घर सौटन के लिए रेलवे भाड़ा देने का वायदा करता है। उन्हें यह भी पता है कि मजदूरों के रूप में उन्हें बहुत कम पैसे दिए जायेंगे। पाना और रेलभाड़ा के अलावा वे कोड़ा की भी उम्मीद करते हैं। वे जानते हैं कि उनमें से कुछ मर भी जायेंगे। जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा वे कश्मीर, दिल्ली या मध्य प्रदेश में एक अजनबी मौत के सिकार बनेंगे। उन राज्यों के मजदूरों का नया चेहरा बारीकी से देखने की जरूरत है जहाँ वधुआ मजदूर प्रथा का जबरदस्त चलन है। वगैरह दमन के बिना वधुआ मजदूर प्रथा का अस्तित्व नहीं हो सकता।

फरवरी 1976 में आयोजित नारायणगढ़ शिविर में इसी मुद्दे पर विचार किया गया। सबलपुर में स्थानीय आदिवासियों का जमीन नहीं मिलती। उनको बड़ा देते समय बड़े बेटहाणा ब्याज लेते हैं। यदि वे भुगतान नहीं कर पाते हैं तो सरकारी सस्थाएँ उनकी जमीनें जप्त कर लेती हैं और बेच देती हैं, हालाँकि आदिवासियों की जमीन को खरीदना बेचना सर-काननी है। वन-विभाग के लिए जो आदिवासी बंदू की पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में दो रुपये मिलते हैं। उड़ीसा में न्यूनतम मजदूरी कानून के अनुसार कम-से कम मजदूरी चार रुपये होती है।

बलकट और आस-पास के गाँवों में आदिवासियों की जमीन को तहसीलदार सर-आदिवासियों में बाँटना है। इस तरह की जमीन—जिसे परंपरा में भूमि कहा

जाता है—आदिवासियों के लिए ही है। 14 गावां में, जहां खोमर नामक आदिवासी रहते हैं सारी जमीन का घर आदिवासियों ने हड़प लिया है।

पुर्गे जिले में पिपली खानान्तगत मंगलपुर गांव में हरिजन मजदूरों और सवण हिंदुओं की बस्ती के बीच एक बाड़ा लगाया गया है। पांच मंदिरों में से चार दासतों से सवणों के लिए हैं। सवणों के कुंआ से हरिजन पानी नहीं ले सकते। मजदूरों में दावग ह—होलिया और माधारण मजदूर। होलिया वग के मजदूर बगुआ मजदूर हैं। किसी होलिया को भू-स्वामी 200 से 300 रुपये और डेढ़ बीघा सेत उधार देता है। इसमें एकज में उसे पूरे साल उस व्यक्ति के खेत पर काम करना पड़ता है। लगभग सभी भू-स्वामियों के यहां होलिया मजदूर होते हैं।

पुरुष और महिला मजदूरों को प्रतिदिन कम से कम ढाई रुपये और दो रुपये मिलते हैं। लगभग सभी पर बज्र चढ़ा होता है। ब्याज की दर 100 प्रतिशत साताता है। आश्चर्य नहीं कि बज्र लेने वाला बगुआ बन जाता है।

(1) जोनु पेहाना नामक हरिजन किसान के परिवार में सात सदस्य हैं। उसमें पाम एक छोटी आपत्ती और गौशाला है। उसमें पास अपनी डेढ़ बीघा जमीन है जिससे वह लगभग एक क्विंटल धान पैदा कर लेता है। उसने बटाई के आधार पर भू-स्वामी से और डेढ़ बीघा जमीन तथा इस पर होने वाले खर्च के लिए 250 रुपये नकद लिये थे। फलस्वरूप उस बिना मजदूरी लिये भू-स्वामी की जमीन पर आधा महीना काम करना पड़ता है और शेष दिन वह अपने खेत पर काम करता है या छेतिहर मजदूर बना रहता है। जानु को उन तमाम कानूनों की जानकारी नहीं है जो उसमें जैसे लोगों का लाभ के लिए बन है। उसे केवल यही पता है कि सहकारी संस्था के पाम कज के लिए वह जब भी गया उसे निराश हाकर लौटना पड़ा। जोनु कभी ट्रेन पर नहीं चढ़ा। उस कबल इतना ही पता है कि उड़ीसा उसकी जन्मभूमि है और इंदिरा गांधी सारी दुनिया की नेता है।

वह जानता है कि सरपंच और ग्रामीण स्वयंसेवकों का सब पर शासन है लेकिन य गरीबों के उत्थान के रास्ते की सबसे बड़ी खानद है। उसे पता है कि उसमें गांव में 75 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक का पास 600 बीघा जमीन है। मिट्टी का तेल, चीनी और गेहूँ बचन वाली दुकानें भी हैं, पर जोनु य चीज नहीं खरीद सकता। वह सोचना है कि अगर वह डाढ़न मजदूर बन जाये और घर छोड़ दे तो उसकी जिंदगी बहुत ही जायगी। लेकिन अपने परिवार को कैसे छोड़ें ?

अपना के जमान में देसी रजवाडों में बगुआ मजदूर प्रयायी जिनके बेटी, बगार और बहुरा उस कद नाम थे। 1923 और 1929 में कानून के जरिए इन्हें समाप्त कर दिया गया। लेकिन इन जिला में अन्य अलग नामों में यह प्रथा



जनी रही ।

इसके अलावा एक गुटिया प्रणाली थी जिसमें गुटिया के नाम से प्रचलित जमींदार मजदूरों को कच्चा देकर अनिश्चित समय के लिए उन्हें बधुआ मजदूर बना लेते थे । 1956 में यह प्रथा भी समाप्त कर दी गयी, पर व्यवहार में इसका कोई असर नहीं पड़ा । दूरदराज के गावां में गुटिया जमींदारों ने वेनामी जमीनों खरीद ली और प्रत्येक के पास 400 से 500 बीघा जमीन है । वे सब हिंदू हैं, पचायतो के नेता हैं और बड़े-बड़े अक्सर उनके दोस्त हैं । वे हरिजना और आदिवासियों की जमीनें हड़प लेते हैं । अनेक मामला में उनके बधुआ मजदूर अगर उनकी इजाजत लिये गांव में बाहर नहीं जा सकते ।

(2) घाटपाड़ा गाँव का रसिया दीप एक आठ वर्ष का हरिजन लड़का है । एक वर्ष की उम्र से ही वह एक सबण हिंदू के यहाँ बधुआ मजदूर है । उसकी सालाना तनखाह 10 रुपये है । उसे दो पैट और एक कमीज भी मिलती है । उसे नम में दाना पहर खाना मिलता है जिस पर उसके मालिक का एक रुपया से ज्यादा खर्च नहीं होता । फिर भी उस हफ्ते में दो दिन खाना नहीं दिया जाता । वह हर रोज 12-14 घंटे काम करता है ।

(3) सीमाचल पतरी एक हरिजन है । उसकी उम्र 30 वर्ष है और वह लगीगढ ब्लॉक के एक गांव में रहता है । वह पिछले 15 वर्ष से बधुआ मजदूर है और सबण हिंदू है । उसकी सालाना तनखाह 200 रुपये है और साथ में उसे तीन सेट कपड़े भी मिलते हैं । उसे हर सप्ताह बहुत घटिया किस्म का 21 किलो धान मिलता है । इसे कूटन-बनान के बाद वह साढ़े दस किलो ग्राम चावल गिराल लेता है । इस तरह का चावल उधर के गांव में एक डेढ़ रुपये किला मिलता है । फरवरी में जून तक उसके पास कोई काम नहीं होता । इन चार महीना में उसे धान भी नहीं मिलता ।

परिवार के एक सदस्य को मामूली से पैसे देकर पूरे परिवार को गुलाम बनाने की प्रथा का उड़ीसा में काफी चलन है ।

उड़ीसा भारत का हिस्सा है । गरीबों का गुलाम बनाने के सभी हथियार यहाँ इस्तमाल किये जाते हैं ।

कानूनी और सरकारी नियम यहाँ हरिजना तथा आदिवासियों के लिए नहीं हैं ।

## राजस्थान

राजस्थान के विभिन्न जिला में बधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है

जिला

बालवाड कोटा

बूदी, सवाई माधोपुर उदयपुर,  
गगानगर अजमेर भीलवाडा

झुलुनू

नागौर शिकार टाक, चित्तौडगढ़

सह्या

10 000 20 000

5,000 10,000

500 5 000

कुल बहुआ मजदूरों में से 56 प्रतिशत इस प्रथा को समाप्त करने से  
संवर्धित विधायक के पारित किये जाने के भीतर बहुआ बनाये गये।

(1) उदयपुर जिले के ब्राह्मण की हुदार गाँवों में जीवा नामक 20 वर्षीय  
एक युवक रहता है जो एक सागरी है अर्थात् बहुआ मजदूर है। जब वह पाँच  
वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गयी और उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के  
साथ चली गयी। जीवा के पास कुछ बीघे जमीन थी जिसे उसने चाचा के  
जातदार रूपसिंह को 100 रुपये में बेच दिया था। फिर उसने एक ब्राह्मण  
जातदार शिवराम से 80 रुपये कूज लिया और जीवा को उसका सागरी बना  
दिया। तनरवाह की भी कुछ बात हुई थी पर जीवा को कभी कोई तनरवाह  
देखन को नहीं मिली। उसने शिवराम के सागरी के रूप में तीन साल बिताये।

जल्दी ही उसके चाचा की और रुपया की जरूरत पड़ी। उसने कुवेरलाल  
नामक एक ब्राह्मण से 200 रुपये उधार लिये, शिवराम का पसा चुकता किया  
और जीवा को कुवेरलाल का सागरी बना दिया। उस समय जीवा आठ वर्ष  
का था।

कुवेरलाल एक क्रूर व्यक्ति था। वह जीवा को पीटा करता था और दिन  
भर में 15 घंटे काम लेता था। जीवा को दिन में दो बार थोड़ा खान को दिया  
जाता। आखिरकार जीवा से जब बरदाश्त नहीं हो सका तो वह भाग गया, पर  
कुवेरलाल के आदमियों ने उस पकड़कर वापस पहुँचा दिया। उसे इतना पीटा  
गया कि वह बेहोश हो गया। कुवेरलाल का जब लगा कि इस लड़के का रखना  
अपनी परेशानी बढ़ाना है तो उसने जीवा के चाचा से कहा कि वह पसा वापस  
करे और जीवा को ले जाय।

फिर जीवा के चाचा ने उस एक दूसरे किसान के हाथ 300 रुपये में बेच  
लिया और कुवेरलाल का पसा चुका दिया।

जीवा ने कुवेरलाल के साथ पाँच वर्ष तक काम किया और फिर दूसरे  
मालिक के साथ काम करने लगा। इस समय वह दूसरे मालिक की गुलामी में है।  
उसका सालाना बतन 150 रुपये है, पर उसे कभी एक पसा भी नहीं मिला।

जब उससे कहा जाता है कि बहुआ मजदूर प्रथा समाप्त हो गयी है तो  
मुमकिन है और सामान्य रहता है।

उमने जैसे साखा और नागा में जन्म यह बात बड़ी जानी है ता व भी चुप ही रहते हैं।

(2) पनिया गांव में 1961 में एक भीत औरत के बारे में जानकारी मिली जो महज 25 रुपये वज्र के कारण 20 वर्ष से गुलामी कर रही थी। बाद में उसके पति ने और ऋण लिया। वह औरत अभी भी सागरी है। उस जनाज पीसन के काम में लगाया गया था। उसने अपना मालिक को रुपये दन चाहे, पर मालिक ने पैसे लेने से इंकार कर दिया। 1961 में उसने विद्रोह कर दिया और काम बंद कर लिया।

1961 में सागरी प्रथा खत्म कर ली गयी। इस प्रथा के तहत कज लेने के कारण किसी हरिजन या सागरी को गुलाम बना लिया जाता था। जीवा के मामले से दृष्टा जा सकता है कि कजदार व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी सागरी बना सकता था।

1968-69 की एन रिपोर्ट से पता चलता है कि यह उन्मूलन कारगर नहीं हुआ है। 122 लागा स बातचीत में पता चला कि केवल 16 सागरिया को इस प्रथा के समाप्त किये जाने की जानकारी थी। उनमें से सबन यही कहा था कि कज चुपता करने का एकमात्र तरीका सागरी के रूप में काम करना है।

1975 में वधूआ मजदूर प्रथा को कानून के जरिए समाप्त कर दिया गया।

इस बीच सागरिया की संख्या में वृद्धि हुई है।

### तमिलनाडु

तमिलनाडु के उत्तर में दक्षिण जार्जेट जिले सचमुच वधूआ मजदूरों से भरे गिने हैं। यहां 40,000 से अधिक तादाद में वधूआ मजदूर हैं। धर्मपुरी जिले में ही 20,000 से अधिक वधूआ मजदूर हैं।

चंगलपेट, मदुर, तंजौर त्रिचनापट्टी और तिरुनेल्वेलि जिला में से प्रत्येक में दस से बीस हजार तक की तादाद में वधूआ मजदूर हैं। कोयम्बतूर में पाँच से लेकर दस हजार तक, रामनाथपुर और सेलम में पाँच सौ से लेकर पाँच हजार तक की तादाद में वधूआ मजदूर हैं। 1967 में प्रकाशित एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यह पद्धति नीलगिरि में भी चालू है यद्यपि 1969-70 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तमिलनाडु में यह पद्धति प्रचलित नहीं है। 1971-72 तथा 1972-73 में प्रकाशित दो अन्य रिपोर्टों में यह बताया गया कि नीलगिरि जिले के गुडालूर तालुक में शहरी रथतकारों में पनिया और बटट्टुयावना जो दोनों ही जनजातियाँ हैं, व लोग को ठेके पर खेती में लगा रखा है। राज्य सरकार ने यह दावा किया कि जनजातियों के ये लोग अपनी मर्जी

से ही काम करते हैं और उन्हें अपनी तनखाह के जलावा खाना और कपड़ा भी मिलता है। इन दाया की सत्यता के प्रति संदेह व्यक्त किया गया है। 1979 में अरमुगम की कहानी प्रकाश में आयी। वह अनुमूर्चित जाति का एक गरीब आत्मी था। आठ वर्ष की उम्र में उसे एक सवण हिंदू न पड़ियाल के तौर पर काम पर रख लिया। 1979 में उसे सत्रह साल काम करते हुए हाँ गये थे। तब उसकी उम्र पच्चीस वर्ष थी।

उसके पिता ने 100 रुपये उधार लिये थे और उसे पड़ियाल बनवा दिया था। उसके मालिक ने उसे प्रति वर्ष 300 किलो घान देन का वादा किया था। इसके बावजूद उसने सिर्फ 60 किलो घान और 37 पैसे प्रतिदिन दिये। अरमुगम सवेर 6 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता था। उसके मालिक के पास 27 एक्ड़ जमीन कई खेत जोतने वाले पशु, बीस गायें और ॥ बधुआ मजदूर थे। किसी ने अरमुगम को बताया कि पड़ियाल पद्धति को खत्म कर दिया गया है। वह अपने मालिक के पास गया और उसने यह माँग की कि उसका वेतन बढ़ाकर एक रुपया प्रतिदिन कर दिया जाये। उसने यह भी कहा कि पुराने ऋण को चुकता माना जाये। उसने स्वतन्त्र किये जाने की माँग की।

उसका मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि 500 रुपये अब भी पानना बाकी है। उसे आजाद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

अरमुगम भाग गया। उसके मालिक ने सोचा कि इस मामले को एक मिसाल बना देना चाहिए अथवा दूसरे पड़ियाल भी सिर उठान लगेग। उसने अपने चालीस गुडों की एक टोली का भेजा और अरमुगम का पकड़ मँगाया। उसे उन्होंने एक बिजली के खम्भे से बांधकर नशमनापूवक पीटा। भोजन और पानी के बिना उस चिलचिलाती धूप में बिजली के खम्भे से बंधा रहने दिया गया। उसकी जमीन का टुकड़ा भी छीन लिया गया और उसका वेतन घटाकर 30 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया।

1979 में तमिलनाडु में संभवतः 2,50,000 पड़ियाल थे। अरमुगम को अभी तक उनमें ही गिना जा रहा है।

(2) 1976 में पनियान आदिवासियों की दुख-दुदशा की बातें सुनी गयीं। शेद्री जाति के महाजनो ने उन्हें खाद्य-वस्तुएँ खरीदने के लिए कब्जा किया। बदले में पनियानों ने बिना वेतन के उनके खेतों में काम किया। कार्तिकेयन कमटो ने उनकी दुख-दुदशा के बारे में जाँच-पड़ताल की। पता चला कि कब्जा लेते वक़्त पनियानों ने एक साद कागज पर अँगूठे के निशान लगाये थे। इस प्रकार के बंधन में बंध गये। एक महाजन ने एक पनियान को 900 रुपये कब्जा दिया था और एक वर्ष बाद मूल-मूल समेत उससे 10,000 रुपये की माँग की। अन्तर्गत पनियान के पास बधुआ मजदूर बनने के सिवा कोई चारा न था।

तमिलनाडु में ऐसे हालात की मौजूदगी विलकुल स्वाभाविक है क्योंकि तमाम राज्यों की तरह तमिलनाडु पर भी सवण हिंदुओं का शासन है। जब कामराज मुख्यमंत्री थे तो रामनाड जिले में सवण हिंदुओं द्वारा हरिजनों का बस्ते आम किया गया था। वहाँ में, 1968 में जब अनादुर मुख्य मंत्री थे तो जिले में भी वे सवण हिंदुओं ने कम से कम चौघातीस हरिजन मद, औरतों और बच्चा को ओपडिया में बंद कर आम लपटा दी और उन्हें ज़िंदा जला दिया। मुख्य मंत्री अपराधियों को कानून के बंधन से छुड़ाने तक लाने में नायामयाब रह।

तमिलनाडु के सवण हिंदुओं को इस बात पर बहुत विश्वास है कि उन पर कोई आंच नहीं आ सकती। 1978 में विल्लुपुरम के एक व्यापारी ने एक हरिजन युवती के सामने एक अश्लील प्रस्ताव रखा और उस मुहल्ले, जिसे पेरिया कहते हैं के हरिजन युवकों ने 23 मार्च 1978 को प्रतिवाद किया। उस घनी व्यापारी ने उनके मुहल्ले पर 24 25 और 26 तारीख को हमले किये और उनकी आपडिया जला डाली। 12 अप्रैल के लडके और 35 वर्षीया महिला समेत बारह लोगों को पीट पीटकर मार डाला गया। यह घटना 27 जुलाई 1978 को हुई। इसके पहले, तीन दिन के अग्निबाड़ा में जने हुए सत्तर व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जा चुका था। प्रशासन और पुलिस विभाग निष्क्रिय बठ रह।

27 तारीख की घटना के बाद अचानक एक मंत्री एक पुलिस दल को साथ लेकर विल्लुपुरम में शांति कायम करने के लिए पधारे। पर इसके एक हफ्ते पहले ही हरिजनों के पेरिया में शमशान की शांति छान चुकी थी।

(3) जनवरी 1978 में पांडिचेरी के निकट पुरानसिंग पालयम के हरिजनों ने पौराणिक राजा हरिश्चंद्र की एक बंदी बनाने की कोशिश की। शमशान भूमि में उनके लिए निमत क्षेत्र में यह बंदी बनायी जा रही थी। सवण हिंदू उसी स्थान पर अपना दाह-संस्कार की बात सपन में भी नहीं सोच सकते। उन्हें हरिजनों की गुस्ताखी जखर गयी और उन्होंने उनके घर ढा दिये। दूकानदारों ने हरिजनों को घाने पीने की चीजें देने से इन्कार कर दिया, और हरिजनों को खेता पर भी काम करने से रोक दिया गया।

सरकार मजबूर थी।

(4) रजति नामक एक हरिजन युवती की मृत्यु दिसंबर 1978 में हुई और यह घटना 20 मार्च 1979 का सामने आयी जब उसके पिता ने तीन महीने तक प्यास पान के लिए मिप्पल दौड़ घूंप करने के बाद मक्की घटना प्रकट कर दी।

रजति नल्लिपालयम के पेरिया ना गोडार की गाय चराती थी। 19 दिसंबर 1978 का प्यासी रजति ने पशुओं की नाँद से पानी निकालकर पी लिया। उस निंद्यतापूर्वक पीटा गया, क्योंकि नॉन पवित्र गायों के लिए रखी गयी थी, अपवित्र हरिजन के लिए नहीं।

उस शाम वह घर नहीं लौटी और बाद में उसकी मृतदेह गोडार के कुएँ में मिली। सब परीक्षण में पता चला कि उसे जबरदस्ती डुबो दिया गया था। सेलम के पुलिस अधीक्षक ने इस मृत्यु को आत्महत्या करार कर दिया। गोडार पर रजत के पिता को रूपया देना चाहिए, पर यह हत्या का प्रमाण नहीं था।

1979 की एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि तमिलनाडु में हरिजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के शासन में यह हमेशा एक मजदूर चीख रही है। यह तत्कालीन कामराज, अनादुर और जनता पार्टी के शासनवालों में एक सी रही।

हमने यह पहले ही बताया है कि बधुआ मजदूरों और हरिजनों पर अत्याचार, दोनों की जड़ में एक ही मनोवृत्ति है।

## उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के बलिया, हमीरपुर, हरदोई, खेरी, सीतापुर, बिजनौर और बरेली जिलों में बीस हजार से अधिक बधुआ मजदूर हैं।

एटा, माँसी, मिर्जापुर, सहारनपुर, बस्ती, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, शाहजहाँपुर, मुलतानपुर, मेरठ, वाराणसी और देवरिया जिला में दस हजार से बीस हजार के बीच की तादाद में बधुआ मजदूर हैं।

बादा, बदायूँ, इटावा, जालौन, गाजीपुर, मथुरा, पीलीभीत, उन्नाव और नसीरत जिला में पाँच हजार से दस हजार के बीच की तादाद में बधुआ मजदूर हैं।

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, मैनपुरी और गाढ़ा जिलों में पाँच सौ से पाँच हजार के बीच की तादाद में बधुआ मजदूर हैं।

देहरादून, पीड़ी गढ़वाल, चमोली, त्रिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रामपुर और पन्नावाड़ जिलों के बारे में कोई जानकारी सुलभ नहीं है या प्राप्त नहीं की जा सकती।

कानून की 386वीं धारा के अनुसार बधुआ मजदूर नियुक्त करना दंडनीय अपराध है।

देहरादून जिले के जौनसार-बाबर क्षेत्र में कोल्हा और बाजगी लोग बधुआ मजदूर हैं। वे हरिजन हैं। उनके मासिक राजपूत हैं। यहाँ जिन रियाजों का चलन है उन्हें 'भाट' 'खंडित भंडित' और 'सजयेत' कहते हैं। उन्नाव जिले में इन 'साग-बाँध' कहा जाता है।

जौनसार-बाबर में कोल्हा और डोम-कोल्हा सागा का पचायना बाग 'गुमरी' नामक पद्धति के सहारे बस में रखा जाता है।

नीचे कुछ मिसालें दी जा रही हैं।



लेते हैं। बाद में इस ऋज को चुकता करने में अममय होने पर उन्हें ऋणदाताओं द्वारा चलाये जा रहे वेश्यालयों में अपनी पत्नियाँ को अर्पित कर देना पड़ता है। चंद वर्षों में ऋण को रकम दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है और लड़की की हेसियन बर्दिनी की हो जाती है। यह जघन्य व्यापार चलाने में भूस्वामियों को ग्राम पटवारियाँ और सरकारी अधिकारियों में मदद मिलती है।

इस सामाजिक पृष्ठभूमि में दौलती की करुणकथा को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

(1) जीनसार बाबर के करीब सभी कोल्टा परिवार बधुआ मजदूर हैं। कमला उर्फ दौलती घोरा गाँव की एक औरत थी। उसके पिता ने अनाज खरीदने और अपनी सबसे बड़ी लड़की की शादी करने के लिए 1,200 रुपये का ऋण लिया था।

जब दौलती की उम्र 16 वर्ष थी तब उसी गाँव के एक ब्राह्मण ने उसके पिता के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसका समूचा ऋण चुका देने का तयार है बशर्ते दौलती को उसने सुपुत्र कर दिया जाय। उसने कहा कि उसका उद्देश्य मर्यादापूर्ण है, क्योंकि वह दौलती से शादी करना चाहता है।

यह ध्यान रहे कि इस पहाड़ी अंचल की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं और यहाँ की स्थानीय कहावत है कि लड़की के जीवन के पहले दस वर्ष हँसी खुशी भर रहते हैं और उसने बाद आसू वहाँ की शुरुआत होती है।

दौलती का पिता राजी हो गया। उसका बच्चा चुका दिया गया और दौलती का भरठ ले आया गया तथा एक वेश्यालय में रखा दिया गया।

दस वर्षों तक उसने एक वेश्या का काम किया और ब्राह्मण उसकी समूची आमदनी को ऋण के भुगतान स्वरूप लेता रहा। वह उसकी बधुआ मजदूरिन बन गयी। जब वह तीस वर्ष की उम्र के निकट पहुँची तो उसका सौंदर्य चुका लगा और उसका रट पट गया क्योंकि शहर में ब्राह्मणों का ताज़ी देह चाहिए। तब उसे वापस घौरा ले आया गया, जहाँ वह पैदा हुई और बड़ी हुई थी, और वहाँ उसने अपनी टूटी देह में ग्रामीण ब्राह्मणों की सेवा करनी शुरू की।

उस ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसके लड़के ने उसकी जिम्मेदारी ममाली और उसकी आमदनी हमियाना शुरू किया। उसके लिए एक छोटी-सी ब्रापड़ी बना दी गयी जहाँ उसने अपना व्यापार जारी रखा।

दौलती यह नहीं जानती कि बीस वर्षों की वेश्यावृत्ति में उसका पञ्च पुत्र पाया कि नहीं, अथवा उसका बच्चा कभी चुक पायेगा या नहीं। वह अभी भी जिन्दा है, अपना घघा चलाती है, और अपनी आमदनी मासिक को दे दती है।

(2) जीनसार बाबर क्षेत्र देहरादून और उत्तरकाशी दोनों अंचलें अलग आता है। हम दूसरे अंचल की एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं



ग्राम	ऋणी	ऋणदाता	कारण	राशि	बधन की अवधि
सटटा	मीनू	बुलीलाल	अनाज	500 रु०	17 वर्ष
सटटा	मीनू	सालासिंह	अनाज	300 रु०	17 वर्ष
सटटा	मुखा	हुक्मा	शादी	300 रु०	18 वर्ष
सटटा	मुखा	ठाकुर	भेड़ खरीदना	35 रु०	5 वर्ष
सटटा	मुखा	सुल्कू	लडकी का बक्सा		
			खरीदना	20 रु०	10 वर्ष
सटटा	नंदा	दर्रासिंह	अनाज	100 रु०	12 वर्ष

तीना ऋणी हरिजन हैं और ऋणदाता राजपूत है। सभी समझौते मौखिक रूप से हुए हैं।

(3) उत्तरवाशी के पुरोला प्रखंड में जीप के जलावा जय शिपी वाहन का जाना संभव नहीं है। पुरोला के बाढ़ सड़का भील तक पहाड़िया हैं। यहाँ ग्राम पटवारी टक्स-तहसीलदार और पुलिस दोनों की भूमिकाएँ साथ साथ निभाना है। वे मददगार हैं। यहाँ से औसतन पचास लड़कियाँ हर साल अपने पिताओं, भाइयों और पतियों को ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए मरदानी इलाका के बंधालया को जाती हैं।

कुआँ ग्राम जो डमटा-नौगाँव सड़क पर स्थित है, के ब्राह्मण सरपंच माया राम ने 1961 में पानू नामक एक हरिजन युवती को विभिन्न बंधालया के हाथों चार बार बेचा है। हर बार वह किसी दलाल से शादी के लिए गये जान वाली रकम ग्रहण करने की रस्म अदा करता है और शादी की रस्म का मुआयना कर लेने के बाद उसे उसके हाथों बेच देता है। जब वह कुछ समय वहाँ काम कर चुकी होती है तो फिर वह उसे खरीद लेता है केवल दुबारा बेचने के लिए।

(4) 27 जुलाई 1974 को पुरोला गवर्नमेंट इंटरकॉलेज के प्रोफेसर प्रेमदत्त शर्मा ने श्यामा देवी नामक एक हरिजन लड़की को दिल्ली और देहरादून के बंधालया के हाथों बेच दिया।

ऐसी सभी घटनाओं में ग्राम पटवारी शामिल रहते हैं। एक पटवारी ऐसी औरत से आमदनी बढ़ोरने के लिए दिल्ली जाता रहता है।

जानकी नामक एक लड़की का वयान निम्नलिखित है

पुरोला की औरतों के लिए बंधावर्ति का कहीं जत नहीं है। पुलिस और सरकार ता केवल तमाशा ही करते हैं।

‘हमारे आत्मियों को ऋण से मुक्ति दिलाओ। उन्हें जमीन दो। केवल पुरोला के क्षेत्रों में आजात आत्मियों के हाथों उपजायी गयी हरी भरी फसले ही औरतों को मुक्ति दिला सकती हैं।

“और कोई उपाय नहीं है।”

## पश्चिम बंगाल

हम 1975 के बर्धित श्रम पद्धति उत्सादन अध्यादेश व शब्द 'मुनीश पद्धति' नोट कर लेना चाहिए। य दा शब्द पश्चिम बंगाल म बधुआ मजदूरों का अस्तित्व जाहिर कर देते हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से इनका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन अर्थ रूप से यह निश्चय ही मौजूद है। य रूप है— धातुआ, माहिंदार, वाराभासिया और मुनीश पद्धति जिसमें कृषि देकर अपना ठेके पर बधुआ मजदूर नियुक्त किए जाते हैं।

1976 म कुछ अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में बड़का तथ्य कह डाला है। देहाती क्षेत्रों में त्रमण चढ़ती तापद में लोग अपनी जमीन छोड़ बैठ रहे थे और इसका कुछ परिणाम था तेत मजदूरों की तादाद में वृद्धि होना। पूर्ण मौसम का पीछे छोड़ रही थी और परिणामस्वरूप तनवाह घट रही थी। इन मजदूरों के लिए तय की गयी 'यूनितेड मजदूरों के नियमों के अनुसार कोई भूस्वामी बतन नहीं दे रहा था। पश्चिम बंगाल में जोनदार ही महाजन थे। उन्होंने मजदूरों को अपने बतन के साथ खाना भी देकर बधुआ बना लिया।

1961 म 1971 के बीच मिर्नापुर में भूमिहीन मजदूरों की तादाद 23 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गयी। पूरे पश्चिम बंगाल के आधार पर ये आँकड़े 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत हैं। इन दश वर्षों में फामरा की तादाद घट गयी। जानदार लागू पूरी भूमि का इन्फेक्शन बढ़ रहा था। यह स्वाभाविक था कि ऐसे मजदूरों की उन्नत द्वारा बधुआ मजदूर बना लिया जाता।

मुझे ये इलाके बाकुडा, पुर्नलिया और मिर्नापुर जिला में, जहाँ मान में बेचन एक ही पसल हानी है मजदूर माल भर में जाठ महीन जोनदार महाजन से मिलन वाल बज पर बिना रहते हैं। इन तीनों जिलों में मजदूरों का तन बड़ा जानदार के तना में बुआई, रोवाई और कटाई के दौरान काम करने की मौद्रिक शक्तों में बढ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे उस पत्र बिना बतन के काम करते हैं जब उनकी आमदनी हो सकती थी। बाकुडा और पुर्नलिया के ग्रामीण, पिछड़े जिलों में मजदूरों का तन भर तन जानदार के लिए धातुआ अर्थात् वाराभासिया के नीचे एक काम करते हैं। वष की समस्या पर इन मजदूरों का उनका उन्नत के अनुसार पाँच से नकर बारह मन तक धानन मिलता है। जानदार के ही पर ॥ रहा पाते मजदूरों का ग्राहक-व्यवसाय मिलता है।

पुर्नलिया के मिर्मा और बापमूटी में एक दूसरी पद्धति है। मजदूरों को धारागी 5 रकम प्रति बीघा की दर पर आवासिया में जमीन १०००००००० है। वे एक बीघा और ग्राहक भी देते हैं। आवासियों का तन उन्नत मजदूरों का

और फसल होने पर व्यापारी उसे लेकर बेच देते हैं।

पश्चिम बंगाल में बहुआमजदारी की पद्धति का प्रचलित रिवाज के सदृश में समझना होगा। जहाँ मजदूर राजनीतिक रूप से सचेत हैं, वेतन थोड़ा अधिक है। भातुजा और बारोमासिया लोग थोड़ी अच्छी हालत में हैं। लेकिन यह दृष्टांत विरल है। कहा जाना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक चेतना अधिक सजीव है। पर यही परता बहुआमजदारी की पद्धति का सबसे शानदार तर्जुमा में जारी रखा गया है।

(1) बीरभूम जिले के इलाम बाजार ग्राम में भादुरबुनी गांव में गनी मडल नामक एक जोतदार है। वह 200 बीघा जमीन एक बड़ी परचून की दुकान और आटा पीसाई की मशीन का मालिक है। इलाम बाजार में उसके दो पक्के मकान हैं। उनमें पशुओं के व्यापार में दो लाख रुपये और सूदगारी में 6 लाख रुपये लगा रखे हैं। वह पांच माहिंदार रखता है।

उम से एक का नाम इरफान शेख है। उसके पास चार बीघा जमीन है। उसके परिवार में आठ सदस्य थे। उसने एक बार गनी से थोड़ा धान कज पर लिया था। गनी का नियम था कि अगर एक मन उधार लिया जाय तो दो मन वापस करना होगा। इस कृण के कारण इरफान का अपनी जमीन गनी को सांपनी पड़ी और तीस वर्ष की उम्र में वह गनी का माहिंदार बन गया। बारह वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गयी और कज चुकाने का भार उसके सड़क रहमान के कंधा पर आया। उसे गनी से प्रतिदिन एक बार का भोजन मिलता था और प्रतिमाह 37 किलो चावल। पांच वर्ष तक माहिंदार रहने के बाद रहमान के पेट में जलसर हो गया। वह काम नहीं कर पाया और गनी ने उसका मरना भी ल लिया।

रहमान भाग गया। बाद में वह वापस लौटा और उसने शादी कर ली। गनी ने उसमें उसकी पत्नी को छीन लिया जिससे बाद में गनी के बच्चे का जन्म दिया। रहमान ने प्रतिवाद किया। उसके खिलाफ अपराध का एक फर्जी मुकद्मा खड़ा किया गया। वह मुकदमा अभी तक चल रहा है।

रहमान अभी तक मजदूरी करता है। पिता और पुत्र ने मिलकर मजदूरी के सत्रह साल पूरे कर दिये। अब भूत, जो इरफान का दूसरा लड़का है गनी का माहिंदार बन गया है। दो वर्ष तक काम करने के बाद, उसने एक बार गनी द्वारा एक नौकरानी पर बलात्कार करने के खिलाफ प्रतिवाद किया था। गनी ने उसे निकाल बाहर किया।

(2) उसी गांव में एक और जोतदार है जिसका नाम इरफान शेख है। उसके पास 65 बीघा जमीन है और उसने सूखोरी में एक लाख रुपये लगा रखे हैं। उसके पास तीन माहिंदार हैं। उनमें से एक अमसुल हसन है। अभी उसके पास

डेढ़ बीघा जमीन थी। एक बार इरफान न शमसुल के पिता को दा म न धान उधार दिया था। उसने ऋण के एवज में शमसुल के परिवार का अपना माहिन्दार बना लिया। वह परिवार के केवल एक सदस्य को भोजन देता था और हर सदस्य से काम कराता था। दरअसल, उसके पास तीन माहिन्दार नाम मात्र के लिए थे। वह सिर्फ एक को वतन देता था और दूसरों से उगने मुफ्त में ही काम कराया। शमसुल के पिता और बरदाश्त न कर सके और वे भाग गये। शमसुल और उसका परिवार अभी तक वधुआ हुआ है। जब इरफान के अपन खेतों में काम नहीं रहता तो वह उन्हें दूसरे के खेतों में काम करने भेजता है और उनकी आमदनी खुद हथिया लेता है। ऋण देन पर वह 240 प्रतिशत सूद लेता है।

(3) इलाम बाजार थाने के नाचनशा गांव के रामकृष्ण वधुआध्यापक मिलिये। वह कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वह फारवड ब्लॉक (भावसवादी) पार्टी का नेता है और बिलासी गांव की पचायत का उपप्रधान है। ऐसा सुना जाता है कि 1980 के मई महीने में कभी फामरो न पचायत कार्यालय को घेर लिया था और कार्यालय के अधिकारियों से पचायत के काप की राशि 90 000 रुपये का हिसाब मांगा था। सभी अधिकारियों ने कब्ज कर लिया कि रामकृष्ण के जन्मे गबन की राशि बी 5,700 रुपये।

वह 60 बीघा जमीन का मालिक है। उसका कोई बगदार (बटाई पर जमीन जोतने वाला) नहीं है और मोना माहिन्दार बीस बीघा जमीन जोतते हैं।

धुमू लोहार उन माहिन्दारों में से एक है। वह 28 वर्ष का है। खाना, 200 रुपये, दो लुगिया, तीन धोलिया, सालाना एक बनियाइन और एक दिन में पांच बीडिया—यही उसका वेतन है। वह भोर चार बजे में लेकर शाम के सात बजे तक खेत में या घर पर काम करता है।

जब रामकृष्ण पचायत का उपप्रधान बन गया तो उसने माहिन्दार और मौदरानिया को वतन देना बंद कर दिया। इसके बजाय वह उन्हें पचायत को काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत मिले भंडार से गेहूँ देता है।

वीरभूम में प्रचलित वतन दर के अनुसार धुमू लोहार के काम का वेतन 11 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए। जिले का वतन दर आधिकारिक सरकारी दर से बहुत कम है। धुमू के परिवार में लगभग सात सदस्य हैं। उनमें से सिर्फ उसका ही खाना मिलता है। अपने परिवार को खिलाने के लिए उसे रामकृष्ण से उधार लेना पड़ता है।

इस प्रकार उसने कष्ट का पहाड़ बढ़ा दिया है।

यह अंतिम दृश्य सच्चे मायना में पश्चिम बंगाल की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही राज्य है जहाँ हर जिले में हजारों तथाकथित व लोग प्रश्नहीन रूप से जमीन के मालिक हैं। व फर्जी नामों से इस जमीन

कब्जा जमाय रखते हैं जो तय की हुई सीमा से अधिक होती है।

पचायत बन जान से उनके हाथों में बेशुमार शक्तियाँ आ गयी हैं। वे प्रखंड विकास पदाधिकारियाँ, अनुमंडल दहाधिकारियाँ और पुलिस अधिकारियाँ जैसे पिटठुओं पर हुकूम चलाते हैं। वे भालुआ, माहिंदार चारोमासिया तथा मुनीश पद्धतियाँ को जिलाय रखते हैं। वे बहुआ मजदूरों के पसीने से मुनाफा कमाते हैं। उनकी भूमि में उत्पन्न अनाज के बगदारी के अनुसार बंटवारा का दज नहीं किया जाता। राज्य सरकार के ग्रामीण दम्तों में निलज्ज रक्तशायक शामिल हैं। सरकार ने इन लोगों पर गांव के निवासियों का भाग्य सुधारन की जिम्मेदारी सौंप रखी है। अथ राज्या में जैसा होता है वसा ही यहा भी होता है। उनकी शक्तियाँ असोमित हैं। आधिकारिक पुस्तिकाओं में वर्णित पश्चिम बंगाल का कहीं अस्तित्व नहीं है।

जो लोग सत्ताधारी पार्टों का पक्षपायक बनन को तयार हैं उन्हें सत्ता भी मिलेगी सुयोग भी।

जितने आंकड़े मिल सके हमने प्रस्तुत किये हैं। अब यह ज्ञात हो चुका है कि बहुआ मजदूर प्रणाली चारा ओर फली हुई है। निम्नलिखित सात ज्वालों की स्थिति खास तौर पर निरूपित है

- 1 उत्तरी तमिलनाडु—धमपुरी उत्तर व दक्षिण आर्कोट, चेंगलपेट।
- 2 आंध्र प्रदेश—तलगाणा, हैदराबाद, आदिलाबाद भडक, करीमनगर महबूबनगर नासगाडा, निजामलड वारंगल।
- 3 गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र—गुजरात में वतसाड सूरत, वडोदा, पंचमहल। महाराष्ट्र में नासिक, धुलिया और तालगाव।
- 4 मध्य गुजरात—मेहसना, सुरेद्रनगर, काठिया में सक्कर राजकाट तक।
- 5 समूचा उत्तरी मध्य प्रदेश—महाकोशल, राजगड, रतलाम बिदिशा, गुना, मुरना, सागर, छतरपुर सतना, रीवा, शहदाल मरगुजा रायगड, बस्तर।
- 6 पश्चिमी उत्तर प्रदेश—बिजनौर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरली, खेरी, सीतापुर।
- 7 उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तरी सीमाव क्षेत्र—उत्तर प्रदेश में वलिया और देवरिया। बिहार में चम्पारन और सारन।

निम्नोक्त प्रत्येक जिले में 40,000 से अधिक बहुआ मजदूर हैं—तमिलनाडु में उत्तर व दक्षिण आर्कोट, आंध्र प्रदेश में नासगाडा और करीमनगर कर्नाटक में शिवमोगा, महाराष्ट्र में अहमदनगर गुजरात में वडोदा, मध्य प्रदेश में सतना,

शहडाल और वस्तर, बिहार में पलामू और उत्तर प्रदेश में देवरिया।

बधुआ मजदूर प्रणाली का पूरा बयान करना असंभव है। यह बिहार में हलवाहा के छदमवेश में छिपी रहती है, तो पश्चिम बंगाल में भातुआ-माहिंदार-चारोमासिया के छदमवेश में। कौन जानता है कि अग्रे छदमवेश कौन-सा है?

स्वतंत्र किया गया बधुआ मजदूर और अग्रे आदिवासियों का ठेकेदारा द्वारा 'पुराना' मजदूरों के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है और उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों परियाजनाआ, कोयला खानों और चाय बागानों में काम पर लगाया जा रहा है। उन पर अभी तक जुल्म ढाये जा रहे हैं। इस तरह पुरानी पद्धति में एक नया लबादा आठ लिया है। इस परिदृश्य पर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं तैयार की गयी है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिला में चमार हलवाहा का 'गोबर' पद्धति के तहत भोजन दिया जाता है। ऐम मजदूरों का आमतौर पर खाना मिल जाता है। मगर यहाँ सवण हिंदू मजदूरों का खाना नहीं दन।

धान झाड़ने के दौरान पशु दाना भूमा खाता है और जा अश पचना नहीं वह गोबर के रूप में बाहर निक्स आता है। हलवाहे उसे साफ करत हैं, गुग्यान हैं और उस पीसकर अपना भोजन तैयार करत हैं। पर इस घाथ का भी मूल्य आँका जाता है और इस उनके वेतन से घटा लिया जाता है। पाँच या छह बला के गायर स एक मन अनाज या दाना निक्स आता है।

जब तक बहुसंख्यक लोगो की अल्प संख्या की व्यवस्थाओं जस 'गोबर' पर निर्भर करना पड़ता है, तब तक बधुआ मजदूरों की पद्धति मौजूद रहगी।

हम अब भी यह नहीं जानते कि दशक तमाम हिस्सा में क्या हो रहा है? हमारे सामने महज आंशिक तस्वीर है। जब तक उत्पीड़ित लोग आवाज नहीं उठाते तब तक हम नहीं जान सकेंगे।

य आवाज उठा पायें, इसने लिए बाड़ी कुछ करना बाड़ी है।

28 अक्टूबर, 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद ने बहुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने से संबंधित 'बधित थम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम' पर हस्ताक्षर किये। इस अधिनियम का परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है। उस वष जुलाई में थम मंत्रियों की बैठक में इस विषय में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उनके अनुसार 22 राज्यों में से 18 राज्यों में इस प्रथा का काफी चलन था। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किये।

राष्ट्रपति के अध्यादेश में कहा गया था कि

1 इस अध्यादेश के जरिए देश में विद्यमान बधित थम के सभी रूपा को समाप्त किया जाता है। ये रूप हैं आदियामार, बारोमासिया, बसहया, बंधू भगेल, चेरुमार, गारुगल्लू हाली, हारी हरवड हालया, जावा, जीता, पमिया खुडित मुडित, कुधिया, लेपेरी, मुझी, भट, मुनीश पद्धति, नित मजूर पलेर पडियाल, पनाइलाल सामडी सजी, सजावत सेवक सेवकिया सरी बटटी। इसके जरिए अब से सभी बहुआ मजदूर स्वतंत्र किये जाते हैं। पेशगी रकम देकर अब कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता।

2 उन ऋणा को रद्द किया जाता है जिनकी बजह से बहुआ मजदूरों को काम के लिए मजबूर किया जाता था।

3 मुक्त किये गये मजदूरों का जमीन से हटाया नहीं जा सकता।

4 यदि कोई जमीन किसी महाजन के पास बघक रखी गयी हो तो यह जमीन मुक्त हुए बहुआ मजदूर को वापस कर दी जायेगी, जिसका इस जमीन पर पूरा अधिकार होगा।

5 अब से कोई भी महाजन पुराने कबाया कज के आधार पर जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता। यदि इस तरह के दावे किये जाते हैं तो उक्त महाजन पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा तीन मय की जेल या दाना

सजाएँ दी जा सकती ह।

एक सतवत्ता समिति का गठन किया जाना था जो यह देखेगी कि अध्यादेश के सभी प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। इसका काम मुक्त किये गये बधुआ मजदूरों के आर्थिक पुनर्वास की भी देखरेख करना था।

इस मामले में भी कानून और इसे लागू किये जाने के बीच काफी बड़ा अंतर था। बड़े-बड़े सामंता के निहित स्वार्थ कानून को चलन नहीं दे सकते थे क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक हानि होती थी। इसलिए जानबूझ कर इन कानूनों में कोई-न-कोई खामी छान दी गयी ताकि इन्हें आसानी से न पाटा जा सके। राज्य सरकारों ने अध्यादेश की उपेक्षा की। उन्होंने जानबूझ कर मौजूदा बधुआ मजदूरों की संख्या को कम करके दिखाया और समय-समय पर बड़ी हठधर्मिता के साथ कहा कि उनके राज्य में एक भी बधुआ मजदूर नहीं है। इसीलिए उनके द्वारा प्रदर्शित आकड़ों के अनुसार यह तादाद महज 1,20,000 थी।

लेकिन राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अपने सर्वेक्षण में यह साबित कर दिया कि देश में लगभग 23 लाख बधुआ मजदूर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया कि उसके राज्य में एक भी बधुआ मजदूर नहीं है। हमें पता है कि बारोमसिया, माहिंदार, भुजुआ जादि के नाम से ज्ञात बधुआ मजदूर इस राज्य में हैं और हर वर्ष उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। बधुआ मजदूरों का अस्तित्व बना हुआ है, पर पश्चिम बंगाल सरकार अपनी खामोशी के जरिए और अपने उपेक्षा पूर्ण रव्य के द्वारा इस प्रणाली के प्रसार में मदद पहुँचा रही है।

कोई भी व्यक्ति इसके लिए राज्य सरकार की उदासीनता, अफसरा की अक्षमता आदि का दोषी ठहरा सकता है। सचार्इ यह है कि सरकार धरलू और विदेशी दोनों सामंतों तथा पंजीपतिया के हितों पर ध्यान देकर ही शासन चलाती है। सरकार ऐसे कानूनों को लागू कर ही नहीं सकती जो इनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचायें। लेकिन कानूनों का पारित किया जाना जरूरी था वरना किसान लोग विद्रोह कर देते। सरकार जानती है कि ये कानून निरर्थक हैं और इनसे उन किसानों का कोई भला नहीं होगा जो गरीब हैं और दूसरे पर आश्रित हैं। अदालत में जाने का मतलब है वेहद खर्च। साथ ही किसान उन महाजनों और जोतदारों का नाराज करना भी नहीं चाहते जो खेत में काम न होने के दिनों में भी उन्हें कर्ज देते हैं और इस तरह के कर्जों पर किसान आश्रित रहते हैं। यदि वे नाराज हो जायेंगे तो भविष्य में कर्ज नहीं मिल सकेगा। इसका दुःखद पहलू यह है कि ऐसे ही कर्जों को लेकर उन्हीं बधुआ मजदूर बनना पड़ता है। वे कोट-बचहरी में जा नहीं सकते। अगर वे अदालत का सहारा लेते हैं तो भविष्य में क्या वे फिर कर्ज ले सकेंगे?

सरकारी विभाग भी पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं हैं और उनमें से ज्यादातर



ग्रामीण क्षेत्रों में महाजना तथा जोतदारा के प्रभाव में हैं।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिन बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था, वे फिर महाजना के चंगुल में पड़ गए।

नवम्बर 1977 में रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम ने बंधुआ मजदूर प्रणाली पर आयोजित तीन दिन की कार्यशाला में अपने लिखित भाषण में बताया कि इस समस्या की जड़ में 'आर्थिक स्थितियाँ' हैं। हजारों लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं और ऐसे ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं जिनके कारण उन्हें बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें साधारण मजदूर से बहुत कम मजदूरी दी जाती है और उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कानून बना देना ही काफी नहीं है। 'नौगा की चेतना' का विकसित करना और व्यवस्था के खिलाफ उन्हें छाड़ा होने में मदद देना भी जरूरी है।

1975 में अध्यादेश पारित हुआ और 1976 में संसद में बताया गया कि आंध्र प्रदेश में 14 और बिहार में 581 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया।

क्या किसी को विश्वास होगा कि इन दोनों राज्यों में बंधुआ मजदूरों की सट्टा बस यही थी? श्री जगजीवनराम ने कहा कि जब तक सामाजिक तौर पर स्वीकृत वण-व्यवस्था को दूर नहीं किया जाता, भयंकर गरीबी दरिद्रता और रोजिंदारी मजदूर प्रथा को नहीं समाप्त किया जा सकता। वण व्यवस्था का असर गरीबी में भी है। इसी वजह से ही वे निम्नतम मजदूरी पर काम करने को विवश होते हैं। उनकी गरीबी ने उन्हें बंधुआ मजदूर का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताने का निवश किया।

एक उदाहरण प्रस्तुत है

8 अक्टूबर, 1977 को बिहार सरकार के धर्म सचिव ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों के नाम एक सवलर (सं. ए. ए. सी. 10140 एल० इ० 813) भेजा। इस सवलर के जरिए जिलाधिकारियों का निर्देश दिया गया था कि जहाँ वे यह महसूस कर रहे हैं कि जमींदार और रैयत एक दूसरे के खिलाफ हैं और उनके बीच झूठभेड़ की आशंका है, वे 'न्यूनतम' वतन कानून लागू करें। यह निर्णय निकाला जा सकता है कि कुछ जमींदार और जोतदार 'न्यूनतम मजदूरी' देने के बारे में अनिच्छुक थे।

जुलाई 1975 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा ने बंधुआ मजदूर प्रणाली समाप्त करने में सम्बंधित विधेयक का विधान सभा में पेश करते हुए कहा था कि बंधुआ मजदूरी कराने वाला व खिलाफ भीसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तत्कालीन धर्ममंत्री श्री राजमंगल पांडेय ने कहा था कि इस विल से इस बात की गारंटी होगी कि एक एक्ड़ वाले छोटे किसानों

से लेकर वधुआ मजदूरी करन वाल सभी लोगो को स्वतन्त्र कर दिया जायेगा। वास्तविकता यह है कि कुछ भी नहीं हुआ और साल दर-साल वधुआ मजदूरा की सपना बढती हो गयी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वधुआ मजदूरी कराने वाला के गिलाफ मोसा का रस्तमाल किया गया हो। अक्तूबर म राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद भी स्थिति म कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

जून 1976 की एक सरकारी रिपोर्ट म बड़े श्व के साथ दावा किया गया कि आठ राज्या म 48 636 वधुआ मजदूरो का स्वतन्त्र कराया गया और जयो का मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। जिनको मुक्त कराया गया है, उन्हें जमीन दवर या पशुपालन, मुर्गीपालन, ग्रामीण कला व शिल्प जाति म लगाकर फिर स बसाया जा रहा है। सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण बैंक और सामाजिक कार्यकर्ता—सभी उनकी जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी आर्थिक अवस्था पर विचार किया जा रहा है। मुक्त किये गये मजदूरा मे से 14 आंध्र प्रदेश स 581 बिहार स 27195 बंगाल मे 19000 उत्तर प्रदेश से, 10112 राजस्थान से 481 तमिलनाडु से 243 मध्यप्रदेश से और 10 उड़ीसा स थे।

उस वष सितम्बर माह म केन्द्रीय समीक्षा समिति की रिपोर्ट म बताया गया कि आठ राज्या म 75,000 वधुआ मजदूरा का पता चला है। उनम से 55,000 को मुक्त करा दिया गया है। इन मुक्त कराये गये लोगो मे से तीन हजार मजदूरा का फिर से बसाया गया है।

बिहार सरकार न भी वजुआ मजदूरा का पता लगाने उह मुक्त कराने और उनक पुनर्निर्माण के लिए सतकता समितिया और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की। कानून का उल्लंघन करन के लिए दा व्यक्तिया को सजा दी गयी और उह एक वष के लिए जेल भेज दिया गया। आज प्रदेश म भी ऐसी ही व्यवस्था की गयी जहाँ वधुआ मजदूरा को स्वतन्त्र कराया गया और खेती करन तथा रहन के लिए उह जमीन दी गयी। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान मे भी यही हुआ। उपराक्त सभी मामलो म और छासनीर से जादिवासी इलाका म कानून को अमल म धान म ढिलाइ देखी जा सकती है। फलस्वरूप मुक्त कराये गये वधुआ मजदूर नरवारी मन्द के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकते थे। साथ ही अध्यादेश क जा जान स जोतदारा महाजना तथा मजदूरा के बीच सवध कटु हो गये थे। इस बात की संभावना नहीं रहे गयी थी कि मुक्त कराये गये वधुआ मजदूर का मातिका के सेन पर फिर काम मिल सकेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मुक्त कराये गये मजदूर एक बार फिर वधुआ बनन के लिए मजबूर हो गये।

1978 के जाकडा स पता चलता है कि 56 प्रतिशत वधुआ मजदूर पिछले हैं

तीन वर्षों म और 33 प्रतिशत पिछन एक वर्ष म बहुआ बनाय गय ।

अनक राज्य सरकारें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों स इस प्रथा के उन्मूलन को अपन यहाँ स्वीकार नहीं कर सकी । जो भी कदम उहनि उठाये वे महज केन्द्र सरकार के दबाव के कारण थे । जस हो श्रीमती गांधी बनाव हार गयी और जनता पार्टी सत्ता म आयी, उहान अपन सार प्रयास छाड़ दिय । हजारों मजदूरों का जिह मुक्त कराया गया था, भूखे भेडिया के सामन पाव दिया गया । राजस्थान का दृष्टांत उल्लेखनीय है । यहाँ वास्तविकी कानून और जागीरदारी प्रथा के समाप्त हान के बाद जबरन मजदूरी प्रणाली समाप्त हा गयी थी । लेकिन बहुआ मजदूर (जिह सागरी कहा जाता था) का अस्तित्व बना रहा । छोटे छोटे कर्जों के कारण हजारों खेतिहर मजदूरों को गुलामी के लिए मजबूर किया गया । श्रीमती गांधी के शासन-काल म 5,384 बहुआ मजदूरों को मुक्त किया गया । उनके पुनर्वास का जिस समय प्रयास किया जा रहा था जनता पार्टी सत्ता म आ गयी और राजस्थान म हरिदेव जाशी की सरकार ने जोतदारों और महाजनों के खिलाफ जा भी मामलें थे, वापस ले लिये । इससे बाद यहाँ की सरकार का पतन हो गया और राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और तब तत्कालीन राज्यपाल न पिछली सरकार द्वारा लिये गये फैसलों का पालन करन का फैसला किया । सागरी मजदूरों के 693 मामलों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया जिनमे से 77 को सजा हुई और मृत्यु के अभाव म 77 को रिहा कर दिया गया । अपन खिलाफ मामले वापस ले लिये जान के बाद इन सभी न एक बार फिर नये जाश के साथ अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी ।

मध्य प्रदेश का उदाहरण लें । यहाँ राज्य सरकार बहुआ मजदूरों का पता नहीं लगा सकी बल्कि यह कहना ठीक होगा कि इसन बहुआ मजदूरों का पता नहीं लगाया । इसलिए उनको मुक्त करान और उनको फिर से बसाने के मिलसिल म भी कुछ नहीं किया जा सका । केन्द्र सरकार द्वारा दिय गये दा करारों के बावजूद कोई दस्तमाल नहीं हुआ और बन्धु-विवाही म पड़ा रहा । 1978 म राष्ट्रीय श्रम संस्थान न एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमे कहा गया था कि राज्य म बहुआ मजदूरों की संख्या 5 लाख है । 42 जिलों के 172 गावों म बहुआ मजदूरों की मौजूदगी तलाबी गयी थी जिनमे अधिकांश हरिजन तथा आदिवासी थे । इम से विशेष रूप से उल्लेखनीय जिले हैं—बिलासपुर, शहडोल, सरगुना, विदिशा, सतना, रायगढ़ और बस्तर । इनम म प्रत्येक जिले म 20,000 से अधिक बहुआ मजदूर थे । इसके बाद बालाघाट, छतरपुर, माडला, राजगढ़, सागर, रीवा, गुना और मुरना का स्थान ह । इम स प्रत्येक म 10,000 से 20,000 बहुआ मजदूर थ । इसके बाद तीसरे स्थान पर है—धार, इन्दौर, रायसोन, रतलाम, सेहोर, शाजापुर, खडगोन, उज्जैन, खालियर और शिवपुरी । इनमे से प्रत्येक म

5,000 से 10,000 बधुआ मजदूर थे। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के आयुक्त की विभिन्न रिपोर्टों तथा मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ द्वारा किये गये प्रयासों के जरिए भी इन आँकड़ों की पुष्टि की जा सकती है। फिर भी राज्य सरकार इन बधुआ मजदूरों की शिनायत नहीं कर सकी—वैश्व आपातकाल के दौरान हमने महसूस किया कि राज्य में बधुआ मजदूर हैं। घड़ी आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल थी। बाद में, जिन बधुआ मजदूरों को आजाद कराया गया था वे एक बार फिर बधुआ बन गये, क्योंकि उन्हें कोई मदद नहीं दी गयी।

इस अध्यादेश का महाराष्ट्र की स्थिति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य सरकार ने यह मानने से इन्कार किया कि उसने यहाँ बधुआ मजदूर हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में अध्यादेश का लागू करने का मकसद ही नहीं पड़ा हुआ और मामला के हित बरकरार है।

फिर भी सर्वेक्षण से पता चलता कि यहाँ बधुआ मजदूरों की समस्या उल्लेखनीय थी। इस संतुलन में बुरायत जिले में—धान, बालावा, नासिक, धुलिया और चंद्रपुर। 1976 में अगस्त से अक्टूबर के बीच भूमि-मनाआ ने पानघाट तालुका के 190 गांवों में से 20 का सर्वेक्षण किया जहाँ आदिवासियों की संख्या काफी थी। केवल 20 गांवों में इन्होंने 261 बधुआ मजदूरों का पता लगाया। इन सबसे मिल पाना संभव नहीं था और इनमें से अधिकांश मजदूर माहूँकारा और महा-जना से इतने भयभीत थे कि जुवान भी नहीं खानत थे। लगभग सभी लोग बातचीत की गयी और बातचीत के दौरान पता चला कि इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को इसलिए बधुआ बनना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने बज लिया था और बज की यह राशि 600 रुपये में कम हो गयी। शेष लोग 600 रुपये में 1500 रुपये के बीच की राशि बज के रूप में वेतन के कारण बधुआ बन गये। लगभग 33 प्रतिशत लोग छह वर्ष में भी कम समय से बधुआ रूप में काम कर रहे थे। शेष 6 वर्ष से लेकर 21 वर्ष से बधुआ बने हुए थे। जिन 100 लोगों में बातचीत की गयी उनमें से 35 लोगों का यह दावा भी नहीं था कि उन्होंने कितना रूपये बज के रूप में लिया। 87 लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका उमर अभी कितना बज बाकी है। 70 लोगों का अपना बज की व्याज दर का पता नहीं था।

100 मजदूर ऐसे थे जो प्रतिदिन 11 घंटे काम करते थे। 21 लोगों का बचपन से ही बधुआ था और शायद वे वाद भी उसकी यही स्थिति बनो रही। 79 लोग ऐसे थे जिन्होंने शादी के बाद इस दुभाग्य का शिकार होना पड़ा। इन 100 में से एक मजदूर ऐसा भी था जिसे नकद या अन्य रूप में कोई बचत नहीं मिलता था—उसे बस दोनो बच्चे खाना मिलता था। दो मजदूर एक ही जिन्हें प्रतिदिन

दो रुपये मिलते थे। 97 मजदूरों का वतन के रूप में आज दिया जाता था। 71 मजदूर ऐसे थे जिन्हें प्रतिदिन 1 प्याली (600 ग्राम) चावल मिलता था। 26 लोगों का हर महीने 20 प्याली वतन के रूप में मिलते थे—रह अतिरिक्त रूप से 20 प्याली और दिया जाता था जिससे इनका कच्चा बराबर होता था। महिला मजदूरों का प्रतिदिन एक प्याली चावल मिलता था। इन तीनों लोगों में से 13 मजदूर अकेले थे और 43 दम्पति थे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में वधुआ मजदूरों की मौजूदगी से इकार किया। फिर भी अक्टूबर 1975 में हरिजन सेक्टर सपन मिरमार जिले के पुण्डु तानुष में 12 गाँवों का सर्वेक्षण किया और 63 वधुआ मजदूरों का पता लगाया। ये काली और डाम जाति के थे—जाना जातियाँ हरिजन हैं। इन पर सौ रुपये से लेकर तीन हजार रुपये का कच्चा था। इन्हें अपनी गुलामी के बदले में थोड़ा सा चावल और पुराना कपड़ा मिलता था। अनुभव बताया जा सकता है कि अजय जिला में भी यह प्रथा प्रचलित थी।

सरकार ने धूम्र इस प्रथा के अस्तित्व से ही इकार किया था इसीलिए इससे उन्मूलन का सवाल भी नहीं पड़ा हुआ। इस प्रकार निहित स्वार्थी तत्वा ने इससे सख्त अध्यादेश का नाकाम कर दिया।

सितम्बर 1976 में नयी दिल्ली के सूत्रों से पता चला कि 73,909 वधुआ मजदूरों की शिनायत की गयी थी। इनमें से 55,555 का मुक्त कराया गया और 3,039 का फिर से बसाया गया। वधुआ मजदूरों के बारे में सरकारी तौर पर जा आकड़े एकत्रित किये गये थे इनमें आंध्र प्रदेश में 826, त्रिपुरा में 581, उड़ीसा में 285, मध्य प्रदेश में 243 राजस्थान में 4,974 तमिलनाडु में 2,416, कर्नाटक में 33,584, और उत्तर प्रदेश में 39,000 थे।

उस वर्ष राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण के 27वें चक्र में जो सर्वेक्षण हुआ, उससे एक अलग ही तस्वीर उभर कर आयी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नियमित वतन पान वाला कर्मचारियों और वतन भोगी मजदूरों में भी वधुआ मजदूर थे। इनका प्रतिशत हिमाचल प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में क्रमशः 0.74, 5 और 2.3 था। देश में कुल कामकाजी लोगों की संख्या 24 करोड़ थी जिसमें से 70 लाख वतनभागी कर्मचारी और मजदूर थे। इन आँकड़ों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा अनुसूचित जातियाँ और जाजातियाँ के आयुक्त ने भी समर्थन दिया था।

सरकारी जाबडों और सर्वेक्षणों से प्राप्त आँकड़ों में इतना ज्यादा अंतर क्या था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाजनों और जोतदारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने वधुआ मजदूरों के अस्तित्व से ही इकार किया था। यदि ये इनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेती तो इन मजदूरों का मुक्त कराने के

लिए कानूनी कदम उठाने का भी सवाल पड़ा होता। इससे निहित स्वार्थी तन्त्र का चाट पहुँचती जा मौजूदा सामाजिक स्थिति में समभव नहीं था। इसी कारण यूननतम मजदूरी कानून भी लागू नहीं हुआ और छतिहर मजदूर कम मजदूरी पर काम करते रहे।

बहुआ मजदूर निरक्षर थे और उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी। इनमें से अनेक को आज भी यह नहीं पता है कि कानून की निगाह में वे एक स्वतंत्र नागरिक हैं। अपनी अज्ञानता के कारण वे अपने बाजिब हक के लिए एकजुट नहीं हो सके। अक्टूबर 1975 के अध्यादेश के जरिए वे मुक्त नहीं हो सकें। यदि ऐसा होता तो वे उन महाजना और जोनदारा के खिलाफ आंदोलन संगठित करते जिन्होंने उन्हें अभी भी बहुआ बना रखा था। राजनीतिक दलान भी चुप्पी साध रखी थी क्योंकि किमाना और छतिहर मजदूरों की तुलना में जोनदारा और महाजना के साथ उनके रवादा पारस्परिक संबंध थे।

ध्यान देने की बात है कि राजस्थान तमिलनाडु और उड़ीसा में संविधान के अंतर्गत इस व्यवस्था को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था और अपने-अपने राज्यों में क्रमशः 1956, 1940 और 1920 में इसका उन्मूलन कर दिया था। फिर भी बहुआ मजदूरों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और वे अपने अधिकारों के लिए किसी तरह के दावे नहीं कर सकते थे। यदि उन्हें उचित मजदूरी मिलती तो वे शायद इतना कष्ट नहीं लेते जिससे उन्हें बहुआ बनना पड़ा। चूंकि वे अंध थे, इसलिए यह नहीं समझ सके कि अदायगी किमती नान के बावजूद महाजन के खाने में कस उनके कष्ट बढ़ता रहा।

बैकटस्वामी की ही मिमाल ले जिसमें 25 प्रतिशत व्याज पर दायद के लिए 270 रुपये काज लिया था। इससे छवक में वह 730 दिन तक काम करने के लिए राजी हुआ था। इस ठेके की अवधि के अंत के समय उस पर 405 रुपये चढ़ चुके थे। यदि उसे 450 रुपये प्रतिदिन की दर में यूननतम मजदूरी मिली होती तो उसके हिस्से में 3,285 रुपये होते। अपना ऋण चुकता करने के बाद भी उसके पास 2,880 रुपये होते। कहने की जरूरत नहीं कि उस कुछ भी नहीं मिला। मुक्त कराया गया बहुआ मजदूरों के पुनर्वास के बारे में सरकारी स्तर पर धुआंधार प्रचार किया गया। इन मिलमिने में कुछ राज्यों की भूमिका का उल्लेख किया जाना चाहिए।

आन्ध्र के अनुसार आंध्र प्रदेश में सितम्बर 1976 तक 926 बहुआ मजदूरों का पता लगाया गया था। इनमें से 698 का फिर्त में बसान का दावा किया गया। सरकार ने कलेक्टर तथा हरिजना एवं पिछड़ी जातियों के निदेशकों का निर्देश दिया कि वे मुक्त कराया गये बहुआ मजदूरों को खेती-बाड़ी और आवास के लिए जमीन की व्यवस्था करें। जमीन का टीका करने तथा भेती-योग्य

बनाने के लिए कम व्याज पर ऋण दिये जाने की अपेक्षा की जाती थी। राजस्थान में मुक्त कराये गये 1,328 बघुआ मजदूरों में से प्रत्येक का 500 रुपये का भुगतान किया गया। कुछ को तो काम दिये जाने की भी बात बही गयी। बिहार में 581 बघुआ मजदूरों को स्वतंत्र किया गया और 376 को धान, धान के बीज तथा उर्वरक प्रदान किया गया।

तमिलनाडु सरकार ने तहसीलदारों की नियुक्ति की ताकि अध्यादेश को कारगर बनाने की गारंटी रहे। जिन पनियाखा को स्वतंत्र किया गया उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों की विकास योजनाओं में लगा दिया गया। छोटे किसानों को राष्ट्रीय कृषि बैंक की मदद से बहायन पहाड़ी क्षेत्र में छोटे किसानों के विकास से संबंधित कार्यों में लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 31,000 बघुआ मजदूरों का पता लगाया गया और इनमें से 19,177 को मुक्त कराया गया। 1976 में सितम्बर माह तक यह योजना बनायी जा रही थी कि 16,000 मुक्त मजदूरों को फिर से बसाया जाये।

अनेक राज्य सरकारों ने बघुआ मजदूरों के अस्तित्व से ही इकार कर दिया और कहा कि अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। जिन्होंने बघुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें फिर से बसाने की दिशा में सक्रियता दिखायी थी, वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह की योजनाएँ और कार्यक्रम वे बना रहे थे उससे पता चलता था कि न तो वे वाई सुनियोजित योजना ही बना रहे थे और न ऐसा करने की उनकी इच्छा ही थी। कोई अनुभव हीन व्यक्ति भी यह जासानी से समझ सकता था कि पुनर्वास के लिए आवश्यक चीजें हैं—खेती-योग्य जमीन, जातन के लिए मवेशी, खेती के उपकरण, बीज, उर्वरक और सिंचाई व्यवस्था। फसल तैयार होने तक खाने पीने के लिए पास में पसा होना भी जरूरी था।

सिंचाई यह थी कि इस तरह की महामता नहीं दी गयी और पुनर्वास का काम शून्य ही रहा। इसका नतीजा भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिन्हें जमीन मिली भी, उन्होंने उसे महाजन को वापस लौटा दी और फिर अपने बंधों पर गुलामी का जुआ लाद लिया। जिन्हें हल बल दिया गया उन्होंने अपना पट भरा के लिए हल बल बेच दिया और एक बार फिर वे बघुआ मजदूर बन गये। जिन्हें नकद राशि मिली थी, उन्होंने उसे खर्च कर दिया और किसी का गुलाम बनकर वे फिर सेना में काम करने लगे। देश भर में यही स्थिति देखने को मिली। अध्यादेश के बाद बघुआ मजदूरों की वतार में 52.6 प्रतिशत एस.एल.एम. लोग आ गये थे जो हाल में बघुआ बन गये।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच भी एक सड़ाई है। दरजमल इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बघुआ मजदूर महज बेजान

जाकडे नहीं है बल्कि वे भी हाड भास के आदमी हैं जिन्हें जोतदारों और महाजना का शोषण बरदाश्त करना पड़ता है। राष्ट्रीय श्रम सस्थान के अनुसार वधुआ मजदूरों की संख्या 23 लाख थी। राज्य सरकारों ने इससे इकार किया और इस संख्या को 1 लाख 20 हजार बताया। केन्द्र सरकार का दावा है कि यह संख्या 2 लाख से कुछ अधिक है। इसने राज्य सरकारों से सर्वेक्षण करने के लिए कहा। राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच पन्नाचार जारी है। कुछ राज्यों ने तो केन्द्र सरकार को जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी।

पुनर्वास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। केन्द्र में कुल खर्च का आधा हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की है। छठी योजना में इस काम के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फिर भी कुछ नहीं किया गया। जब तक सरकारी व्यवस्था और भूमि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होता, निहित स्वार्थों का ही बोलबाला रहेगा।

हर तरह विचार विमर्श और तरह-तरह की योजनाओं के बावजूद 10 प्रतिशत भी उपलब्ध किये जाने में शक है। केन्द्र के नक़्क़ादों को साबित किया जा सकता है। श्रीमती गांधी ने इस मामले को अपनी 20-सूची योजना में शामिल किया और इस सिलसिले में अध्यादेश जारी किया गया। लेकिन सचार्ई यह है कि कुछ भी नहीं बदला। सरकार वधुआ मजदूरों का पता नहीं लगा सकी और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा पेश किये गये आंकड़ों का भी इमन में पता नहीं दी। पुनर्वास का काम खटाई में पड़ा रहा और वधुआ मजदूरों का शोषण जारी रहा।

सही तसवीर पाने के लिए जब सर्वेक्षण शुरू हुआ तब केवल 10 राज्यों में वधुआ मजदूरों के अस्तित्व को स्वीकार किया। जिन राज्यों में वधुआ मजदूरों के अस्तित्व से इकार करके पहले से चली आ रही व्यवस्था की हो रक्खी की। क्या जिन राज्यों में इनकी मौजूदगी को स्वीकार किया, वे मचमुच इस प्रथा को समाप्त करना चाहते थे? ऐसा करने का मतलब सामंती प्रभुओं को कमजोर बनाना होता जो सरकार की रीढ़ हैं। इन राज्यों में केवल राजनीतिक यात्रीगरी लिखायी। आखिर किस तरह गुजरात में केवल 42 और उड़ीसा में महज 311 वधुआ मजदूरों के होन की बात कही गयी? आखिर कैसे दस मृत्युवादी राज्यों में इनकी संख्या केवल 1 लाख 20 हजार बतायी गयी? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारें किस तरह यह दावा कर सकी कि उनके राज्यों में न केवल वधुआ मजदूरों का पता लगा लिया गया है और उन्हें मुक्त करा दिया गया है बल्कि उन्हें फिर से बसा भी दिया गया है? फिर भी इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चार सदस्यों ने उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया और बताया कि वधुआ मजदूरों के पता लगाने का काम बहुत बठिन है क्योंकि वे मराजनों और



अपने मासिक वेतन इतना कम होता है कि कुछ भी बचत में धन यदि संचयित मदद करती तो यह काम बंठित नहीं होता।

उस मसल पर वेशुमार धन खर्च किया जा चुका है, हालांकि की हालत पहले जैसी ही बनी रहो। 1978-79 में कर्नाटक में 378 वधुआ मजदूरों के पुनर्वासि के लिए 5.07 लाख रुपये खर्च 388 मजदूरों के पुनर्वासि पर 2.69 लाख रुपये मध्य प्रदेश में पुनर्वासि पर 2.37 लाख रुपये, उड़ीसा में 308 लोगों के पुनर्वासि रुपये राजस्थान में 700 मजदूरों के पुनर्वासि पर 14 लाख रुपये में 495 मजदूरों के पुनर्वासि पर 10 लाख रुपये खर्च किए।

तमिलनाडु सरकार के अनुसार वधुआ मजदूरों की संख्या 1977-78 में 517 मजदूरों को फिर से बसाया गया। 19 द्वारा दसों काम के लिए दिये गए 5.32 लाख रुपये यह खर्च जात्र प्रदेश में 1978-79 में मुक्त कराये गए 2,920 वधुआ मजदूरों पर 18.01 लाख रुपये खर्च किये।

1978-79 में मुक्त कराये गए वधुआ मजदूरों के पुनर्वासि 97.64 लाख रुपये प्रदान किये। बताया जाता है कि 5,420 मजदूरों पर राज्यों ने इसमें से 55.92 लाख रुपये खर्च किये।

1979-80 में 53.62 लाख रुपये दिये गये थे। इस धन को के पुनर्वासि में व्यय किया जाना था। चाल वष के लिए 3 व प्रावधान है। यह पसा बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ दूसरे किसी राज्य में वाइ याजना नहीं पेश की।

यदि काम का प्रगति इसी रफ्तार में होती रही तो पुनर्वासि चला जायेगा। छठी योजना में 25 करोड़ रुपये का जो प्रावधान इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

यह मान लेना बंठित है कि महज इस धन के खर्च किये जा करायें गये मजदूरों को समाज में उचित स्थान प्राप्त हो जायेगा। देख लिया है कि पुनर्वासि की याजना एक दाग है। हम यह नहीं भावी याजनाएँ इससे कुछ बेहतर होंगी।

जब तक वधुआ मजदूरों में चेतना नहीं पैदा होती और वे खड़े नहीं हो जाते, तो भी उन्हें आजाद जिम्मेदार बितान का हक नहीं

हम प्रारंभ के अध्यायों में देखा कि किस तरह बघुआ मजदूर प्रणाली की शुरुआत हुई और खती-बाड़ी में लग लोग का बघुआ मजदूर बनना पड़ा। जानकारों और महाजनों द्वारा दाय जा रहे जुल्म भी आज भी जारी हैं।

1947 के बाद में इन मजदूरों की दुर्दशा पर जनक थार विचार विमर्श हुआ और पर्याप्त घड़ियाली आँसू बहाय गए। फिर भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया। यह हालात तब तक ऐसी ही बनी रहेंगी जब तक भूमि पावनकारी में आमूल परिवर्तन नहीं आता। फिलहाल 20 प्रतिशत जमीन के पास 80 प्रतिशत जमीन है और 80 प्रतिशत जमीन के पास 20 प्रतिशत जमीन। राजनीतिक दलों में जमीन का वास्तविक विभाजन का दम का झूठा नारा उठाया है और इस प्रकार मसूचे समान जो एक राजनीतिक खेल बना दिया गया। दरजमल इस प्रकार खिलाफ आम आन्दोलन छेड़ने की उद्देश्य है और कोई भी राजनीतिक दल—चाहे उसका रंग लाल पीला, नीला कुछ भी हो—नतुन तरीके से मनाना, बदाबि मभी स्वयं के राजनीतिक नेता गैर-मेतिहर जमीनदार परिवारों के हैं। इसलिए इन मतलों के धन हैं। उनका भी स्वाभाव है। यह जाना नहीं की जा सकती कि ये उभरी व्यक्तियों का मजदूरों के जा उनका पता है। इसीलिए बघुआ मजदूरों के अतिरिक्त मजदूरों के वरत हैं और हम प्रचार करना निश्चित स्वाभाव बनाय रखते हैं। जो राज्य इन गरीबों के हान की बात मानने भी है ये मजदूरों का मुक्त कराने और उन्हें बर्मान की लिंगा में कुछ भी नहीं करने।

इस प्रकार आज भी वही हालत बनी हुई है जो 1947 में थी।

इस समय का श्रीमती गांधी की 20-सूत्री योजना में शामिल किया गया और एक अध्यात्म जारी किया गया। राष्ट्रीय धर्म मन्थन के तहत एक मन्थन चलाया है कि हम कोई लाभ नहीं लेंगे। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जातियों के आनुवंशिक जातिवादी के 1970 में जन्म के 1 05 180 बघुआ मजदूरों का पता लगाना गया है 1 04,789 का मुकाबला किया है और 31 844 का रिक्त

से बसाया गया है। स्थान के स्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आ वधुआ मजदूर हैं। कुल खेतिहर

1939 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सत्रिय सदस्य था। अंतर्राष्ट्रीय कि वे जल्दी से जल्दी अपना यह को समाप्त करें। कुछ सशोधना के सामान्य पेश किया गया और वे यह प्रयास आज भी कर रहे हैं।

1947 के बाद हर तरह की के अंतर्गत नैतिकानुनी घोषित की 374 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का ऐसा दंड है जिसके लिए कद या सविधान और दंड संहिता की मद नेतृत्व में अनुसूचित जातियों और को समाप्त किया जाना की दलील दे लेकिन हमने शुरू के अध्यायो में यह में केन्द्र किस तरह विकल रहा।

सरकारी जाँच के अनुसार 1 चुका है और 31 844 का फिर स डाल है। हमने बताया है कि वे लागू वधुआ बन गए। जिन्हें मुक्त कराया बनी थी, उनकी हालत अत्यंत दयनी मदद मिली थी, उन्होंने कुछ समय तक वधुआ मजदूर बन गये। जिनके लिए होन के पहले ही दिन में भयावह स्थिति होना पड़ा।

उन्हें जातिद्वारा और महाजना के और महाजनों ने तय कर लिया था कि काम नहीं देंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि जो मकई और धान दिया गया चलाया। नकद के रूप में प्राप्त धन पर

जिनको अभी बसाया जाना था वम यही विक्षेप था कि या तो वे घर

अनुसार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश त्रिहार राज प्रान्त तमिलनाडु और कर्नाटक में 23 लाख मजदूरों का 6 प्रतिशत अनुपात है।

मगधन की पहली बैठक हुई। भारत इसका एक प्रथम मगधन न ममा मन्त्रालय तथा म अनुराज विद्या म जयपुरी और अजिनाय मजदूरी के मनी रखा गया यह ममरा नमारा रक्षाय विज्ञानमदन तथा राज्या म रानून पारित हुए। तद्विनि

जयन्त मजदूरों का सविज्ञान की द्वारा 23 (1) दिया गया। भारतीय मन्त्रालय की धारा मजदूरों के लिए जार जयदस्ती करना एक अनुमाना जयवा नाना रज न्या जा सकते हैं।

भी उकार मारित हुई। यू० एन० स्तर के मानजानिया के जायाग न वधुआ मजदूरी प्रया । जतन एक अध्याय 1975 में जारी हुआ तथा है कि इस अध्याय की जमन में सान

04 789 वधुआ मजदूरों का मुक्त कराया जा गया था चुका है। य मारे तब महज एक जिन्हें मुक्त कराया गया था क्या तुलना गया था जार जिनके लिए पुनर्वास योजना थी। जिन्हें मुक्त कराया जान के तब याडा के अपना काम चनाया पर चली ही व फिर पुनर्वास योजना प्रनाया गयी थी म मुक्त त म थे। जतन दाना का दुभाग्य का शिरार

यहां कोई काम नहीं मिला क्योंकि जोतारों के मुक्त रंगय गये मजदूरों को अपना काम कि मुक्त कराया गये मजदूरों को वान के रा उमी का खाकर उत्तान अपना काम न ही मच हा चना था।

उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास नौकर के रूप में मन्त्र प्रदान या मन्त्रमन

करने के काम में या जगला में दैनिक मजदूरी पर काम करें। इस तरह के काम तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं और न सबको दिये जा सकते हैं। भूख और गरीबी न एक बार फिर उन्हें बधुआ बनने के लिए मजबूर कर दिया।

मजदूरों की ठेकेदारी करने वालों को इसी मौके का इंतजार था। जनता सरकार के शासन काल में ठेकेदारों ने बिहार और उत्तर प्रदेश में मुक्त कराये गये इन मजदूरों को गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में काम करने के लिए भेज दिया।

1979 के अकाल में इस प्रक्रिया में तेजी ला दी। भूख और गरीबी का अब ज्यादा जोर था। सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत नहीं मिली जो अस्थायी तौर पर इन लोगों को मदद पहुँचा सकती। इसलिए उनके दिल के दिल अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में भेज दिये गये जहाँ उद्योगों तथा बड़े उद्ये कृषि फार्मा में काम करने के लिए समूचे मजदूरों की जरूरत थी। कौटा से दूसरे राज्य में स्थानांतरित एक मजदूर ने बताया कि किस प्रकार असुशल मजदूरों को महाराष्ट्र भेजा गया। ये सभी मुक्त कराये गये बधुआ मजदूर थे। पंजाब के धनी किसानों ने भी ठेकेदारों के जरिए कई हजार ऐसे मजदूरों का आयात किया जिन्हें बधुआ जिंदगी से मुक्त कराया गया था।

महाराष्ट्र और पंजाब में इन मजदूरों का जो अत्याचार झेलना पड़ता है उसकी जानकारी किसी को भी उत्तर प्रदेश में हा सकती है। ठेकेदारों ने अच्छी तलाक़ाह, अच्छा भोजन और आरामदेह मकान का लालच देकर इन मजदूरों को महाराष्ट्र पहुँचा दिया। लेकिन सच यह भी कि उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते थे जिससे वे दिन में एक बार भी अपना पेट भर सकें और रहने के लिए उनके पास काढ़ जगह भी नहीं थी।

जो पंजाब गये उनकी हालत भी बदतर थी। उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। काम के घंटे बहुत ज्यादा थे। उनकी हालत पहले जमी ही थी—बेम, अथ मालिक फल गये थे।

इसका सारा दाप पुनर्वास के काम में सरकार की उपेक्षा का दिया जाना चाहिए। बधुआ जिंदगी से आजाद इन मजदूरों ने अपने काँ जोर भी बुरी हालत में पाया, क्योंकि सरकार ने अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया था जो इनका मुक्त कराय जाने के बाद उसे करना चाहिए था।

मुक्त कराये गये मजदूर महाजनो और जोतदारों के पास नहीं जा सक, क्योंकि कानूनी काम उठाने के कारण इनसे उनके मजदूर बटु हो चुके थे। साथ ही सरकार ने बँका तथा इस तरह की समस्याओं का गठन नहीं किया था जिसमें ग्रहण के रूप में मजदूरों का कुछ सहायता मिल सके।

परअन्त ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे सरकार याव के महाजनो के स्थान

तरह के कानूनों से किसको ज्यादा सुखी होती ?

अध्यादेश में वर्णित रूपों के अनिश्चित और भी कई तरह के बधुजा मजदूर हैं। वे कानून के दायरे में नहीं आते। उनके राज्यों में इनके अस्तित्व से ही इकार करके इस प्रथा का बर्नाय रखने में मदद पहुँचायी है। ता भी राष्ट्रीय धर्म संस्थान ने साबित कर दिया है कि बधुजा मजदूरों का अस्तित्व है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

मुक्त कराये गये बधुजा मजदूरों का दी गयी जमीन खेती याच नहीं थी और फसल तयार होने तक उनमें भरण पोषण का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। कुछ का हल मिला तो बल नहीं और कुछ को बल मिला तो हल नहीं। कुछ को खाल बल और हल मिला ता जमीन नदारद। गवर्नर की भी यह पुनर्वास योजना।

यह एक सुनियोजित तमाशा था। इस तमाशे में आकर्षित न होने वाला म दिना दिन बढ़ती तादाद में मुक्त कराये जा रहे थे बधुजा मजदूर वे जिनके कंधे पर एक नयी तरह की गुलामी का जुआ रखा जा रहा था।

परिशिष्ट  
बधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधिनियम  
1976

(1976 का अधिनियम सख्याक 19)

(9 फरवरी, 1976)

जनता के दुबल वर्गों के जाधिक और शारीरिक शोषण का निवारण करन के उद्देश्य से बधित श्रम-पद्धति के उत्सादन का और उससे संबधित या उसके आनुपगिक विषया का उपबध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्ठीसवे वष म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हा—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1 (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 है।
- (2) इसका विस्तार संपूण भारत पर है।
- (3) यह 1975 के अक्तूबर के पच्चीसवें दिन को प्रवक्त हुआ समझा जायगा।

## परिभाषाएँ

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संभव हो अन्यथा अपेक्षित नहीं है—

- (क) 'अग्रिम' से, चाहे नकद या वस्तु रूप में अथवा भागत नकद या भागत वस्तु रूप में ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसमें इसका पश्चात ऋणी कहा है) दिया जाता है
- (ख) 'करार' से ऋणी और ननशर के बीच करार (चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक अथवा भागत लिखित रूप में हो और भागत मौखिक) अभिप्रेत है और इससे अन्तर्गत काइ एसा करार भी है जिसमें ऐसी बलात् श्रम का उपबन्ध किया गया है जिसके अस्तित्व की उपधारणा संबंधित परिदृश्य में प्रचलित किसी सामाजिक रूढ़ि के अधीन की जाती है।

**स्पष्टीकरण**—ऋणी और लेनदार के बीच करार के अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक रूढ़ि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात् श्रम के संबंध में की जाती है, अर्थात्

आदियामार वारामासिमा बसन्तिया बेधू, मगेला, चेस्मार, गारुगल्लू हाली, हारी हरबइ, हालया, जाना, जीता, कामिया, खुडिन मुडित, कुथिया लखरा मुषी, मेट, मुनीश पद्धति नित मजूर पलरू पडियाल पनाईलाल मागडी, सजी सजावत सबक सेवकिया, सेरी, उट्टी

(ग) मातप्रधान समाज के व्यक्ति के संबंध में 'पूर्वपुरुष या वंशज' में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस समाज में प्रवृत्त उत्तराधिकार की विधि के अनुसार एसा अभिव्यक्ति के समरूप है,

(घ) 'वधित ऋण' से ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो वधित श्रम-पद्धति के अधीन या उससे अनुसरण में वधित श्रमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह एसा अभिप्राप्त किया गया है,

(ङ) 'वधित श्रम' से वधित श्रम पद्धति के अधीन किया गया काइ श्रम या की गयी काइ मया अभिप्रेत है

(च) 'वधित श्रमिक' से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो वधित ऋण करता है या जिसने उपात किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने वह उपगत किया है

(छ) 'वधित श्रम पद्धति' से बलात् श्रम या भागत बलात् श्रम की उपधारणा अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार में इन जायज का करार होता है या जिसमें ऐसा करार किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा

परिशिष्ट  
वधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधिनियम  
1976

(1976 का अधिनियम सख्याक 19)

(9 फरवरी, 1976)

जनता के दुबल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से वधित श्रम-पद्धति के उत्सादन का और उससे संबंधित या उसके आनुपंगिक विषयो का उपबध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवे वष म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप म यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारम्भ

सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1 (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम वधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह 1975 के नवम्बर के पच्चीसवे दिन का प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।



## परिभाषाएँ

2 इस अधिनियम म, जब तक कि सदन स अथवा अपेक्षित न हो—

- (क) 'अग्रिम' स, चाहे नकद या वस्तु रूप म जथवा भागत नकद या भागत वस्तु रूप म, ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसम इसक पश्चान ऋणी कहा है) दिया जाना है,
- (ख) 'करार' म ऋणी और लेनदार क बीच करार (चाहे वह लिखित रूप म हो या मौखिक अथवा भागत लिखित रूप म हो और भागत मौखिक) अभिप्रेत है और इसक अन्तगत कोई ऐसा करार भी है जिसम एस बलात धर्म का उपग्रह किया गया है जिसक अस्तित्व की उपधारणा संबंधित परिसेन म प्रचलित किसी सामाजिक हडि क अधीन की जाती है।

**स्पष्टीकरण**—ऋणी और लेनदार क बीच करार क अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक हडि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात धर्म के संबंध म की जाती है, अर्थात्

आदियामार वारामासिया बसहया बंधू भगेल, चेरुमार गारगल्लू हाली, हारी हरबई हालया, जाना जीता कामिया खुडित मुडित कुपिमा लेखेरी, मुझी भेट, मुनीश पद्धति नित मजूर पलेर पडियाल पनाईलाल, मागडी, मजी, मजावन, सेवक सबकिया मेरी वेट्टी,

(ग) मातप्रधान समाज क व्यक्ति क संबंध म 'पूवपुरुष या वंशज' स वह व्यक्ति अभिप्रेत है जा उस समाज म प्रवक्त उत्तराधिकार की धिक् के अनुसार एसी अभिव्यक्ति के समरूप हे

(घ) 'वधिन ऋण' स ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जा वधित धर्म-पद्धति के अधीन या उसक अनुसरण म वधित धर्मिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाना ह या जिसक वार म यह उपधारणा की जाती ह कि वह एस अभिप्राप्त किया गया है

(ङ) 'वधित धर्म स वधित धर्म-पद्धति क अधीन किया गया कोई धर्म या की गयी कोई सजा अभिप्रेत है

(च) 'वधिन धर्मिक' स ऐसा धर्मिक अभिप्रेत है जा वधित ऋण उपगत करता ह या जिसन उपगत किया ह या जिसक वार म यह उपधारणा की जाती है कि उसन वह उपगत किया है

(छ) 'वधित धर्म पद्धति से बलात धर्म या भागत बलात धर्म की पद्धति अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लदार स इस आशय का करार करता है या जिसन एस करार किया है या जिसके वार म यह उपधारणा की

जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि—

(1) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वपुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा अभिप्राप्त उधार के प्रतिफल में (चाहे ऐसा अग्रिम किसी दस्तावेज द्वारा साक्षित है या नहीं) और ऐसे अग्रिम पर देय ब्याज के, यदि कोई हो, प्रतिफल में अथवा

(2) किसी रुद्धिगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में, अथवा

(3) किसी ऐसी बाध्यता के अनुसरण में जो उत्तराधिकार द्वारा उसको यागत हुई है अथवा

(4) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वपुरुषों या वंशजों में से किसी के द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए, अथवा

(5) किसी विशेष जाति या समुदाय में उसके जन्म लेने के कारण, वह—

(i) स्वयं या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के माध्यम से या अपने पर जाश्रित किसी व्यक्ति के माध्यम से लेनदार का, या देनदार के फायदे के लिए धन या सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो मजदूरी के बिना या नाममात्र की मजदूरी पर करेगा, अथवा

(ii) अपने नियोजन या अपनी जीविका के अथवा साधना की स्वतन्त्रता विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खा देगा अथवा

(iii) भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवधि संचरण का अपना अधिकार खा देगा अथवा

(iv) अपनी किसी सम्पत्ति या अपने धन का या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या अपने पर जाश्रित किसी व्यक्ति के धन के उत्पाद को विनियोजित करेगा या उसे बाजार मूल्य पर विनियमन करने का अपना अधिकार खा देगा,

और इसके अतिरिक्त बलात् धन या भागत बलात् धन की वह पद्धति भी है जिसके अधीन ऋणी प्रतिभूति लेनदार के साथ इस आशय का करार करता है या जिससे ऐसा करार किया है या जिसके बार में यह उप-धारणा की जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि ऋणी द्वारा ऋण का प्रतिसदाय करने में असफल रहने की दशा में वह ऋणी को ओर से वधित धन करेगा

(ज) किसी व्यक्ति के संबंध में कुटुम्ब के अतिरिक्त उस व्यक्ति का पूर्वपुरुष और वंशज भी है,

(य) किसी श्रम के संवध में 'नाममात्र' की मजदूरी से वह मजदूरी अभिप्रेत है जो—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के संवध में सरकार द्वारा नियत निम्नतम मजदूरी से कम है और

(ख) जहाँ किसी प्रकार के श्रम के संवध में ऐसी यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गयी है वहाँ, उसी परिश्रम में काम करने वाले श्रमिकों को उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के लिए प्रसामान्यतः सदातः मजदूरी से कम है

(ज) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाय गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

### अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

3 इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम में मिलने वाली अधिनियमितियाँ या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमितिके आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगी।

## अध्याय 2

### बधित श्रम-पद्धति का उत्सादन

4 (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर बधित श्रम-पद्धति का उत्सादन हुआ जायगा और उस प्रारम्भ पर प्रत्येक बधित श्रमिक, उचित श्रम करने की किसी भी बाध्यता से मुक्त और उन्माचित हुआ जायगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति—

(क) बधित श्रम-पद्धति के अधीन या उसके अनुसरण में कोई श्रम नहीं देगा, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति का कोई बधित श्रम या किसी अन्य प्रकार का बलात्कृत श्रम करने के लिए विवश नहीं करेगा।

क्रूरार, रुद्धि, आदि का पूरा होना

5 इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसी रुद्धि या परम्परा या कोई मजिना, क्रूरार या अन्य लिखित (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उपर

पश्चात की गयी हो या निष्पादित की गयी हो) जिसके आधार पर किसी व्यक्ति से या उस व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य से या उस व्यक्ति के आश्रित से वधित श्रमिक के रूप में कोई काम करने या सेवा करने की अपेक्षा की जाती है, शून्य और अप्रबतनशील होगी।

### अध्याय 3

#### वधित ऋण का प्रतिमदाय करने के दायित्व की समाप्ति

6 (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी वधित ऋण का प्रतिमदाय करने या ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व चुकता न किये गये किसी वधित ऋण के किसी भाग का प्रतिमदाय करने के लिए वधित श्रमिक का प्रत्येक दायित्व समाप्त हुआ समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी वधित ऋण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए कोई ऋण या अन्य कायबाही किसी सिविल यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी से समझ नहीं होगी।

(3) वधित ऋण की वसूली के लिए प्रत्येक डिमैन्ड या आदेश, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया हो और ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पूणतया चुकता न किया गया हो, एम प्रारम्भ पर पूणतया चुकता किया गया समझा जायेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी वधित ऋण की वसूली के लिए की गयी प्रत्येक कुर्की एम प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगी और जहाँ ऐसी कुर्की के अनुमरण में वधित श्रमिक की कोई जगम सम्पत्ति अभिगृहीत हो गयी थी और उनकी अभिरक्षा से हटा ली गयी थी और उससे त्रिभुज के लम्बित रहने के कारण किसी यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी थी वहाँ ऐसी जगम सम्पत्ति का कब्जा एम प्रारम्भ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, वधित श्रमिक को वापस कर दिया जायेगा।

(5) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व वधित श्रमिक की या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या अन्य आश्रित की किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी वधित ऋण की वसूली के लिए किसी नेनदार द्वारा उलपूवक ले लिया गया था वहाँ ऐसी सम्पत्ति का कब्जा एम प्रारम्भ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उस व्यक्ति का वापस कर दिया जायेगा जिससे वह अभिगृहीत की गयी थी।

(6) यदि उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा एम अधिनियम के प्रारम्भ से तीस मिनट के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो वधित व्यक्ति उसी सम्पत्ति का कब्जा को वापसी के लिए विहित प्राधिकारी

को ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, आवेदन कर सकेगा और विहित प्राधिकारी लेनदार का सुनवाई का उचित अंतर देने के पश्चात्, लेनदार को यह निर्देश दे सकेगा कि वह आवेदक को सम्बन्धित सम्पत्ति का कब्जा ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वापस कर दे।

(7) विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (6) के अधीन किया गया आदेश निम्नलिखित यायालय द्वारा किया गया आदेश समाना जायगा और धन सम्बन्धी निम्नतम अधिकारिता वाले एम यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर लेनदार मजदूरों में निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाष के लिए स्वयं नाम करता है।

(8) शकाओं को दूर करने लिए यह घोषित किया जाता है कि जहाँ कुछ की गयी किसी सम्पत्ति का विषय किसी बधित मजदूर का बसूती के लिए किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया या वहाँ ऐसे विषय पर इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रभाव नहीं पड़ता।

पर तु बधित श्रमिक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राविष्ट अभिकर्ता ऐसे प्रारम्भ से पाँच वर्ष के भीतर किसी समय एम विषय का अपास्त करने के लिए आवेदन तय कर सकेगा जब वह उस विषय की उद्घापणा में विनिर्दिष्ट उस रकम को जिसकी बसूती के लिए विषय का आदेश किया गया था उसमें से उतनी रकम और अतः कालीन लाभ जो विषय की ऐसी उद्घापणा की तारीख से डिक्रीद्वारा प्राप्त किया गया हो, कम करके डिक्रीदार का सदातः करने के लिए यायालय में जमा कर दे।

(9) जहाँ बधित धर्म पद्धति के अधीन किसी वाध्यता के प्रारम्भ के लिए कोई वाद या कायवाही जिसमें अतः बधित श्रमिक का दिया गया किसी उधार का बसूती के लिए वाद या कायवाही भी है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर नम्बित हो वहाँ ऐसा वाद या अन्य कायवाही ऐसे प्रारम्भ पर चारित्र्य हो जायगी।

(10) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रत्येक बधित श्रमिक का विषय के पूर्व या उसके पश्चात् निम्नलिखित कारागार में निरुद्ध किया गया है, एम निराश्रित तत्काल छोड़ दिया जायगा।

**बधित श्रमिक की सम्पत्ति का बधक आदि से मुक्त किया जाता**

7 (1) बधित श्रमिक में विहित सभी सम्पत्ति या इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी बधित मजदूर के सम्बन्ध में किसी बधक, भार धारणा अधिकार या अन्य विल्लामा के अधीन थी जहाँ तक उसका सम्बन्ध बधित मजदूर में है वहाँ तक इस बधक भार धारणाधिकार या अन्य विल्लामा से मुक्त और उमाचित हो जायगी और जहाँ ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक

पूर्व वधकदार के कब्जे में थी या भार, धारणाधिकार या विलग्न क धारक के कब्जे में थी वहाँ ऐसी सम्पत्ति का कब्जा (उस दशा के सिवाय जब वह किसी अन्य भार के अधीन थी) एस प्रारम्भ पर वधित श्रमिक को वापस कर दिया जायगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा वधित श्रमिक को वापस करने में कोई विलम्ब किया जाता है तो ऐसा श्रमिक एस प्रारम्भ की तारीख से ही वधनार में या भार धारणाधिकार या विलग्न क धारक से ऐम अत कालीन लाभ वसूल करने का हक्दार होगा जो धन-सम्बन्धी निम्नतम अधिकारिता वाले एस सिविल "यायालय द्वारा अवधारित किय जायें जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

मुक्त किये गये वधित श्रमिक का वासस्थान, जादि से वेदखल न किया जाना

8 (1) एस किसी व्यक्ति का जो वधित श्रम करने के किमी दायित्व से इस अधिनियम के अधीन मुक्त और उन्मोचित किया गया है, किसी वासस्थान या अन्य निवास परिसर से जिसका अधिभाग वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व वधित श्रम के प्रतिफल के भागरूप कर रहा था, बदखल नहीं किया जायगा।

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति लेनदार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वासस्थान या अन्य निवास परिसर से बदखल किया जाता है तो उस उपखंड का, जिसमें ऐसा वासस्थान या निवास-परिसर स्थित है कायपालक मजिस्ट्रेट वधित श्रमिक को ऐसे वासस्थान या अन्य निवास परिसर का कब्जा, यथासाध्य शीघ्रता से वापस करेगा।

समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा सदाय का स्वीकार न किया जाना

9 (1) कोई लेनदार किसी एस वधित ऋण के लिए जो इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर समाप्त हो गया है या समाप्त हुआ समझा गया है या पूर्णतया चुकता कर दिया गया समझा गया है, कोई सदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास में जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला यायालय उस व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी शास्तियों के अतिरिक्त जो उस उपधारा के अधीन अधिरोपित की जायें, यायालय में वह रकम जो उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में स्वीकार की जाती है ऐसी अवधि के भीतर जा जादेश में निर्निर्दिष्ट की जाय वधित श्रमिक को वापस किय जान के लिए जमा करे।

## अध्याय 4

### कार्यान्वयन प्राधिकार

वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबधा को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किये जायें

10 राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तिया प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐस कतव्य अधिरोपित कर सकेगी जा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि इस अधिनियम क उपबधा समुचित रूप से कार्यान्वित किय जा रहे ह और जिला मजिस्ट्रेट अपना ऐसा अधीनस्थ अधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किही शक्तिया का प्रयोग और इस प्रकार अधिरोपित सभी या किही कतव्या का पालन करेगा और उन स्थानीय सीमाजा को विनिर्दिष्ट करेगा जिनक भीतर ऐसी शक्तिया का प्रयोग या एसे कतव्या का पालन इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जायगा ।

अथ सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कतव्य

11 धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उस धारा क अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी वधित श्रमिक क आर्थिक हिता को सुनिश्चित करके आर सहायण देकर ऐसे वधित श्रमिक के कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा जिसस कि उस वधित श्रमिक का कोई और वधित श्रम उन के लिए सविदा करने का बाद अमर या हेतुक न हो ।

जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का कतव्य

12 प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट का और धारा 10 क अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी का यह कतव्य होगा कि वह यह जाच करे कि इस अधिनियम क प्रारभ के पश्चात किसी वधित श्रम पद्धति या किसी अन्य प्रकार क बलात श्रम का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाजा क भीतर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रवतन किया जा रहा है या नहीं और यदि ऐसी जाच क परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति वधित श्रम पद्धति या बलात श्रम की किसी अन्य पद्धति का प्रवतन करत पाया जाता है तो वह तत्वात ऐसी बाधबाध करेगा जो एम बलात श्रम क प्रवतन का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक है ।

## अध्याय 5

## सतकता समितियाँ

13 (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड में उतनी सतकता समितियाँ गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतकता समिति में निम्नलिखित संस्य हाग अवति—

(क) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा

(ख) तीन व्यक्ति जो अनुमूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ के हों और जिनमें निवास कर रहे हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे,

(ग) नौ सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले में निवासी हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

(घ) जिनमें ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(ङ) जिले में वित्तीय और प्रत्यय समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायेंगा।

(3) किसी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतकता समिति में निम्नलिखित संस्य हाग अवति—

(क) उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा

(ख) तीन व्यक्ति, जो अनुमूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ के हों और उपखंड में निवास कर रहे हों, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो उपखंड में निवासी हों, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(घ) उपखंड में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

(ङ) उपखंड में वित्तीय और प्रत्यय समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने



के लिए एक व्यक्ति, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा,

(च) एक अधिकारी जो धारा 111 व अधीन विनिर्दिष्ट है और उपखंड में कार्य कर रहा है।

(4) प्रत्येक सतकता समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी और उस—

(क) जित्त व लिए गठित सतकता समिति को देना में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा,

(ख) उपखंड के लिए गठित सतकता समिति की देना में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा

ऐसी अनुसूचित सहायता दी जायेगी जो आवश्यक हो।

(5) सतकता समिति की कोई कार्यवाही सतकता समिति के गठन या कार्यवाही में किसी त्रुटि के कारण ही अवधिमान्य नहीं होगी।

सतकता समितियों के कृत्य

14 (1) प्रत्येक सतकता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इस अधीन बनाये गये नियम के उपबन्धों का समुचित रूप में विचार-परिणाम हो, किन गये प्रयत्न और की गयी कारवाहियों के द्वारा न कि जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का आदेश देना

(ख) मुक्त किय गये बधित श्रमिकों के आदिश आगे आमात्रिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना

(ग) मुक्त किय गये बधित श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्येक की व्यवस्था करने के उद्देश्य में श्रमीण परा और महत्वागी माना-प्रिया के कृत्य का समन्वय करना

(घ) उन अपराधों की समस्या पर नजर रखना जिनका प्रावधान अधिनियम के अधीन किया गया है

(ङ) यह सर्वोप करनी कि क्या कोई अपराध किया गया है जिसका मतलब इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था

(च) मुक्त किय गये बधित श्रमिकों के या उनके कुटुम्ब के आर्थिक या उस पर आर्थिक व्यक्ति के विरुद्ध सम्पत्ति किसी भी रूप में प्रभारित करना जो किसी बधित श्रमिक या किसी अन्य व्यक्ति के सम्पत्ति या उनके किसी भाग या वस्तु के लिए हो जिसका उद्देश्य

ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(2) सतकता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य का इस वाद के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किया गया बर्धित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किया गया बर्धित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयाजन के लिए प्राधिकृत अधिकर्ता समया जायगा।

### संवत्स का भार

15 जब कभी किसी बर्धित श्रमिक या सतकता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह बर्धित ऋण है तो ऐसे ऋण के बर्धित ऋण न हान के संवत्स का भार लननार पर हागा।

## अध्याय 6

### अपराज और विचारण के लिए प्रन्या

#### बर्धित श्रम के प्रवतन के लिए दड

16 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई बर्धित श्रम करने के लिए विवश करगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

#### बर्धित ऋण के दिये जाने के लिए दड

17 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात कोई बर्धित ऋण देगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय हागा।

#### बर्धित श्रम-पद्धति के अधीन बर्धित श्रम कराने के लिए दड

18 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी ऐसी रूढ़ि परम्परा, सविदा, करार या अन्य लिखत का प्रवतन करेगा, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति पर आश्रित किसी व्यक्ति से अपक्षा की जाती है कि वह बर्धित श्रम पद्धति के अधीन कोई सवा करे तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और यदि जुर्माना

वसूल किया जाता है तो उसमें से वधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन उससे वधित श्रम कराया गया था पांच रुपये की दर से सदाय किया जायगा।

वधित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दंड

19 ऐसा कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा हो जाती है कि वह किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी वधित श्रमिक को वापस करे इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा करने में लोप करेगा या असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती या जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और यदि जुमाना वसूल किया जाता है तो उसमें से वधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान सम्पत्ति का कब्जा उसे वापस नहीं किया गया था पांच रुपये की दर से सदाय किया जायगा।

दुष्प्रेरण का एक अपराध होना

20 जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो या नहीं वह उसी दंड से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपवधित है जिसका दुष्प्रेरण किया गया है।  
स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'दुष्प्रेरण' का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंडमहिता (1860 का 45) में है।

अपराधों का कायपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किया जाना

21 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए कायपालक मजिस्ट्रेट का प्रथम वग यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वग यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसी शक्तियों के प्रदान किय जाने पर उस कायपालक मजिस्ट्रेट को, जिसे इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गयी हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजना के लिए यथास्थिति प्रथम वग यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वग यायिक मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।  
(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न किया जायगा।

अपराधों का सन्तान

22 इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध मनेय और जमानतीय होगा।

## कम्पनिया द्वारा अपराध

23 (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जान के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारताध्यक्ष और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही वह कम्पनी भी एक अपराध के दायी समझे जायगा और तदनुसार अपराध के विरुद्ध कार्यवाही किया जान और दंडित किया जान के भागी होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के हात टूट भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि यह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी ऐसे या के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दायी समझा जायगा और तदनुसार अपराध के विरुद्ध कार्यवाही किया जान और दंडित किया जान के भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में प्रयोजन के लिए—

(क) कम्पनी में कोई निगमित निवाम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टि का अन्य संगम भी है तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

## अध्याय 7

## प्रतीग

## सदभावपूर्णक की गयी कारवाही के लिए संरक्षण

24 इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्णक की गयी या की जान के लिए जाशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के अध्यक्ष राज्य सरकार के किसी अधिकारी के या मतवता समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।

## सिविल यायालयों की अधिकारिता का बजन

25 किसी भी सिविल यायालय का किसी ऐसे विषय के बारे में अधिकारिता नहीं होगी जिस अधिनियम का कोई उपबन्ध लागू होता है और किसी

सिविल प्रयालय द्वारा किसी ऐसी बात के बारे म काइ व्यादश नहीं लिया जायगा जाइम अधिनियम के अधीन की गयी है या की जान क लिए आवश्यक है।

नियम बनाने की शक्ति

26 (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजना को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र म अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विधिपूतया और प्रवर्गामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिशत प्रभाव डाल बिना एस नियम निम्नलिखित सभी या कि ही विषय क लिए उपबध करेगा अर्थात्—

(क) वह प्राधिकारी जिसको धारा 6 की उपधारा (4) या उपधारा (5) म निर्दिष्ट सम्पत्ति के कब्जे की वापसी के लिए उस धारा की उपधारा (6) क अनुसरण म जानदन लिया जाना है

(ख) वह समय जिसके भीतर सम्पत्ति क कब्जे की वापसी क लिए धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाना है

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाय गय किसी नियम के उपबध का न्याययन सुनिश्चित करने के लिए मतकता समितियां द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उठाये जान वान कर्म

(घ) काइ जय विषय जा विहित लिया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम क अधीन केंद्राय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम प्रभाव जान क पश्चात यथाशीघ्र सदन क प्रत्येक सदन क समक्ष जन वह सदन म हा तीस दिन की अवधि क लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सदन म अवधारणा अधिक जानुनमिक सत्रा म पूरी होसकेगी। यदि इस सदन क या पूर्वोक्त जानुनमिक सत्रा क ठीक बाद क सदन क अवमान क पूर्व दाना सदन उस नियम म कोई परिवर्तन करने क लिए सहमत हा जाये तो तत्पश्चात वह एम परिवर्तित रूप म ही प्रभावी हागा। यदि उक्त अवमान क पूर्व दोना सदन सहमत हा जाये कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जायगा। किंतु नियम के एम परिवर्तित या निष्प्रभावी हान स उसके अधीन पटन की गयी किसी बात की विधिमायता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडगा।

### निरसन और व्यावृत्ति

27 (1) वधित थम-वदति (उत्सादन) अधि  
17) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) एस निरसन व हात हुए भी यह है कि  
गयी कोई बात या कारवाई (जिसके अंतर्गत कोई  
गया कोई निर्देश या नामनिर्देशन, प्रदत्त शक्ति अधि  
अधिकारी भी है) इस अधिनियम व तत्स्थानी उपबन्ध  
जायगी।

देश, 1975 (1975 का

कत अध्यादेश के अधीन की  
काशित अधिसूचना, किया  
पित कृतव्य या विनिर्दिष्ट  
के अधीन की गयी समझी







